राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 271

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, बुधवार, 11 मार्च, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

विश्व विजेता टीम पर होगी धनवर्षा बीसीसीआइ देगा 131 करोड़ रुपये

>> 12

संपादकीय

सफलता को व्यापक स्वरूप देने का समय : सफेद गेंद क्रिकेट में शानदार सफलता को अन्य खेलों में दोहराने के लिए खेल संस्कृति के विकास की भी प्रतीक्षा है। **तरुण गुप्त** का आलेख।

सुहाने सपने दिखाते सिविल सेवक : ऐसे सिविल सेवकों की कमी नहीं, जिन्होंने समाज सेवा की बड़ी-बड़ी बातें की थीं, पर बाद में वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। **राजीव सचान** का दृष्टिकोण।

• पेज-8

विमर्श

डिजिटल लत से मुक्ति की पहल : कर्नाटक का 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय बच्चों को डिजिटल जाल से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाने का प्रयास है। **डा. जगदीप सिंह** का विश्लेषण।

चिंता बढ़ाता ऊर्जा संकट : ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की अस्तित्वगत अनिवार्यता बन गई है। **प्रो. आरके जैन** का आलेख।

• पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

मोटापे के बोझ में दबता बचपन

क्यों हो रही है कम उम्र में किडनी की समस्या

• पेज-13

जागरण विशेष

सड़क हादसों में सिर को सुरक्षित रखेगा यह हेडगियर

सोनीपत : शोधार्थी अरविंद सेठी ने ऐसा हेलमेट तैयार किया है, जो सिर व दिमाग के बीच मौजूद तरल की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली से प्रेरित है।

• पेज-14

घरों और परिवहन क्षेत्र को मिलेगी पर्याप्त मात्रा में गैस

आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू, जमाखोरी रोकने के लिए बनी निगरानी समिति

गैस आपूर्ति की नई प्राथमिकताएं तय, एलपीजी उत्पादन 10 प्रतिशत बढ़ा

कई शहरों में एलपीजी के लिए लंबी कतारें, कमर्शियल सिलेंडर की कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस आवंटन का नया ढांचा लागू किया
- उर्वरक उद्योग को 70% और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 80% गैस आपूर्ति

पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े दबाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के उपयोग की प्राथमिकताओं को फिर से तय कर दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के उत्पादन, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस (पीएनजी) की आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि घरों और परिवहन क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी न हो। इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करते हुए नया आदेश जारी किया है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी समिति बनाई गई है। देशभर के तमाम शहरों में कामर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से होटल-रेस्तरां के बंद होने का खतरा बढ़ गया है।

नए आदेश के अनुसार, गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मिलने वाली गैस का हिस्सा घटाकर उसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कुल उपलब्धता पर्याप्त है, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए घरेलू जरूरतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता देश के लगभग 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शनों तक नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

अधिकारियों के अनुसार उपलब्ध एलएनजी का इस्तेमाल सबसे पहले एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद उर्वरक उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कम से कम 70 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

एलपीजी उत्पादन में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच, देश के कई हिस्सों से एलपीजी वितरक एजेंसियों ने आपूर्ति में बाधा आने की सूचना दी है।

वहीं, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआइ) ने अपने सदस्यों को गैस की खपत घटाने की सलाह दी है। (पेज 5 भी देखें)

लखनऊ में मंगलवार को लालबाग इलाके में इंडेन गैस एजेंसी के बाहर भरा एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए कतार में लगे लोग। प्रेट्र

19.1 करोड़ घन मीटर गैस की जरूरत भारत को रोज

33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन देशभर में

7 लाख टैंकर खाड़ी देशों में अलग-अलग जगह मौजूद

3,50,000 टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य में अटके

50 अरब डालर के सामानों की आपूर्ति भारत से खाड़ी देशों में

हम घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह की कमी नहीं है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। - हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

अमेरिका-इजरायल का ईरान पर फिर बड़ा हमला

पश्चिम एशिया में **महासंग्राम**

11 वां दिन

- ईरान पर दबाव बढ़ाने को अमेरिका-इजरायल ने झोंकी हमलों की नई लहर
- ईरान ने भी इजरायल और खाड़ी देशों को बनाया निशाना

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध मंगलवार को 11वें दिन और भी भीषण हो गया। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर नए सिरे से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने भी इजरायल और खाड़ी देशों की ओर मिसाइल और ड्रोन दागकर पलटवार किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरनेवाले तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित हुई तो अमेरिका 20 गुना ताकत से ईरान पर हमले करेगा। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो क्षेत्र से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आइआरजीसी ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध कब खत्म होगा, यह तेहरान तय करेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान युद्ध हार रहा है। अगले कुछ घंटों में अब तक के सबसे भयानक हमले होंगे।

दक्षिणी लेबनान के अब्बासियाह में मंगलवार को इजरायली हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। एएफपी

ईरान की चेतावनी, हमें खत्म करने के चक्कर में कहीं आप ही न खत्म हो जाएं पेज>>11

- इजरायल के पीएम नेतन्याहू बोले, ईरान पर हमले जारी रहेंगे
- अमेरिका रक्षा मंत्री बोले, और भयानक हमले झेलेगा ईरान
- अमेरिकी सेना ने कहा, समुद्र में ईरानी बारूदी सुरंग हमारे निशाने पर
- अमेरिका ने 10 दिनों में 5000 ठिकानों पर की बमबारी, 50 जहाज डुबोए

एअर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज, 12 मार्च से टिकट होंगे महंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- घरेलू उड़ानों पर प्रति टिकट 399 रुपये अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 200 डालर तक सरचार्ज
- एटीएफ की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस पर दबाव, अन्य कंपनियां भी बढ़ा सकती हैं किराया

खाड़ी क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक संकट के कारण विमान ईंधन की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला है। एअर इंडिया समूह ने अपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर चरणबद्ध तरीके से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 12 मार्च 2026 से नई बुकिंग कराने वाले यात्रियों को टिकट के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

घरेलू उड़ानों पर प्रति टिकट 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अधिकतम 200 अमेरिकी डालर (लगभग 18324 रुपये) तक सरचार्ज लागू करने का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि एअर इंडिया के इस फैसले के बाद अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी अपने किराए में बढ़ोतरी कर सकती हैं।

तीन चरणों में लागू होगी बढ़ोतरी : कंपनी के मुताबिक फ्यूल सरचार्ज को तीन चरणों में लागू किया जाएगा और यह सभी उड़ानों पर लागू होगा, जिनमें एअर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित उड़ानें भी शामिल हैं। वर्तमान में एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी उड़ानों पर कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लेती है।

पहले चरण में घरेलू उड़ानों और सार्क देशों के लिए प्रति टिकट 399 रुपये का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि पहले यह शुल्क नहीं लिया जाता था। पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व की उड़ानों पर 10 अमेरिकी डालर का नया सरचार्ज लागू किया जाएगा। दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए फ्यूल सरचार्ज 40 से बढ़ाकर 60 डालर कर दिया गया है। अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर यह 60 से बढ़ाकर 90 डालर कर दिया गया है।

दूसरा चरण 18 मार्च 2026 से नई बुकिंग पर लागू होगा। इसके तहत यूरोप जाने वाली उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज 100 डालर से बढ़ाकर 125 डालर कर दिया जाएगा। वहीं उत्तर अमेरिका और आस्ट्रेलिया की उड़ानों पर यह 150 से बढ़ाकर 200 डालर कर दिया जाएगा।

प्रतीकात्मक

पहला चरण (12 मार्च से)

- 399 रुपये फ्यूल सरचार्ज घरेलू और-- सार्क देशों पर
- 10 डालर का नया सरचार्ज पश्चिम एशिया की उड़ानों पर
- 60 डालर सरचार्ज लगेगा दक्षिण-पूर्व एशिया की उड़ानों पर
- 90 डालर दक्षिण अफ्रीका जानेवाले यात्रियों को देने होंगे अतिरिक्त

दूसरा चरण (18 मार्च से)

- 125 डालर सरचार्ज यूरोप की उड़ानों पर
- 200 डालर अतिरिक्त चुकाने होंगे उत्तरी अमेरिका व आस्ट्रेलिया जाने के लिए

तीसरा चरण (तारीख घोषित नहीं)

- हांगकांग, जापान व दक्षिण कोरिया पर सरचार्ज लगेगा, बाद में होगा एलान

इसके बाद तीसरा चरण लागू किया जाएगा। हांगकांग, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्वी बाजारों के लिए तीसरे चरण में फ्यूल सरचार्ज लागू किया जाएगा, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी।

पहले बुक टिकट रहेंगे अप्रभावित : एअर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय से पहले जारी किए गए टिकटों पर यह नया सरचार्ज लागू नहीं होगा। हालांकि यदि यात्री टिकट की तारीख या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करते हैं तो किराए की दोबारा गणना के साथ नया सरचार्ज लागू हो सकता है।

स्पीकर ओम बिरला पर लोकसभा में राजनीतिक घमासान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने बिरला को बताया जेंटलमैन
- साथ ही सदन में विपक्ष की आवाज कमजोर करने का लगाया आरोप
- सरकार ने कहा- स्पीकर ने विपक्ष को दिए हैं पर्याप्त अवसर

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसदीय परंपराओं, सदन के संचालन और विपक्ष को मिलने वाले अवसरों को लेकर सीधा टकराव दिखा। विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक स्वर से ओम बिरला को जेंटलमैन बताया, लेकिन आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में सदन के संचालन में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही और विपक्ष की आवाज कमजोर की जा रही है। सत्तापक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिरला ने नियमों और परंपराओं के अनुरूप ही सदन का संचालन किया है।

कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत करते हुए बिरला की खूबियां गिनाने के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मजबूरियां भी बताईं। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू, जदयू नेता राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने स्पीकर का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष सरकार के कामकाज में मुद्दे नहीं ढूंढ़ पा रहा, इसलिए स्पीकर को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान और बीआर आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह सदन सरकार और विपक्ष दोनों का है। संविधान के अनुच्छेद-105 के तहत सांसदों को अभिव्यक्ति की विशेष स्वतंत्रता दी गई है और नियमों के जरिये उसे सीमित नहीं किया जा सकता। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के विदेश जाने का मुद्दा उठाने से पहले सदन में माइक बंद होने के आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए। स्पीकर का पद अत्यंत गरिमामयी है और इस पर उठे सवालों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना (यूबीटी) के अरविंद सावं, आदि नेताओं ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से बिरला का सम्मान करते हैं, लेकिन सदन में निष्पक्षता की भी अपेक्षा रखते हैं।

नेता प्रतिपक्ष पर भी प्रस्ताव आना चाहिए : ललन पेज>>3

नेता प्रतिपक्ष को 20 बार रोका गया : गोगोई

लोकसभा में बोलते कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई। प्रेट्र

गौरव गोगोई ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। दावा किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को करीब 20 बार रोका गया। स्पीकर ने विपक्षी महिला सांसदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए। कहा कि कई बार विपक्षी सांसदों के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी आवाज सदन तक नहीं पहुंचती। अविश्वास प्रस्ताव व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि संसद की गरिमा और संविधान की रक्षा के लिए लाया गया है।

सदन में बोलकर राहुल विदेश चले जाते हैं : रिजीजू

लोकसभा में बोलते केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू। एएनआइ

रिजीजू ने कहा कि बिरला ने नियमों और परंपराओं के अनुसार निष्पक्षता से सदन का संचालन किया है। कुछ नेता सदन में भाषण देकर विदेश चले जाते हैं। सरकार की बात नहीं सुनते, जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने पूर्व में राहुल गांधी द्वारा स्पीकर को 'यार' कहने पर आपत्ति व्यक्त की। रिजीजू ने प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रशंसा करते हुए कहा, 'वह सदन को ज्यादा समय देती हैं, ज्यादा मिलनसार हैं और नेता प्रतिपक्ष पद को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं।'

हिंसा व भय मुक्त होंगे बंगाल विस चुनाव : मुख्य चुनाव आयुक्त

कोलकाता : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ (फुल बेंच) द्वारा बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दो दिनों तक समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद कोलकाता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने आश्वस्त किया कि विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंसा और भय रहित वातावरण में संपन्न होंगे। राजनीतिक दलों और नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आयोग मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। (पेज-5)

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क से जुड़े तीन सरकारी कर्मी बर्खास्त

जम्मू : सफेदपोश आतंकियों पर कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को जलशक्ति विभाग के तीन कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। ये तीनों अस्थायी कर्मी थे और इस समय जेल में बंद हैं। ये आतंकियों के लिए हथियार, सुरक्षित ठिकाना, सुरक्षाबलों की रैकी और युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने सहित कई राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल थे। (पेज-6)

'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय पर एनसीईआरटी ने फिर मांगी माफी

नई दिल्ली : एनसीईआरटी ने आठवीं की पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल करने के लिए मंगलवार को फिर माफी मांगी। साथ ही कहा कि पाठ्यपुस्तक वापस ले ली है। आठवीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में कहा गया था कि भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का बोझ और न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या प्रमुख चुनौतियां हैं। (पेज-7)

उत्तराधिकार में बराबरी पर सुप्रीम कोर्ट बोला, इसका जवाब यूसीसी

मुस्लिम महिलाओं का मामला

शीर्ष अदालत पहले भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में व्यक्त कर चुकी है राय, शरिया एक्ट रद करने की मांग पर कहा, क्या इससे शून्यता उत्पन्न नहीं हो जाएगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकार में पुरुषों के बराबर अधिकार देने की मांग के मामले पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को एक बार फिर खुलकर समान नागरिक संहिता का समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि इसका जवाब समान नागरिक संहिता (यूसीसी) है। यह पहला मौका नहीं है जब शीर्ष अदालत ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार समान नागरिक संहिता के पक्ष में मत व्यक्त कर चुका है। अभी देश में सिर्फ दो राज्य हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। एक गोवा और दूसरा उत्तराखंड। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का मामला केंद्र सरकार ने विचार के लिए विधि आयोग को भेजा था, जो अभी भी आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

समान नागरिक संहिता की तरफदारी करने वाली उक्त टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जोयमाल्या बागची और आर. महादेवन की पीठ ने शरिया एक्ट, 1937 को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण बताते हुए उसे रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। याचिकाकर्ता पौलोमी पवनी शुक्ला व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जैसे ही बहस शुरू की, तभी प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर कोर्ट 1937 के शरिया कानून को रद कर देता है तो मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार के बारे में कानूनी शून्यता उत्पन्न नहीं हो जाएगी और उस स्थिति में क्या होगा। भूषण ने कहा कि यह कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, इसलिए रद होना चाहिए। उत्तराधिकार धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसे रद करने से कानूनी शून्यता नहीं उत्पन्न होगी। इसकी जगह भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कहीं हम सुधारों के प्रति अति उत्साह में उन्हें वंचित न कर दें। उन्हें अभी जो मिल रहा है, उससे भी कम मिल सकता है। इस बारे में कुछ होमवर्क होना चाहिए कि अगर 1937 के कानून को रद किया जाता है तो क्या होगा। भूषण ने कहा कि कोर्ट यह कह सकता है कि मुस्लिम महिलाओं को भी उत्तराधिकार में बराबरी का हक होगा। इस पर कोर्ट ने पर्सनल ला के बारे में नरसू अप्पू माली केस में दिए पूर्व फैसले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पर्सनल ला को मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तभी जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भूषण से कहा कि भेदभाव के मुद्दे पर आपका केस बहुत मजबूत है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि कोर्ट इस मामले को विधायिका के विवेक पर छोड़ दे, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश ने सहमति जताते हुए कहा कि उसका उत्तर समान नागरिक संहिता है।

कोर्ट ने किया यह सवाल

जस्टिस बागची ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक पत्नी का नियम सभी समुदायों में समान रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि अदालत सभी दो विवाहों को असंवैधानिक घोषित कर दे? हमें निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन विधायी शक्तियों पर छोड़ना होगा। कोर्ट समय-समय पर यूसीसी बनाने की सिफारिश कर चुकी है।

नमामि गंगे : देवप्रयाग के बाद आचमन योग्य नहीं गंगा जल

राज्य ब्यूरो, जागरण • चमोली

- कैग ने उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम की वर्ष 2018 से 2023 की लेखा परीक्षा में इंगित की कई खामियां

राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए चल रहे केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम के बावजूद उत्तराखंड में गंगा पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर केंद्रित वर्ष 2018 से 2023 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसी तरफ इशारा कर रही है, जो मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र में सदन के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट बताती है कि देवप्रयाग तक गंगा का पानी आचमन योग्य (ए श्रेणी) है, जबकि इससे आगे ऋषिकेश व हरिद्वार तक यह नहाने योग्य (बी श्रेणी) ही है। कैग ने लेखा परीक्षा में कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई खामियों को इंगित किया है। कैग ने वर्ष 2018-23 तक की अवधि तक की लेखा परीक्षा में गंगा में प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने या कम करने के लिए कार्यक्रम की प्रभावशीलता का आकलन किया।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि राज्य सरकार ने गंगा तट पर स्थित नगरों में पूरक सीवेज सुविधाओं में वृद्धि को धन ही आवंटित नहीं किया।

वापस भेज दिए गए 21.34 करोड़

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक 985.17 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए, जिसमें से 873.17 करोड़ रुपये ही उपयोग में लाए गए। शेष 21.34 करोड़ की राशि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को वापस की गई।

600 देश दुनिया के शेफ दिखा रहे आहार मेले में अपनी कला, शनिवार तक चलेगा पांच दिवसीय मेला, आगंतुकों को मिल रहा लाइव किचन में अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद। इस साल मेले में ऐसी तकनीक भी दिखाई गई हैं जो आपके काम को आसान बना देंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 11 मार्च, 2026

आज का मौसम
बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तेज धूप भी निकली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
11 मार्च	36.0	18.0
12 मार्च	35.0	18.0
नोएडा		
11 मार्च	34.0	17.0
12 मार्च	33.0	17.0
गुरुग्राम		
11 मार्च	35.0	19.0
12 मार्च	34.0	20.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

कश्मीरी गेट आइएसबीटी में मिलेगा खाने पीने का सामान

नई दिल्ली : आइएसबीटी के अंदर अब खाने-पीने का सामान मिल सकेगा। अंदर के साथ ही सामने के हिस्से में भी साफ-सफाई की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान की होगी। व्यावसायिक कार्य वाले स्थान को दो-दो साल के लाइसेंस अवधि के लिए लीज पर दिया जाएगा। बस टर्मिनल में करीब 20 जगहों की पहचान की गई है, जिन्हें रिटेल दुकानों, सर्विस आउटलेट और सुविधा स्टोर के तौर पर शुरू किया जा सकेगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीटीआइडीसी) ने इस संबंध में टेंडर निकाला है। (राब्यू)

स्क्रैप कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद में युवक की हत्या

नई दिल्ली : मध्य दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से पिछले तीन दिन से लापता अरीब नाम के युवक का शव फरीदाबाद से बरामद किया गया है। दरियागंज के कूचा चालान का रहने वाला अरीब स्क्रैप कारोबारी था। चांदनी महल थाना पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम राहुल और बाबू हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपितों ने कारोबार से जुड़े पैसों के विवाद में अरीब की हत्या की थी। (जासं)

कारोबारी का मिला शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

नई दिल्ली : सात मार्च को गायब हुए कपड़ा कारोबारी व इंफ्लुएंसर आकाश उर्फ पुष्पेंद्र का शव संदिग्ध हालात में पटपड़गंज औद्योगिक थाना क्षेत्र के एक मैदान से बरामद हुआ। जिस वक्त युवक का शव मिला, नाक व मुंह से खून निकल रहा था। पास में नशे के इंजेक्शन पड़े मिले। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। (जासं)

व्यापार समझौतों में चीनी आयात पर टैरिफ में छूट की अनुमति नहीं : पीयूष गोयल

बनेगा फूड बास्केट ▶ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया आहार मेला 2026 का उद्घाटन

गोयल ने कहा, कृषि व प्रोसेस्ड फूड निर्यात में भारत को मजबूत बनाने के लिए सहयोग जरूरी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

भारत मंडपम में मंगलवार को आहार मेला 2026 के उदघाटन अवसर पर मेले की डायरेक्टरी का लोकार्पण करते केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। साथ में हैं आइटीपीओ के अध्यक्ष जावेद अशरफ और विदेशी राजनयिक एनटेनियो बारटोने। जागरण

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल, गेहूं, मक्का, सोया मील और दालों की कई किस्मों को व्यापार समझौतों में संरक्षण दिया गया है। वहीं चीनी क्षेत्र में आम तौर पर रियायतें नहीं दी गई हैं। इससे ऐसे आयात को रोका जा सके जो भारत के गन्ना किसानों और घरेलू उत्पादकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। गोयल ने खाद्य, कृषि और हास्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आह्वान किया है, ताकि भारत को कृषि और प्रोसेस्ड फूड निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके।

भारत मंडपम में आयोजित 'आहार 2026–अंतरराष्ट्रीय फूड एवं हास्पिटैलिटी मेले' के 40वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के खाद्य एवं कृषि उत्पाद (कृषि उपज और मत्स्य उत्पाद) का निर्यात अब लगभग पांच लाख करोड़ रुपये (55 अरब डालर से अधिक) वार्षिक का हो गया है। इस कारण भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन चुका है। 2014 से 2025 के बीच भारत के कृषि और खाद्य निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अवधि में प्रोसेस्ड फूड का निर्यात चार गुना बढ़ा है, जबकि फल और दालों का निर्यात तीन गुना बढ़ा। प्रोसेस्ड सब्जियों का निर्यात चार गुना, कोको का निर्यात तीन गुना, अनाज का निर्यात दोगुना और चावल का निर्यात 62 प्रतिशत तक बढ़ा है। कार्यक्रम में आइटीपीओ के अध्यक्ष जावेद अशरफ सहित विदेशी प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

गोयल ने कहा कि यह लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस परिकल्पना के अनुरूप है, जिसमें भारत को 'दुनिया का फूड बास्केट' बनाने की बात कही गई है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत द्वारा किए गए नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर लेकर आए हैं। इन समझौतों के जरिये भारत को 38 विकसित देशों के बाजारों तक पहुंच मिली है। इससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने में मदद मिलेगी। गोयल ने किसानों और उद्यमियों से एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष का लाभ उठाने और फूड प्रोसेसिंग व वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने को कहा है। इससे किसानों को वैश्विक बाजारों में बेहतर मूल्य मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने आहार 2026 में इटली को पार्टनर देश बनाने पर स्वागत करते हुए कहा कि भारत को इटली के फूड और हास्पिटैलिटी सेक्टर के अनुभवों से सीखना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदर्शनी को 13 मार्च की शाम और अगले दिन आम जनता के लिए भी खोला जाएगा, ताकि युवा वर्ग भारत और दुनिया के खाद्य एवं हास्पिटैलिटी उद्योग की क्षमताओं को करीब से देख सके।

75 एकड़ में फैलेगा 'मिनी ओलिंपिक' का सपना, तीन साल में होगा साकार

▶ नरेला में 'मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम' बनाने के लिए डीडीए ने मांगे प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला के सेक्टर-जी 3 और जी 4 में एक 'मल्टी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम' बनाने की योजना तैयार की है। यह स्टेडियम न केवल दिल्ली का सबसे बड़ा खेल परिसर होगा, बल्कि आधुनिक सुविधाओं में अंतरराष्ट्रीय मानकों को टक्कर देगा। डीडीए ने इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट फार प्रपोजल (आरएफपी) जारी कर दिया है। इसमें कई शर्तें शामिल हैं।

स्टेडियम की मुख्य विशेषताएं

विशाल क्षमता : इस नए क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 80,000 होगी। यह दिल्ली के वर्तमान अरुण जेटली स्टेडियम (55,000 क्षमता) से कहीं अधिक बड़ा होगा।

75 एकड़ का परिसर : इस प्रोजेक्ट को 75 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा।

विविध खेल सुविधाएं : यहां केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस और स्विमिंग पूल जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी।

ओलिंपिक मानक : यह पूरा कांप्लेक्स ओलिंपिक मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में अंतरराष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जा सके।

खिलाड़ियों और पर्यटकों के लिए खास इंतजाम : खेल सुविधाओं के अलावा, इस कांप्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी जोर दिया गया है:-

हास्पिटैलिटी और रिटेल : परिसर में आलीशान होटल, रिटेल आउटलेट्स और कमर्शियल आफिस स्पेस विकसित किए जाएंगे।

क्लब हाउस : खिलाड़ियों और विजिटर्स के लिए एक अत्याधुनिक क्लब हाउस होगा, जिसमें ठहरने के लिए लगभग 75 एग्जीक्यूटिव कमरे होंगे।

पार्किंग : यहां पार्किंग की व्यापक व्यवस्था होगी, जिसमें प्रति 100 वर्ग मीटर के निर्माण पर दो कारों की जगह सुनिश्चित की जाएगी।

55 वर्षों के लिए इस जमीन का दिया जाएगा लाइसेंस

इस जमीन को 55 वर्षों के लिए लाइसेंस के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए बिड सिक्योरिटी के रूप में 28 करोड़ रुपये रखे गए हैं और सालाना सुरक्षित राशि 36.12 लाख निर्धारित की गई है। इस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के बनने से न केवल स्थानीय युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि दिल्ली के इस इलाके के आर्थिक विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी।

आबकारी मामले में ईडी पर ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां सामान्य : हाई कोर्ट

▶ ईडी की याचिका पर अदालत ने केजरीवाल-सिसोदिया सहित अन्य से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आबकारी घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर की गई टिप्पणियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने सामान्य प्रकृति का बताया है। हालांकि, ईडी की याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपितों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाए जाने की मांग को लेकर दायर ईडी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। ईडी ने याचिका में कहा है कि जांच एजेंसी किसी भी तरह से सीबीआइ की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थी और यह स्थिति प्राकृतिक न्याय और न्यायिक मर्यादा के बुनियादी सिद्धांतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा दर्ज केस पर फैसला सुनाते हुए जांच एजेंसी का पक्ष सुने बगैर ही ईडी के खिलाफ टिप्पणियां की हैं। जबकि, मनी लांड्रिंग का मामला संबंधित जज के सामने नहीं था और यह सीबीआइ का मामला था। केजरीवाल को मनी लांड्रिंग के लिए गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। वहीं, केजरीवाल-सिसोदिया की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि ये बातें मामले की मेरिट के आधार पर कही गई थीं और निजी नहीं थीं। प्रतिवादियों की तरफ से ही पेश हुए अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि एजेंसी ने अलग-अलग पैरा उठाया है, जबकि इसे टुकड़े में देखने के बजाय पूरे परिपेक्ष्य में देखना होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि ये सामान्य टिप्पणियां हैं और इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ईडी के तर्कों पर विचार करेगी और देखेगी कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसी बातें कही जा सकती थीं।

होली के दिन युवक की हत्या के आरोपितों के घर पर न की जाए कार्रवाई : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : होली के दिन उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक की हत्या में एक आरोपित की मां ने घर पर बुलडोजर चलाने से रोकने का निर्देश देने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई बुधवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए एमसीडी को मौखिक रूप से निर्देश दिया कि प्राथमिकी में शामिल आरोपितों की संपत्ति पर बुधवार तक कार्रवाई न की जाए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता उत्तम नगर में जेजे कालोनी में एक घर की मालिक है और पिछले चार दशकों से रह रही है। पांच मार्च को पड़ोसियों के बीच हुए झगड़े के बाद मामला दर्ज हुआ था, लेकिन मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सात मार्च को एक भीड़ गैरकानूनी तरीके से इलाके में इकट्ठा हुई और दरवाजे तोड़ आरोपितों के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।

इसके बाद एमसीडी ने पूर्व नोटिस दिए बिना आठ मार्च को एक आरोपित के घर पर बुलडोजर से गिरा दिया।

ग्रीन बजट की तैयारी, पर्यावरण व विकास के बीच संतुलन बनाएगी दिल्ली सरकार

▶ सरकार का मानना है कि ग्रीन बजट से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और तेजी से हो रहे शहरीकरण के इस दौर में दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन बजट की अवधारणा पर गंभीरता से मंथन कर रही है ताकि राजधानी में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। बजट का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय और योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास से जुड़े कार्यों पर केंद्रित हो। इससे पहले आप सरकार वर्ष 2018-19 के लिए ग्रीन बजट पेश कर चुकी है, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था।

उल्लेखनीय है कि कई देशों के साथ-साथ भारत के कुछ राज्यों ने भी ग्रीन बजट या क्लाइमेट बजटिंग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बिहार, राजस्थान, असम, केरल, मेघालय और ओडिशा के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने भी अपने अपने यहां अलग अलग समय पर ग्रीन बजट पेश किया है। इन पहलों का उद्देश्य यह है कि बजट में पर्यावरण से संबंधित योजनाओं और परियोजनाओं को अलग से चिह्नित किया जाए ताकि नीति निर्माण और संसाधनों के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। दिल्ली सरकार भी इन माडलों का अध्ययन कर रही है और राजधानी के लिए उपयुक्त व्यवस्था विकसित करने पर मंथन कर रही है।

दिल्ली विधानसभा। फाइल

सूत्रों के अनुसार ग्रीन बजट जैसी पहल केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास के नए अवसर भी पैदा करती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन (वेस्ट मैनेजमेंट), जल संरक्षण और हरित अवसंरचना (ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ सकेगा। जिससे नई तकनीकों के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिये स्वच्छ परिवहन को मिलेगा बल : ग्रीन बजट के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहन नीति (ईवी पालिसी) से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिससे वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। इसके अलावा सौर ऊर्जा के विस्तार, रूफटाप सोलर परियोजनाओं की उपस्थिति बजट में दर्ज होगी।

गुरुग्राम में सात श्रमिकों की मौत छिपाने की कोशिश, घायलों को ले गए भिवाड़ी

▶ कंपनी, ठेकेदार और साइट इंचार्ज समेत छह पर गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम

गुरुग्राम जिले में सिधरावली के पास सिग्नेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन साइट पर एसटीपी के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी में दबने से सोमवार रात सात श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हो गए। श्रमिकों का आरोप है कि साइट के अंदर हुए हादसे को छिपाने की कोशिश की गई। कंपनी की तरफ से घटना की जानकारी न तो गुरुग्राम पुलिस को दी गई और न ही किसी घायल को पांच किलोमीटर दूर बिलासपुर या आसपास किसी अस्पताल भेजा गया। श्रमिकों को दस किमी दूर राजस्थान के भिवाड़ी के निजी अस्पताल ले जाया गया था। रात करीब नौ बजे भिवाड़ी पुलिस ने जब शव मिलने की जानकारी गुरुग्राम पुलिस को दी, तब पुलिस मामले में सक्रिय हुई। मंगलवार को मामले में कंपनी, ठेकेदार समेत छह लोगों पर गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।

सिधरावली के पास सिग्नेचर ग्लोबल की इस साइट पर प्लाटिंग का काम चल रहा है। वहां मुख्य गेट के साथ चारों तरफ चारदीवारी बनाई गई है। कुछ दिनों से साइट के अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण कार्य चल रहा था। श्रमिकों का कहना है कि प्लांट बनाने के लिए करीब 50 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। इसमें नीचे सीमेंट का बेस बनाया गया था। सोमवार शाम करीब सात बजे अचानक मिट्टी खिसकने लगी। इसको देखकर कई श्रमिक तुरंत बाहर निकल आए, लेकिन 11 अंदर ही फंसे रह गए। श्रमिकों का आरोप है कि 11 लोगों के मिट्टी के नीचे दबने के बाद भी बिल्डर और ठेकेदार ने प्रशासनिक मदद लेने के बजाय घटना को दबाने की कोशिश की। सभी घायलों को भिवाड़ी के गीतांजलि अस्पताल ले जाया गया, जबकि बिलासपुर में भी रमन मुंजाल समेत कई बड़े निजी अस्पताल हैं। इससे समय बर्बाद हुआ और घायलों की स्थिति बिगड़ गई।

शराब पीते हुए बंद कैब में सो रहे दो युवकों की हुई मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित खेड़ा खुर्द में मंगलवार सुबह 11 बजे एक कैब से संदिग्ध परिस्थितियों में दो शव मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जांच के दौरान कैब के अदर देशी शराब तीन पाउच मिले हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि शराब पीने के बाद दोनों युवक कैब के अंदर ही सो गए होंगे। कैब के गेट व शीशे बंद होने के कारण दम घुटने से दोनों की मौत हो गई होगी।

मृतकों की पहचान 42 वर्षीय विकास और 36 वर्षीय बिजेंद्र उर्फ भोला के रूप में हुई है। विकास का शव चालक वाली सीट पर जबकि बिजेंद्र का शव पीछे वाली सीट पर पड़ा मिला है। दोनों खेड़ा खुर्द गांव के ही रहने वाले थे। बिजेंद्र मृतक विकास का मौसेरा भाई था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।

एनसीआर में धुंध और कोहरे की चादर, धूल व नमी ने बिगाड़ी हवा, 15 को वर्षा के आसार

▶ धूल और नमी का मिश्रण है धुंध और कोहरे का कारण

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

मंगलवार को सुबह 11 बजे विकास मार्ग पर छाए स्मॉग के बीच गुजरते वाहन। चंद्र प्रकाश मिश्र

देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार की सुबह मौसम के कई रंग देखने को मिले। एक तरफ जहां आसमान में धुंध छाई रही, वहीं दूसरी ओर हल्के कोहरे ने दृश्यता कम कर दी। हालांकि मौसम विभाग ने इस स्थिति को सामान्य करार दिया। यह बात अलग है कि इसने वायु गुणवत्ता को अवश्य प्रभावित किया।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार सुबह छाई धुंध दरअसल पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाली धूल और हिमालयी क्षेत्रों से आई नमी का परिणाम थी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं ने नमी बढ़ाई, जिससे घने कोहरे की स्थिति बनी। एनसीआर में सबसे कम दृश्यता हिंडन एयरपोर्ट पर दर्ज की गई, जो सुबह सात से आठ बजे के बीच मात्र 600 मीटर रही। मौसम विभाग के वरिष्ठ विज्ञानी आर के जेनामणि ने बताया कि मार्च में इस तरह का कोहरा पहले भी देखा गया है। उन्होंने छह से आठ मार्च 2008 की घटना का जिक्र किया, जब इसी तरह का मौसम था। वहीं, स्काईमेट वेदर के महेश पालावत के अनुसार, यह "डस्ट हेज" है जो बलूचिस्तान और राजस्थान के थार रेगिस्तान से चलने वाली तेज पश्चिमी हवाओं के कारण यहां पहुंची है।

अधिकतम तापमान सामान्य से 7.0 डिग्री ऊपर : दिल्ली में गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार लगातार चौथा ऐसा दिन रहा जब अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 7.0 डिग्री अधिक तो न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री

हवा हुई 'खराब', प्रदूषण का स्तर बढ़ा : धुंध और धूल के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को एक्यूआइ 265 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। इससे एक दिन पहले सोमवार को यह 209 था। केंद्र की अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक बुधवार तक हवा 'खराब' श्रेणी में बनी रहेगी। हालांकि 12 और 13 मार्च से सुधार होने की उम्मीद है।

15 मार्च को वर्षा की संभावना : मौसम विभाग और स्काईमेट के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ और मैदानी इलाकों के ऊपर बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 15 मार्च को वर्षा और धूल भरी आंधी की संभावना है। वर्षा के बाद तापमान में गिरावट आएगी।

जनकपुरी हादसे में आरोपित मुख्य ठेकेदार गिरफ्तार, एक अभी भी फरार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जनकपुरी में पांच फरवरी की रात जोगेंदर सिंह मार्ग पर बीच सड़क पर खोदे गए दिल्ली जल बोर्ड के गहरे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिमी दिल्ली की एंटी आटो थेफ्ट स्क्वायड (एएटीएस) की टीम ने मंगलवार सुबह उदयपुर से मुख्य ठेकेदार हिमांशु गुप्ता को पकड़ लिया है। वे पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयपुर में छिपा हुआ था। पुलिस आरोपित को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर आ रही है। इस मामले में दूसरे मुख्य आरोपित कविश गुप्ता की अभी तलाश जारी है।

जनकपुरी बी ब्लाक में दिल्ली जल बोर्ड के काम के लिए बीच सड़क पर खोदे गए करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में बाइक समेत गिरने से 25 वर्षीय कमल ध्यानी नामक की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि गड्ढे के आसपास न तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी संकेत लगाए गए थे, जिससे यह हादसा हुआ।

भलस्वा लैंडफिल साइट पर 20 एकड़ में बनेगा नया आइएसबीटी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली सचिवालय में बैठक करते दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डा पंकज सिंह। सौजन्य : दिल्ली सरकार

दिल्ली के परिवहन मंत्री डा. पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि भलस्वा लैंडफिल साइट पर करीब 20 एकड़ भूमि पर नया डीटीसी अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) बनाने की योजना बनाई जा रही है। यह प्रोजेक्ट उस भूमि पर प्रस्तावित है, जिसे लैंडफिल साइट से खाली कराया जा रहा है। प्रस्तावित टर्मिनल से शहर के उत्तरी हिस्से में अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

डा. सिंह ने परिवहन विभाग और डीटीसी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। परिवहन मंत्री ने बताया कि अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर) कारिडोर पर एक नया डीटीसी डिपो बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती परिवहन मांग को बेहतर सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने अधिकारियों को बुराड़ी में मौजूदा बस डिपो को अपग्रेड करने को भी कहा है। वहीं नंद नगरी और तेहखंड में बनने वाले आटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के अप्रैल में चालू होने की उम्मीद है। इससे फिटनेस टेस्टिंग का इकोसिस्टम मजबूत बनेगा।

टर्मिनल से अब हर 15 मिनट में निकलेंगी बसें

▶ अब 5800 बसों के हिसाब से तय किया जा रहा है टाइम-टेबल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) की 2500 बसें भी आ गई हैं। इसलिए परिवहन विभाग बसों के संचालन को लेकर नया टाइम टेबल बना रहा है। व्यस्त समय में सड़कों पर अधिक बसें रहेंगी। टर्मिनल से निकलने का समय भी 30 मिनट की जगह 15 मिनट किया जाएगा। वहीं अधिक सवारी वाले रूटों पर बसें अधिक रहेंगी, जबकि दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच बसों की संख्या कम रहेगी।

डिम्ट्स और डीटीसी के द्वारा अलग-अलग तरह से बसों का संचालन किए जाने से कई बार एक ही रूट पर डीटीसी और डिम्ट्स की बसें एक ही समय पर पहुंचती थीं। डिम्ट्स की बसों के संचालन को लेकर डीटीसी के पास कोई अधिकार नहीं था। अब डीटीसी सभी 5800 बसों के संचालन के लिए नए सिरे से योजना बना रहा है। पुरानी दिल्ली से महरौली, कापसहेड़ा, बदरपुर, मोलड़बंद, नरेला, नजफगढ़ का रूट अति व्यस्ततम रूट माना जाता है। इन रूटों पर बसों की संख्या पहले से कम है। इसी तरह केंद्रीय सचिवालय से चलने वाले रूटों पर भी बसें कम हैं। वहीं टीकरी बार्डर से पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी से रूट नंबर 569 और मंगोलपुरी से रूट नंबर 808, 568 भी व्यस्त रूट हैं।

नरेला से 708 नंबर की बस और रानीखेड़ा से पुरानी दिल्ली स्टेशन के लिए रूट नंबर 921 व नजफगढ़ से नेहरू प्लेस को जाने वाली बसों का रूट व्यस्ततम रूट में शामिल है।

टैक्सी सेवा की तरह मलबा उठाने के लिए कर सकेंगे वाहन बुक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वाहनों के अभाव में मलबा इधर-उधर डालने की शिकायतों के बाद अब टैक्सी सेवा की तरह ही मलबा उठवाने के लिए वाहन की व्यवस्था होगी। इसके लिए एमसीडी द्वारा शुरू किए गए मलबा पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। जहां लोग लाग-इन करके मलबा उठाने का आग्रह कर सकते हैं। पोर्टल पर मलबा उठाने के लिए आने वाली टीम का नाम और वाहन की जानकारी आएगी। साथ ही मलबा उठने तक की पूरी जानकारी भी नागरिक आनलाइन ही देख सकेंगे।

निगम के अनुसार https://delhi.tracewaste360.in पर लाग-इन करके मलबा उठाने का आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें लाग-इन करते समय जानकारी देनी होगी कि वह कहां रहते हैं।

जहाज पर नौकरी दिलाने वाले फर्जी काल सेंटर का सरगना समेत छह गिरफ्तार

▶ नोएडा में पांच माह से चल रहा था काल सेंटर, उपकरण, दस्तावेज बरामद

जागरण संवाददाता, नोएडा

देश-विदेश में पानी के जहाज पर हेल्पर, फिटर, बावर्ची, इलेक्ट्रिशियन आदि की नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले काल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश कर सरगना समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित पांच माह से यहां काल सेंटर खोलकर लोगों को ठग रहे थे। एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपितों तक पहुंची। गिरोह 350 से ज्यादा लोगों से डेढ़ करोड़ रुपये की ठगी कर चुका है। गिरोह नोएडा में जगह बदल-बदलकर करीब सालभर से सक्रिय था।

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान सरीम खान, शोएब खान, रितिका, खुशी उर्फ खुशबू, मंतशा अब्बासी, फातिमा के रूप में हुई है। एसीपी राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि बीकाम पास सरीम गिरोह का सरगना है। उसने आकाश संग मिलकर करीब 50 हजार रुपये प्रतिमाह पर जगह किराये पर लेकर काल सेंटर खोला था। इंटरनेट मीडिया पर वीआर हाइरिंग फार क्रूज जाब के नाम से प्रचार प्रसार कर रहे थे। इच्छुक लोगों के संपर्क करने पर एमबीए पास मंतशा, बीबीए पास खुशी बात करती थीं। शोएब, रितिका व फातिमा पंजीकरण और फीस जमा कराते थे। नौकरी के नाम पर 10 हजार रुपये से एक लाख रुपये बंधन और आइडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा के खाते में डलवाते थे। कुछ दिन पीड़ित को टरकाते रहते। फिर उसको ब्लाक कर देते और कुछ दिनों में सिमकार्ड भी तोड़कर फेंक देते थे।

11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में 61 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,287 किमी था, जो 2025 में बढ़कर 1,46,560 किमी हो गया। गत 5 वर्षों में ही 57,125 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया।

जल जीवन मिशन को 2028 तक मिला विस्तार

कैबिनेट के फैसले ▶ अधूरे काम पूरा करने पर होगा फोकस, अब तक 12 .56 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा नल से जल

मिशन को दी गई 1 .51 लाख करोड़ की और केंद्रीय मदद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हर घर नल जल पहुंचाने के लिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने अब 2028 तक विस्तार दे दिया है। इसके साथ ही मिशन को 1.51 लाख करोड़ रुपये की और केंद्रीय मदद भी जारी की गई है। बढ़ी हुई इस अवधि के दौरान मिशन के देशभर के अधूरे कामों को पूरा करने सहित स्वच्छ पानी पहुंचाने से जुड़ी सुविधाओं पर फोकस किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में जल जीवन मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ मिशन का कुल बजट भी बढ़कर 8.69 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 3.59 लाख करोड़ की केंद्रीय मदद भी शामिल है। वर्ष 2019-20 में मिशन के लिए केंद्र ने 2.08 लाख करोड़ की मदद जारी की थी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए गए

नई दिल्ली में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। प्रेट्र

रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले सराहनीय हैं। इससे माल ढुलाई और परिवहन व्यवस्था व्यवस्था बेहतर होगी। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जल जीवन मिशन पर मंत्रिमंडल का फैसला पूरे भारत में ग्रामीण परिवारों के लिए टिकाऊ और विश्वसनीय नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

– नरेन्द्र मोदी, पीएम

जेवर हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क का संशोधित लागत मंजूर

प्रेट्र के अनुसार, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सड़क संपर्क विकसित करने के लिए 3,630 .77 करोड़ रुपये की संशोधित लागत को भी मंजूरी दी। प्रस्तावित 31.42 किलोमीटर लंबा कोरिडोर दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से हवाई अड्डे तक सीधा और हाई स्पीड संपर्क प्रदान करेगा। प्रस्तावित कारिडोर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर (डीएफसी) को पार करेगा, जिससे बहु-माडल परिवहन संभव होगा। इस परियोजना का लगभग 11 किमी हिस्सा एक एलिवेटेड हाईवे के रूप में विकसित किया जाना है, जो डीएनडी-बल्लभगढ़ बाईपास और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी का एक अहम हिस्सा है, जो कि इसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।

फैसलों की जानकारी देते हुए बताया है कि जल जीवन मिशन के इस नए चरण का फोकस सेवाओं को दुरुस्त करने पर होगा। इस बीच अधूरे कामों को भी पूरा किया जाएगा। साथ ही पीने के पानी के गवर्नेंस व ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा।

वैष्णव में बताया कि इस दौरान 'सुजलम भारत' व 'जल अर्पण' जैसी पहल भी शुरू की जाएंगी। सुजलम भारत के तहत सभी गांवों को एक विशिष्ट सुजल गांव पहचान प्रदान की जाएगी, जिसमें स्त्रोत से लेकर नल तक संपूर्ण पेयजल सिस्टम की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। वहीं, जल अर्पण के जरिए इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों व समितियों को हस्तांतरित किया जाएगा। मिशन के तहत अब तक 12.56 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाने का भी दावा किया गया। पीएम ने इस मिशन का 2019 में शुभारंभ किया था। मंत्रालय ने मिशन को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए साथ ही करीब 2.80 लाख करोड़ रुपये की और मांग की थी।

दिवाला कानून और कंपनी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी : प्रेट्र के अनुसार, मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता सहिंता (आइबीसी) और कंपनी अधिनियम, 2013 में विभिन्न संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कानूनों को कारपोरेट मामलों का मंत्रालय लागू करता है।

बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली दो मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी : पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली दो महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 4,474 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 192 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इससे रेलवे यातायात क्षमता बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि दोनों परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। स्वीकृत परियोजनाओं में सैंथिया-पाकुड़ और संतरागाछी-खड़गपुर रेलखंड के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। दोनों रेलखंड पूर्वी भारत के व्यस्त मार्गों में गिने जाते हैं। यहां पहले से ही ट्रेनों का दबाव अधिक है। नई लाइनों के बनने से ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और भीड़भाड़ कम होगी।

छह साल बाद चीन से निवेश का फिर से रास्ता साफ, नियम बदला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कैबिनेट ने दी मंजूरी, 10% तक के एफडीआइ पर मंजूरी की जरूरत नहीं
- गलवन घाटी में चीन से झड़प के बाद भारत ने बदल दिया था नियम

छह साल के बाद एक बार फिर से चीन से विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को लेकर भारतीय सीमा से सटे देशों से जुड़े नियम में बदलाव करने का फैसला किया गया। छह साल पहले वर्ष 2020 में सीमा से सटे देशों से होने वाले निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया था ताकि चीन से होने वाले निवेश को रोका जा सके। इस नियम से दर्जनों इलेक्ट्रानिक्स व मोबाइल फोन कंपनियों में चीन से होने वाले निवेश बाधित हो गए थे। गलवन घाटी में चीन से झड़प के बाद भारत ने यह फैसला किया था। टिकटाक समेत कई चीनी एप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

कैबिनेट फैसले के मुताबिक अब भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों में 10 प्रतिशत तक के निवेश के लिए सीमा से सटे देशों को सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि निवेश से जुड़ी जानकारी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) को देनी होगी। कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रानिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट्स, पाली सिल्कन और इनगोट वेफर की मैन्यूफैक्चरिंग में होने वाले निवेश के प्रस्ताव पर 60 दिनों में मंजूरी दी जाएगी। भारत इन सभी आइटम का चीन से भारी मात्रा में आयात करता है। भारत मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक्स आइटम का काफी निर्यात करता है, लेकिन इस निर्यात से अधिक इलेक्ट्रानिक्स आइटम के कच्चे माल व कंपोनेंट्स का आयात किया जाता है। निवेश के इस फैसले से इन आइटम का निर्माण भारत में ही शुरू करने में मदद मिलेगी। जिन कंपनियों का स्वामित्व भारतीय नागरिकों के पास होगा, उनमें ही इस प्रकार के निवेश की इजाजत होगी।

इस फैसले से नई टेक्नोलाजी में निवेश के साथ कारोबार आसान होगा। वहीं, भारत वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकेगा। पिछले कुछ महीनों से चीन में भारत का निर्यात भी बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों में चीन में भारत के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि चीन से होने वाले आयात के मुकाबले यह निर्यात कुछ भी नहीं है। भारत चीन से 100 अरब डालर से भी ज्यादा का आयात करता है।

गहलोत के समय अरावली में हुआ सबसे ज्यादा खनन, 80% खदानें कांग्रेस ने दी : भूपेंद्र यादव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राज्यसभा में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के काम-काज पर चर्चा में मंत्री की टिप्पणी पर भड़का विपक्ष
- विपक्ष ने अरावली की परिभाषा बदलने, उसके संरक्षण से समझौता करने सहित वायु प्रदूषण पर सरकार को घेरा

बढ़ते वायु प्रदूषण और अरावली सहित पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष मंगलवार को उस समय तिलमिला गया, जब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली के मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अरावली क्षेत्र में सबसे अधिक खनन हुआ है। अरावली क्षेत्र में 70-80% खदानें कांग्रेस सरकारों के समय ही दी गई हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार अरावली सहित पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह मंगलवार को राज्यसभा में मंत्रालय से जुड़े काम-काज पर हुई चर्चा पर जवाब दे रहे थे।

चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के करीब 13 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस वैसे तो सोमवार को सदन से वाकआउट कर चली गई थी और मंगलवार को भी उसने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के काम-काज को लेकर हुई

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मंगलवार को राज्यसभा में बोलते हुए। एएनआइ

चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि चर्चा पूरी होने पर कांग्रेस के अनुरोध पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कांग्रेस को चर्चा में शामिल होने की विशेष अनुमति दी। इस दौरान कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण व अरावली के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि वह पिछले दस सालों में इसे रोकने में नाकाम रही है। डांगी ने कहा कि गैर-कानूनी खनन ने अरावली क्षेत्र की कई पहाड़ियों को खत्म कर दिया है। अरावली की परिभाषा को बदलने की कोशिश की गई।

इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि डांगी भले इस सदन में नए आए हैं, लेकिन वह 2012 से इस मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। अरावली के संरक्षण के लिए मोदी सरकार दो साल पहले ही ग्रीन वाल प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है। वहीं विपक्ष ने सरकार को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किए जाने के बाद भी दिल्ली सहित देश के 130 शहरों में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर घेरा। साथ ही सवाल भी खड़े किए। केंद्रीय मंत्री ने इससे निपटने के लिए अब तक उठाए गए कदमों को गिनाया। साथ ही बताया कि दिल्ली-एनसीआर के शहरों के लिए वार्षिक योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश में संरक्षित वन क्षेत्रों की संख्या 2014 में जहां 757 थी, वहीं अब यह बढ़कर 1,134 हो गई है।

नेता प्रतिपक्ष पर भी आना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव : ललन

प्रथम पृष्ठ से आगे

जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव को निरर्थक बताते हुए कहा कि इसे केवल एक नेता को खुश करने के लिए लाया गया है। लगातार हंगामा सदन की कार्यवाही बाधित करता है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का सदन में जिस तरह व्यवहार रहता है, उसके लिए उनके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पक्ष-विपक्ष के बीच संवाद से 140 करोड़ लोगों के हित में फैसले निकलते हैं। सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए स्पीकर को कई बार सख्त कदम उठाने पड़ते हैं।

पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर सवाल : प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्षीय पैनल के सदस्य जगदंबिका पाल ने कार्यवाही की कमान संभाली और प्रस्ताव को मत के लिए रखा। इस दौरान गौरव गोगोई ने पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि जब स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन है तो कैसे तय किया गया कि कार्यवाही अध्यक्षीय पैनल का सदस्य चलाएगा। एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह सवाल उठाया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि स्पीकर के पद से जुड़े दायित्व किसी हाल में ठप नहीं होते और नियमों के तहत पैनल का सदस्य ही सदन की कार्यवाही संचालित करता है। अविश्वास प्रस्ताव किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पेश किया। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि बिरला विपक्षी सांसदों का माइक बंद करने में महारत हासिल कर चुके हैं।

लोकसभा में सोमवार को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। प्रेट्र

गोगोई को शाह ने दिया जवाब

गौरव गोगोई और अमित शाह के बीच वार-पलटवार भी देखा गया। गोगोई ने कहा, 'भविष्य में जब संसदीय रिकार्ड पर अनुसंधान होगा तो पता चलेगा कि कि रिजीजू ऐसे संसदीय कार्य मंत्री थे, जिन्होंने विपक्ष को सबसे ज्यादा टोका था।' रिजीजू का बचाव करते हुए अमित शाह ने कहा, 'मैं सहमत हूं कि संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर रिजीजू ने सबसे ज्यादा टोका है। लेकिन हमने इतना गैर-जिम्मेदार विपक्ष भी कभी नहीं देखा।'

10 घंटे होनी है चर्चा, शाह देंगे जवाब : अविश्वास प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा तय है और अंत में सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल समेत विपक्ष के 119 सांसदों ने 10 फरवरी को इस प्रस्ताव का नोटिस दिया था। हालांकि सदन में संख्या बल के कारण इसके पारित होने की संभावना नहीं है, लेकिन बहस ने संसद के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान को उजागर कर दिया है।

आजादी के बाद यह चौथा अवसर है जब लोकसभा स्पीकर को इस तरह के प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 1954, 1966 और 1987 में भी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं।

<< लोकसभा में मंगलवार को बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, अनुप्रिया पटेल, जी किशन रेड्डी भी उपस्थित रहे। प्रेट्र

केंद्र ने राज्यों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली, प्रेट्र: पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी मंजूरी जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक अलग निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन पर स्थायी प्राधिकरण (एसएईआइए) नामक एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, साथ ही प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन पर एक स्थायी समिति (एससीईआइए) का गठन भी किया जाएगा।

ये दोनों नए निकाय राज्य स्तर पर श्रेणी बी के अंतर्गत आने वाली विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और समय पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान करेंगे।

श्रेणी बी की परियोजनाओं में निर्माण, भवन निर्माण, खनन और उद्योग शामिल हैं। मौजूदा निकायों के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में ये नए निकाय अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए कार्य करेंगे, जिसे अधिकतम छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

2025-26 में 43 नए मेडिकल कालेज, 11,682 एमबीबीएस की सीटें बढ़ीं

- स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्यसभा को दी जानकारी
- इस शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर की 8,967 सीटें बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देशभर में 43 नए मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रश्न के उत्तर में कहा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार ने देशभर में इस शैक्षणिक वर्ष में 11,682 एमबीबीएस सीटें और 8,967 स्नातकोत्तर (पीजी) सीटें स्वीकृत की हैं। इनमें एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के स्वास्थ्य इकोसिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के सुरक्षित और साक्ष्य-आधारित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआइ इंपैक्ट समिट के दौरान 'स्ट्रैटेजी फार एआइ इन हेल्थकेयर इन इंडिया' (सही) और 'स्वास्थ्य एआइ के लिए बेंचमार्किंग ओपन डाटा प्लेटफार्म' (बोध) को लांच किया है।

अन्य प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने सदन को बताया कि 14 वर्ष की किशोरियों के लिए

अनुप्रिया पटेल। फाइल

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। 17 फरवरी, 2026 तक 8.73 करोड़ महिलाओं की सर्विकल कैंसर के लिए जांच की जा चुकी है। देश में 2025 में सर्विकल कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 79,239 थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11,530 मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु में 8,389, बिहार में 8,250 और बंगाल में 6,437 मामले दर्ज किए गए।

अमेरिका से व्यापार समझौते के खिलाफ पंजाब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में मंगलवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस समझौते की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। उन्होंने कहा कि यह समझौता तीन कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। यह पंजाब व देश के किसानों की बर्बादी का समझौता है। पारित प्रस्ताव में पंजाब की कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर चिंता जताते हुए समझौते को रद करने की मांग की गई।

इस दौरान भाजपा के दोनों विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने भी निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते की जानकारी न तो संसद को दी गई और न ही किसी राज्य के साथ साझा की गई। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिका से सस्ता सोयाबीन और मक्का आने पर हमारे फीड बनाने वालों का कारोबार खत्म हो जाएगा।

जनगणना में आप के बताए धर्म को ही दर्ज करेंगे गणनाकार

- गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में दी लिखित में जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 के दौरान उत्तरदाताओं द्वारा बताए गए धर्म को ही दर्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि जनगणना के दौरान गणनाकार के समक्ष व्यक्ति खुद को जिस धर्म का बताएगा उसे ही रिकार्ड में दर्ज कर लिया जाएगा।

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में कहा, जनगणना में गणनाकार उत्तरदाता द्वारा बताए अनुसार सभी धर्मों/संप्रदायों/विश्वासों को रिकार्ड में दर्ज करता है। जनगणना 2027 में भी गणनाकार उत्तरदाता द्वारा बताए गए धर्म का नाम दर्ज करेंगे। गृह राज्यमंत्री से पूछा गया था कि क्या पिछले जनगणना में 'आदिवासी धर्म' का अलग कालम न होने के कारण आदिवासियों की अलग धार्मिक पहचान में बाधा आई और क्या सरकार का आगामी जनगणना में 'आदिवासी धर्म' के लिए अलग कालम शामिल करने का प्रस्ताव है।

मंत्री ने उत्तर में कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की कुल जनसंख्या 10,45,45,716 थी। उन्होंने कहा कि

नित्यानंद राय। एएनआइ

अनुसूचित जनजातियों की उप-जनजातियों का डाटा अलग से प्रकाशित नहीं किया जाता है। धार्मिक समुदाय के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का डाटा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर आधिकारिक जनगणना तालिकाओं में उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री 13 मार्च को पीएम-किसान की 22वीं किस्त जारी करेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत 22वीं किस्त को डिजिटल ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत 9.32 करोड़ किसानों को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी से पीएम-किसान की किस्त जारी करेंगे।

इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी, जिसके तहत सरकार प्रत्येक किसान को तीन किस्तों में वार्षिक छह हजार रुपये देती है। इससे किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों खरीदने में मदद करने की उम्मीद है। आमतौर पर, किस्तें फरवरी या मार्च, जून या जुलाई, और अक्टूबर में जारी की जाती हैं। फरवरी 2025 में 22 हजार करोड़ रुपये की 19वीं किस्त 9.8 करोड़ किसानों को जारी की गई थी। अगस्त 2025 में 20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किस्त 9.7 करोड़ किसानों को और नवंबर 2025 में 18 हजार करोड़ रुपये की 21वीं किस्त नौ करोड़ किसानों को जारी की गई थी।

संभावना

106वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रविधान है कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण प्रभावी होगा, परिसीमन पूर्व लागू करने का निर्णय लेने पर सरकार को संसद में एक और संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा

परिसीमन से पहले ही महिला आरक्षण कानून लागू करने पर विचार

- आरक्षण लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे बाद में बढ़ा सकती है संसद
- 1996 से चल रहा था महिला आरक्षण का प्रयास, जो अंततः 2023 में हुआ सफल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार इस बात की संभावनाओं को खंगाल रही है कि क्या इस कानून को जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही लागू किया जा सकता है।

संविधान संशोधन की आवश्यकता : वर्तमान कानून यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे सितंबर 2023 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, में यह प्रविधान है कि आरक्षण केवल परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। यदि सरकार इसे परिसीमन से पहले लागू करने का निर्णय लेती है, तो उसे संसद में एक और संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा। हालांकि अभी कैबिनेट के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है, लेकिन अनौपचारिक स्तर पर विपक्ष के नेताओं से इस बारे में चर्चा की खबरें आ रही हैं।

परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसके लिए एक 'तटस्थ' परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके निर्णयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जानकारों का मानना है कि चुनाव आयोग एक या दो राज्यों (जैसे हाल ही में असम) का परिसीमन तो कर सकता है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर यह जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की ही होती है।

सीटों के निर्धारण के लिए 'रोटेशन' का विकल्प : परिसीमन के बिना सीटों का आरक्षण तय करना एक बड़ी चुनौती है। इसके विकल्प के रूप में 'रोटेशन प्रणाली' पर विचार किया जा सकता है। 1990 के दशक के मध्य में गीता मुखर्जी समिति ने सुझाव दिया था कि हर चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। इस चक्र के अनुसार, तीन आम चुनावों के बाद देश के सभी निर्वाचन क्षेत्र कम से कम एक बार महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाते। हालांकि, 2023 में पारित मौजूदा कानून में रोटेशन का प्रविधान शामिल नहीं है।

उल्लेखनीय है कि यह आरक्षण लागू होने के बाद 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिसे संसद बाद में बढ़ा सकती है। वर्तमान में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं के लिए उप-कोटा (कोटा के भीतर कोटा) है, लेकिन विपक्ष इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहा है। महिला आरक्षण का प्रयास 1996 से चल रहा था, जो अंततः 2023 में सफल हुआ। यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी और त्वरित कदम साबित होगा।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

37 कांग्रेस विधायकों में से 32 ने ही भाग लिया विधायक दल की चंडीगढ़ में सोमवार रात को हुई बैठक में। इस बात चिंतित शीर्ष नेतृत्व ने विधायकों की 13 मार्च को रात्रिभोज पर फिर से मीटिंग बुलाई है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 11 मार्च, 2026

राहुल ने खुद माना-वही थे एआइ समिट में नग्न प्रदर्शन के आर्किटेक्ट : भाजपा

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर भाजपा का करारा पलटवार

पात्रा बोले- जैसे गद्दार अपने देश के खिलाफ घटनाओं पर मुस्कुराता है, राहुल के चेहरे पर वैसी मुस्कान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले दिनों एआइ इंपैक्ट में यूथ कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर व्यंग्यात्मक लहजे में बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर आ गए हैं।

सांसद एवं भाजपा प्रवक्ता डा. संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि एआइ समिट में कांग्रेस के नग्न प्रदर्शन के आर्किटेक्ट और डिजाइनर राहुल गांधी ही थे। साथ ही दावा किया कि इसका षड्यंत्र सिर्फ राहुल गांधी के निवास पर ही नहीं रचा गया, बल्कि यह योजना जार्ज सोरोस के गैराज से होकर नेता प्रतिपक्ष तक पहुंची है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार एक गद्दार अपने ही देश के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर मुस्कुराता है, वैसी ही मुस्कान राहुल के चेहरे पर दिखाई दी।

डा. संबित पात्रा। फाइल

डा. संबित पात्रा ने मंगलवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मंच से एक भाषण दिया, जिसमें उनका व्यवहार बेहद आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, "लोग कहते हैं एआइ, आपने भी सुना होगा एआइ। यहां अभी समिट हुआ था, यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम।"

इस बयान की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि जिस प्रकार की कुटिलता भरी मुस्कुराहट और अहंकार से भरा भाव राहुल गांधी के चेहरे पर था और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे वाक्य को प्रस्तुत किया, वह बेहद चिंताजनक है।

भाजपा ने दावा किया कि प्रदर्शन के बाद आरोप लगाया गया था कि इस कृत्य की योजना में राहुल गांधी की मुख्य भूमिका है और अब नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं यह स्वीकार किया है- 'हां, हमने काम कर दिया।'

सांसद एवं भाजपा प्रवक्ता डा. संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लफंगई और नेतृत्व में बड़ा अंतर होता है। कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार से स्वयं को नेता साबित नहीं कर सकता। भाजपा सांसद ने कहा कि यह दुखद है कि न तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी में शिष्टाचार है और न ही मर्यादा, फिर भी वे स्वयं को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बताते हैं। उन्हें यह याद दिलाया जाना चाहिए कि वे भारत जैसे महान लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष बनने के योग्य नहीं हैं।

गौरतलब है कि एआइ समिट में युवा कांग्रेस के सदस्यों के आपत्तिजनक प्रदर्शन पर खुद कांग्रेस बचाव करने से बच रही थी। लेकिन तब राहुल गांधी चुप थे। अब परोक्ष रूप से समर्थन ही कर दिया।

बंगाल में आठ दिन की 'परिवर्तन यात्रा' संपन्न

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : बंगाल में भाजपा की आठ दिवसीय 'परिवर्तन यात्रा' मंगलवार को संपन्न हो गई। एक और 2 मार्च को शुरू हुए इस महाभियान में होली के अवकाश को छोड़कर कुल आठ दिनों तक भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देशभर से आए दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिग्गज नेताओं ने बंगाल की सड़कों पर पसीना बहाया। कार्यक्रम के समापन के साथ ही अब पार्टी के भीतर उपलब्धियों और कमियों का लेखा-जोखा शुरू हो गया है। हालांकि इस परिवर्तन यात्रा का औपचारिक समापन 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान की विशाल जनसभा से होगी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा से पहले ही इस यात्रा ने 'वार्म-अप' का काम किया है। भाजपा लगभग हर जिले और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। इस दौरान पोस्टर, बैनर और जनसभाओं के जरिए पार्टी की 'विजिबिलिटी' (दृश्यता) में भारी इजाफा हुआ। रणनीतिकारों के अनुसार, इस यात्रा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर किया है।

बधाई हो, सीएम पद के लिए आपका नाम सबसे आगे चल रहा

अरुण अशेष ● जागरण

- बिहार में भाजपा के कई विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को मिल रही बधाई
- गंभीर दावेदार बधाई मिलते ही मांगने लगते माफी-ऐसा मत बोलिए लोग पीछे लग जाएंगे

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की घोषणा के तुरंत बाद का पहला प्रश्न- कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सही उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन, राजनीतिक गलियारे में इसका उत्तर अलग ही अंदाज में मिल रहा है।

भाजपा के शायद ही ऐसे कोई विधायक, विधान पार्षद और संसद के दोनों सदनों के सदस्य हों, जिन्हें यह संदेश न मिला हो- बधाई हो, आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। कई पूर्व विधायक भी इस कतार में लगा दिए गए हैं।

इंटरनेट मीडिया अपना कमाल अलग दिखा रहा है। इस प्लेटफार्म पर जिला और विधानसभा स्तर पर मुख्यमंत्री तय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के गंभीर दावेदार बधाई मिलते ही माफी मांगने लगते हैं-ऐसा मत बोलिए। लोग पीछे लग जाएंगे।

यह स्थिति इस धारणा के कारण पैदा हुई कि भाजपा कभी किसी को कहीं से उठाकर कहीं बिठा देती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा है, जहां के मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक हैं।

एक जिले में कई मुख्यमंत्री : इंटरनेट मीडिया पर एक ही जिले में कई नेताओं

को अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही हैं। दरभंगा में पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर और पहली बार राज्यसभा में गईं धर्मशीला गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।

इसके पड़ोसी मधुबनी जिले में तो भाजपा के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी हो रही है। क्यों? इसलिए कि उनकी छवि कट्टर हिंदू की है।

पूर्व मंत्री और पांचवीं बार विधायक बने नीतीश मिश्रा को भी भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है।

महिला मुख्यमंत्री : बधाइयां जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर भी दी जा रही हैं। महिला सशक्तीकरण की एनडीए की नीति के हवाले से दूसरी बार विधायक और पहली बार मंत्री बनीं श्रेयसी सिंह और रमा निषाद की चर्चा हो रही है तो कई बार विधायक रहीं गायत्री देवी को बधाई देने वाले भी कम नहीं हैं। उपमुख्यमंत्री रहीं रेणु देवी पीछे चल रही हैं।

अति पिछड़े हैं आगे, सवर्ण भी निराश नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश को अति पिछड़े प्रिय हैं। इंटरनेट मीडिया की चर्चा में यह कोण भी है। इस श्रेणी में विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार और संजीव कुमार चौरसिया को सबसे अधिक बधाई मिल रही है। प्रेम कुमार नौवीं और चौरसिया तीसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार विधान पार्षद और सहकारिता मंत्री बने डा. प्रमोद कुमार चंद्रवंशी को बधाई देने वाले भी कम नहीं हैं। ये संघ और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि के हैं। इंटरनेट मीडिया पर सवर्ण कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद राजीव प्रताप रूडी, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल सहित कई अन्य नाम चल रहे हैं।

मप्र में भाजपा के नेता संगठन को आर्थिक सहयोग करने में दिखा रहे अरुचि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

- अनुमानित 50 करोड़ रुपये के मुकाबले 10 करोड़ रुपये ही एकत्र कर पाया संगठन

मध्य प्रदेश में दो दशक से सत्तारूढ़ भाजपा के नेता संगठन को आर्थिक सहयोग करने में अरुचि दिखा रहे हैं। इस वजह से भाजपा का आजीवन सहयोग निधि यानी समर्पण निधि अभियान इस वर्ष लड़खड़ा गया है। इसका एक बड़ा कारण पूरी तरह डिजिटल या आनलाइन भुगतान अनिवार्य करना भी बताया जा रहा है। जनसंघ के समय से चले आ रहे इस अभियान की शुरुआत प्रदेश में पार्टी के पितृ पुरुष स्व. कुशाभाऊ ठाकरे ने की थी। इसे प्रतिवर्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि (11 फरवरी) के अवसर पर शुरू किया जाता है। एक महीने के बाद भी इस अभियान में मात्र 10 करोड़ रुपये की राशि एकत्र हो पाई है। पार्टी ने कोई लक्ष्य तो निर्धारित नहीं किया था लेकिन संगठन को इस वर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र होने की आशा थी। 28 फरवरी को समाप्त होने वाले इस अभियान को पार्टी ने 15 मार्च तक

आगे भी बढ़ाया है। बता दें, पहले विधायक और सांसद स्वेच्छा से एक माह का वेतन समर्पण निधि में दिया करते थे। वर्ष 2025 में इसमें 25 करोड़ रुपये एकत्र हुए थे।

समर्पण निधि अभियान में पार्टी ने इस वर्ष दो बड़े परिवर्तन किए हैं। एक तो यह कि सहयोग निधि सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही ली जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई प्रश्न नहीं उठा पाए। दूसरा यह कि 20 हजार रुपये से अधिक सहयोग निधि देने वालों का पैन नंबर भी लिया जा रहा है। एकत्रित राशि का बंटवारा संगठन के विभिन्न स्तरों पर इसके संचालन और मजबूती के लिए किया जाता है। पार्टी नेताओं के अनुसार एकत्रित और वितरित की गई राशि का आडिट करवाया जाता है। इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है।

> देश के कई राज्यों में समर्पण निधि अभियान समाप्त कर दिया गया है लेकिन मध्य प्रदेश में जारी है। आडिट के कारण केवल आनलाइन धनराशि स्वीकार की जा रही है। विधायक-सांसदों पर भी कोई दबाव नहीं है। जो स्वेच्छा से देंगे, वही हमें स्वीकार है।
> **- गोपी कृष्ण नेमा, प्रदेश प्रभारी, समर्पण निधि अभियान, भाजपा**

विधायक जी, कहां हो, आपके साथ चाय पीनी है...!

अनुराग अग्रवाल ● जागरण

- राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा के रणनीतिकार डाल रहे कांग्रेस विधायकों पर डोरे
- भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद चुनाव तक अपने विधायकों के साथ चंडीगढ़ में जमे
- केंद्रीय मंत्री मनोहर, सीएम नायब सैनी और पर्यवेक्षक हर्ष सांघवी ने भी संभाला मोर्चा

चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों पर 16 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस नेताओं ने चंडीगढ़ में डेरा डाल लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद जहां चुनाव होने तक कांग्रेस विधायकों के साथ पूरे समय चंडीगढ़ में जमे रहेंगे, वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक हर्ष संघवी भी चंडीगढ़ पहुंच गये हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर हरियाणा भाजपा के प्रभारी डा. सतीश पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली लगातार न केवल अपनी पार्टी के विधायकों के संपर्क में हैं, बल्कि कांग्रेस विधायकों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने हालांकि दावा किया है कि किसी विधायक ने उनके साथ भाजपा द्वारा संपर्क साधे जाने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए योजनाबद्ध तरीके से रणनीतिकार तैयार किए हैं। भाजपा ने पहले यह चिह्नित किया कि कांग्रेस का कौन सा विधायक भाजपा के किस नेता के करीब है। यह चिह्नित करने के बाद भाजपा के रणनीतिकारों द्वारा कांग्रेस विधायकों को फोन कर पूछा जा रहा है...विधायक जी, आप कहां हैं...आपके साथ चाय पीनी है...आप चाहो तो हमारी चाय पी लो या फिर हमें चाय पीने के लिए बुला लो। कांग्रेस के कुछ विधायक अपने भाजपाई मित्रों के साथ थोड़ी-थोड़ी चाय पी भी चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हालांकि अपनी पार्टी के विधायकों पर पूरा भरोसा है, इसलिए ही उन्होंने किसी भी विधायक को कर्नाटक अथवा हिमाचल की यात्रा पर जाने से रोक दिया है। सोमवार की रात को चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने हिमाचल अथवा कर्नाटक समेत विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने की इच्छा जाहिर की थी। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी चाहते थे कि विधायक घूम आएं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट कह दिया कि हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है और कोई विधायक चंडीगढ़ से बाहर नहीं जाएगा।

चंडीगढ़ पहुंचे गुजरात के डिप्टी सीएम व रास चुनाव के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी की अगुवानी करते सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी व खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम। जागरण

खेला होने में भाजपा की हैट्रिक नहीं बनने देना चाहती कांग्रेस

भाजपा की राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने की वजह से हरियाणा में दो सीटें खाली हो रही हैं। इन दो सीटों के लिए तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के एक उम्मीदवार संजय भाटिया का राज्यसभा जाना तय है, जबकि कांग्रेस के हिस्से की दूसरी सीट पर पार्टी ने कर्मवीर बौद्ध को मैदान में उतारा है। इसी सीट के लिए भाजपा ने अपनी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल को खड़ा किया है। पिछले दो राज्यसभा चुनाव में भाजपा खेला कर चुकी है। इस बार फिर कांग्रेस के हिस्से की सीट पर खेला करने की भाजपा की तैयारी है, इसी आशंका से कांग्रेस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है।

राष्ट्रीय फलक

एक दशक पहले भी मुर्मु के दौरे पर बंगाल में फंसा था 'अनुमति' का पेच

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- 2015 के संताली लेखक सम्मेलन में तत्कालीन राज्यपाल मुर्मु के हेलीकाप्टर लैंडिंग में हुई थी दुश्वारी

उत्तर बंगाल में संताल संगठन के कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की टिप्पणियों पर छिड़े विवाद के बीच अब जंगलमहल में एक दशक पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। नवंबर 2015 में झाड़ग्राम शहर के बाहरी इलाके बेतकुंद्री मैदान में आयोजित संताली साहित्य सम्मेलन में झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मु शामिल हुई थीं। उस समय भी प्रशासनिक अनुमति पर जटिलता पैदा हुई थी।

6-8 नवंबर 2015 को बेतकुंद्री मैदान में 'आल इंडिया संताली राइटर्स एसोसिएशन' का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सात नवंबर को द्रौपदी मुर्मु को रांची से हेलीकाप्टर द्वारा पहुंचना था। सम्मेलन स्थल के पास हेलीकाप्टर उतारने की अनुमति के लिए प्रशासन से बार-बार आवेदन किया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अंततः उनका हेलीकाप्टर रांची से कलाईकुंडा वायुसेना बेस पर उतरा, जहां से उन्हें सड़क मार्ग द्वारा कार से बेतकुंद्री मैदान पहुंचना पड़ा था। उस संगठन के वर्तमान अखिल भारतीय अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू, जो 2015 में सम्मेलन के संयुक्त संयोजक थे, ने कहा कि उस समय प्रशासन के असहयोग से हमें बहुत दुख हुआ था। प्रशासन ने उस समय अनुमति क्यों नहीं दी, इसका कोई आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिले में तत्कालीन कार्यरत एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह उस समय भी भाजपा द्वारा मनोनीत राज्यपाल थीं, इससे अधिक कुछ कहना संभव नहीं है।

सेना को आधुनिक बनाने का रोडमैप तैयार

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'विजन 2047: ए रोडमैप फार अ फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री' जारी किया
- इसमें आवश्यक रणनीतिक सुधारों, क्षमता संवर्धन और संगठनात्मक परिवर्तनों की व्यापक रूपरेखा है

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना को आधुनिक, बहु-आयामी और एकीकृत बल में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन डाक्यूमेंट जारी किया। 'डिफेंस फोर्सेस विजन 2047: ए रोडमैप फार अ फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री' नामक यह डाक्यूमेंट एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष (2047) तक सशस्त्र बलों को दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बनाना है। यह रोडमैप पिछले वर्ष मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के आठ महीने बाद आया है।

स्वदेशी तकनीक पर व्यापक जोर : इस विजन डाक्यूमेंट का एक केंद्रीय स्तंभ सेना के तीनों अंगों के बीच 'ज्वाइंटनेस' और तालमेल को बढ़ावा देना है। इसके तहत योजना, संचालन और क्षमता विकास में अधिक समन्वय पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सेना को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डाक्यूमेंट में नवाचार, अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक प्रशिक्षण ढांचे के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य एक ऐसा बल तैयार करना है जो भविष्य के युद्धों की चुनौतियों के प्रति अनुकूल हो। साथ ही, रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' को बढ़ावा देना इस विजन का प्रमुख हिस्सा है, ताकि देश की विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार स्वदेशी समाधान विकसित किए जा सकें।

'डिफेंस फोर्सेज विजन 2047' का विमोचन करते (बाएं से) रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह। एएनआइ

तीन चरणों में क्षमता का विकास : विजन डाक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक समय सीमा के भीतर सैन्य क्षमताओं के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी गई है। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं के विकास, संस्थागत सुधारों और रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन करेगा।

बयान से पलटी साली, बोली-सपने में छेड़ा था, 7 साल बाद जीजा बरी

जागरण संवाददाता, कानपुर

- एयरफोर्स कर्मी के खिलाफ दर्ज कराई थी छेड़खानी की रिपोर्ट-19 दिन जेल में रहना पड़ा था, जमानत पर था आरोपित

एयरफोर्स कर्मी जीजा पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली नाबालिग साली कोर्ट में मुकर गई। कहा कि जीजा ने सच में नहीं, सपने में छेड़खानी की थी। मुझे भ्रम हो गया था। इस पर कोर्ट ने सात साल पहले दर्ज मुकदमे में एयरफोर्स कर्मी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में एयरफोर्स कर्मी को 19 दिन जेल में रहना पड़ा था।

बिठूर निवासी एयरफोर्स कर्मी का विवाह 10 फरवरी 2019 को बिधनू की युवती से हुआ था। 13 फरवरी को एयरफोर्स कर्मी पत्नी को लेने ससुराल गया तो 15 वर्षीय साली भी उसके साथ आ गई। आठ मार्च 2019 की रात साली जोर-जोर से चिल्लाने लगी। बहन कमरे में पहुंची तो साली ने आरोप लगाया कि जीजा ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। बहन ने पुलिस बुला ली। पारिवारिक मामला होने पर पहले तो समझौते की कोशिश हुई पर बात न बनने पर पिता ने तीन अगस्त 2019 को नौबस्ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। 29 सितंबर 2019 को एयरफोर्स कर्मी की गिरफ्तारी हो गई और 19 दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 2019 को जमानत पर उसकी रिहाई हुई। अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि अपर जिला जज की कोर्ट में साली बयान देने में मुकर गई। उसने कहा कि वह दवा खाकर सोई थी। उसे भ्रम हो गया था। ऐसा सपना देखा था कि जीजा छेड़खानी कर रहे हैं। इसके बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी थी। पीड़िता की बड़ी बहन और पिता ने भी भ्रमवश मुकदमा लिखाने की बात न्यायालय में कहीं।

हर पांच साल में पति बदल देता है पत्नी, बना रहा चौथी शादी की योजना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का मामला, जनसुनवाई में महिला ने लगाए गंभीर आरोप

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति को हर पांच साल में पत्नी बदलने की आदत है और वह अब चौथी शादी करने की योजना बना रहा है। विवाह विच्छेद के बिना पुनर्विवाह की कोशिश कर रहे पति को महिला आयोग ने कड़ा संदेश दिया है। आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सतर्क रहने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

संभाग स्तरीय सुनवाई के दौरान कोरबा जिले की एक महिला ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। आवेदिका ने बताया कि उसका पति विवाह विच्छेद किए बिना चौथी शादी करने की योजना बना रहा है। उसने यह भी कहा कि उसके पति की आदत रही है कि वह हर पांच साल के अंतराल पर अपनी जीवनसाथी बदल लेता है। वर्तमान में दोनों के बीच चार अलग-अलग कानूनी मामले अदालत में लंबित हैं, लेकिन विवाह विच्छेद की डिक्री अभी तक पारित नहीं हुई है।

महिला आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि चूंकि दोनों विधिवत पति-पत्नी हैं, इसलिए पति की प्रस्तावित शादी पूरी तरह अवैध है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि वह विवाह का प्रयास करता है, तो कोरबा के संरक्षण अधिकारी और पुलिस विभाग के माध्यम से शादी पर तत्काल रोक लगाई जाए।

मरते दम तक जेल में रहेगा तीन वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का दोषी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : यूपी के शाहजहांपुर में तीन वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले संजय का पूरा जीवन सलाखों के पीछे बीतेगा। डेढ़ वर्ष पूर्व बच्ची का घर से अपहरण कर उसके साथ घिनौना कृत्य करने में वह दोषी साबित हुआ। पांच नवंबर 2024 को रात तीन बजे एक व्यक्ति की तीन वर्षीय बेटी गायब हो गई। पति-पत्नी ने तलाश की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। सुबह छह बजे गांव से 500 मीटर दूर नलकूप के पास बेटी बेहोश मिली। कपड़े अस्त-व्यस्त होने के साथ ही प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उन्होंने राजाराम नाम के व्यक्ति पर शक जताया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे। पुलिस ने बच्ची को कुछ अन्य लोगों के फोटो दिखाए तो उसने संजय उर्फ संजू को पहचान लिया।

मतांतरण के लिए हिंदुओं पर दवाब बनाता था मुतवल्ली, पद से हटाया गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर

- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की घटना, आरोपित देता था नौकरी से निकलवाने की धमकी
- खुद को 22 जमात का सदर बताता था आरोपित, मुस्लिमों का भी कर रहा था शोषण

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मुतवल्ली (वक्फ के प्रबंधक) अल्तमस सिद्दिकी पर हिंदू परिवारों पर मतांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवारों ने मुतवल्ली की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में की है। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने मुतवल्ली को पद से हटा दिया है, साथ ही एफआइआर दर्ज करवाने के लिए राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। पीड़िता स्मिता वाल्देकर ने आरोप लगाया है कि आरोपित उन पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाते हुए अपना नाम 'फातिमा' रखने को कहता था। उसने धमकी दी थी कि यदि उसकी बात नहीं मानी, तो दो दिन में नौकरी से निकलवाकर जेल भिजवा देगा।

> अल्तमस सिद्दिकी द्वारा दादागिरी की जा रही है। हिंदू भाइयों पर मुसलमान बनने का दबाव बनाया जा रहा है। शिकायत के बाद मुतवल्ली को पद से हटा दिया गया है। गृहमंत्री को पत्र लिखा है। अल्तमस पर केस दर्ज कराएंगे।
> **डा. सलीम राज, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड**

वहीं, मुस्लिम परिवारों ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डा. सलीम राज को दिए गए लिखित ज्ञापन में बताया कि अल्तमस सिद्दिकी स्वयं को '22 जमात' का सदर बताता है और पिछले तीन-चार वर्षों से कुछ सुन्नी मुस्लिम परिवारों पर दबाव बनाकर अपनी मान्यता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जब कई परिवारों ने उसे सदर मानने से इन्कार कर दिया, तो उसने करीब 25 परिवारों को समाज से जबरन बहिष्कृत कर दिया। इन परिवारों का आरोप है कि बहिष्कार के बाद उन्हें कब्रिस्तान, मस्जिद, निकाह, शादी-विवाह और सामूहिक दावत जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, इन परिवारों के साथ रोटी-बेटी के रिश्ते भी समाप्त कर दिए गए, जिससे वे भय और दबाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। पीड़ित पक्ष के लोगों ने कहा कि अल्तमस की शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 13 से

जागरण संवाददाता, पानीपत: हरियाणा में समालखा के पट्टीकल्याणा में 13 से 15 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। बैठक में 2025-26 के संघ के कार्यों की समीक्षा व प्रांतों में हुए विशेष कार्यों पर मंथन किया जाएगा। इस दौरान वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

शुक्रवार से शुरू होने वाली बैठक को सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले संबोधित करेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं और बैठक स्थल माधव सृष्टि के अंदर संघ के अलावा केवल व्यवस्था में जुटे कर्मचारियों व अधिकारियों को ही आने-जाने दिया जा रहा है।

40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया मंगलवार को मुंबई में दिन का तापमान। पिछले साल (2025(के इस दिन के सामान्य तापमान से 7.6 डिग्री अधिक है। आइएमडी ने मुंबई के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है।

एलपीजी की किल्लत, गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी

जागरण टीम, नई दिल्ली

- यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी कतारें
- कई जगह मंदिरों ने लकड़ी व कोयले के उपयोग से भोजन पकाने का लिया निर्णय

50 हजार से अधिक रेस्तरां दिल्ली में, पब, बार और होटलों का संचालन प्रभावित

नई दिल्ली में मंगलवार को साइकिल पर डिलीवरी के लिए एलपीजी सिलेंडर लेकर जाता एक कर्मचारी। रायटर >>

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में एलपीजी की किल्लत होने लगी है। गैस सिलेंडर भरवाने को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कई जगह घरेल आपूर्ति तो अभी सामान्य है, लेकिन वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों को लेकर परेशानी बढ़ रही है। यह स्थिति इसलिए भी है कि लोग आशंका में पहले से ही गैस सिलेंडर भरवाकर जमा करने लगे हैं। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित होने से दिल्ली में 50 हजार से अधिक रेस्तरां, पब, बार और होटलों के संचालन में दिक्कतें आने लगी हैं। अयोध्या में वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कमी के कारण राम नगरी में मंगलवार को नियमित शाम तीन बजे तक चलने वाली राम रसोई मंगलवार को दो बजे ही बंद करनी पड़ी। कई जगह मंदिरों ने लकड़ी और कोयले के उपयोग से भोजन पकाने का निर्णय लिया है।

आल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर फेडरेशन (एआइएलडीएफ) के कार्यकारी अध्यक्ष पीएन सेठ के अनुसार यह दिक्कत कुछ दिन के लिए ही है। रूस से आपूर्ति शुरू होते ही समस्या खत्म हो जाएगी। उधर, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआइ), दिल्ली के अध्यक्ष संदीप आनंद गोयल ने कहा कि व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बंद हो गई है। पीएनजी पाइप लाइन में भी गैस का दबाव 20 प्रतिशत कम कर दिया गया है।

हरियाणा के कई जिलों में पिछले दो-तीन दिनों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। राज्य के कई जिलों में एजेंसियों तक नई खेप नहीं पहुंचने की सूचना है। कई स्थानों पर एजेंसियां पुराने स्टाक से सीमित सिलेंडर दे रही हैं। इन दिनों विवाह समारोहों और सामाजिक आयोजनों के कारण मांग सामान्य दिनों से अधिक बनी हुई है।

पंजाब में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई जिलों में गैस एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई मिलनी बंद हो गई है। जालंधर के होटल संचालकों का कहना है कि अगर सिलेंडर की सप्लाई नहीं होती है तो मजबूरी में कमर्शियल इंडक्शन पर काम चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ राज्य में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति रोक दी गई है। घरेलू एलपीजी की बुकिंग भी बढ़ गई है।

कोलकाता में 2000 रेस्तरां का संचालन प्रभावित

कोलकाता समेत बंगाल में उद्योग संघों ने चेतावनी दी है कि यदि ईंधन की आपूर्ति जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ेगी। नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआइ) की कोलकाता शाखा के प्रमुख पीयूष कंकारिया ने बताया कि शहर में लगभग 5,000 रेस्तरां हैं। इनमें लगभग 40 प्रतिशत यानी लगभग 2000 रेस्तरां के संचालन में तत्काल व्यवधान देखा जा रहा है।

कम होने से बढ़ी कालाबाजारी

जम्मू में गैस कंपनियां किसी भी तरह की किल्लत से इन्कार कर रही है। हालांकि, जमीनी स्तर पर व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता कम होने से कालाबाजारी शुरू हो गई है। गत दिनों इसके दाम में बढ़ोतरी होने के बाद से ही व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कुछ क्षेत्रों में कमी देखने को मिल रही है।

व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक, अस्पताल को राहत

उत्तराखंड शासन ने सभी जिलों में अस्पताल व शिक्षण संस्थानों को छोड़ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी है। इससे अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों के अलावा बैंक्वेट हाल संचालक परेशान हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को भी अब 25 दिन में दूसरा सिलेंडर मिलेगा।

कच्चे तेल की कीमतों मे भारी गिरावट से सरकार ने ली राहत की सांस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फिलहाल पेट्रोल व डीजल के महंगे होने के आसार नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड कीमतों की लगातार निगरानी

पश्चिम एशिया की संकट से घरेलू बाजार में पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में वृद्धि की संभावना फिलहाल टलती नजर आ रही है। वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एक दिन में 118 डालर प्रति बैरल से घट कर 88 डालर प्रति बैरल तक आ गई हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों का आकलन है कि फिलहाल कच्चे तेल की कीमतों के उस स्तर पर पहुंचने के आसार नहीं है कि घरेलू कीमतों को बढ़ाने की तत्काल नौबत आए। मंत्रालय के मुताबिक कुछ समय तक क्रूड की कीमतें 120 डालर से ऊपर बनी रहती हैं तब ही पेट्रोल व डीजल को महंगा करने की जरूरत होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हालात की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया हुआ है।

मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत के प्रतिनिधि ना सिर्फ तेल उत्पादक देशों के संगठन के साथ संपर्क में हैं बल्कि क्रूड कारोबार से जुड़ी तकरीबन सभी बड़ी कंपनियों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। भारत तकरीबन 40 देशों से कच्चे तेल की खरीद करता है और अभी विभिन्न तरीकों से इन सभी देशों के साथ संवाद चल रहा है। यहीं वजह है कि होर्मुज जल मार्ग के 10 दिनों से बंद होने के बावजूद तेल रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक काम कर रही हैं। भारत जितना तेल वैश्विक बाजार से आयात करता है उसका 40% हिस्सा होर्मुज जल मार्ग से आता है। लड़ाई की वजह से यह मार्ग अवरुद्ध है। तकरीबन सभी तेल आयातक एशियाई देशों की सरकारों ने कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की वजह से एहतियातन तेल उपभोग घटाने के लिए कदम उठाए हैं। सूत्रों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि रूस से भारत को तेल की आपूर्ति तेज हो चुकी है। भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की थी लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से फरवरी माह में खरीद काफी कम हो गई थी।

पूरी तरह हिंसा व भय मुक्त होंगे बंगाल विधानसभा चुनाव : मुख्य चुनाव आयुक्त

सीईसी ज्ञानेश कुमार की नेताओं को सख्त चेतावनी, वोटरों को धमकाया तो खैर नहीं

कहा- बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को नहीं करेंगे बर्दाश्त, पात्र मतदाता का नहीं कटेगा नाम

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

कोलकाता में मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (मध्य में), चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू (बाएं) और विवेक जोशी (दाएं)। प्रेट्र

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ (फुल बेंच) द्वारा बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की लगातार दो दिनों तक गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों को आश्वस्त किया कि विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंसा और भय रहित वातावरण में संपन्न होंगे। राजनीतिक दलों और नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आयोग किसी भी स्तर पर मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मी को डराने-धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर आयोग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य में किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल या नेता के दबाव में काम करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मतदाता भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सकें, इसके लिए पूरे राज्य भर में सूक्ष्म तरीके से केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने कोलकाता में रूट मार्च शुरू कर दिया है। शुरुआत में केंद्रीय बलों की 240 कंपनियां पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 30 कंपनियां कोलकाता में तैनात हैं।

सौ वर्ष के 6000 मतदाता

चुनाव आयुक्त ने बताया कि बंगाल में 6,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं, जो सौ वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। वहीं, 18-19 वर्ष आयु के 5.23 लाख नए वोटर पहली बार मतदान करने के पात्र होंगे। राज्य में लगभग 1.31 करोड़ मतदाता 20 से 30 वर्ष के बीच के हैं। लगभग 3.78 लाख मतदाता, जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है।

सभी मतदान केंद्रों की 100 प्रतिशत वेबकास्टिंग होगी

सीईसी ने कहा कि इस बार के चुनाव में राज्यभर के सभी 80,000 से अधिक मतदान केंद्रों (बूथों) पर 100 प्रतिशत लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी, ताकि दिल्ली और कोलकाता में बैठे अधिकारी सीधे मतदान प्रक्रिया पर नजर रख सकें, लगभग 61,000 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

चुनाव आयुक्त को फिर दिखाए गए काले झंडे

मंगलवार सुबह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त को वहां भी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके रविवार रात कोलकाता पहुंचने पर हवाई अड्डे के बाहर और सोमवार सुबह जब वह कालीघाट मंदिर गए, तब भी उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था।

नाम कटने के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई को ट्रिब्युनल गठित करने के आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बंगाल में एसआइआर

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शामिल होंगे हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्ति जज
- हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे चयन, आयोग निकालेगा अधिसूचना

प्रतीकात्मक

बंगाल में चल रहे एसआइआर में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दावों आपत्तियों की जांच के बाद मतदाता सूची से हटाए गए नामों के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई चुनाव आयोग के प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेंगे, बल्कि हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत न्यायाधीशों का ट्रिब्यूनल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपीलों पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्युनल गठित करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ट्रिब्यूनल के लिए न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे और चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में एसआइआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने वालों को चेतावनी दी कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये निर्देश मंगलवार को पीठ ने बंगाल में एसआइआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने ये आदेश तब दिए जब उसे बताया गया कि पिछले आदेश में कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा लोगों के दावों और आपत्तियों के बारे में दिए गए आदेश के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं करेगा, जबकि इस बारे में चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी अपीलों पर सीईओ सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह अपीलों पर सुनवाई के लिए अपीलीय ट्रिब्युनल की पीठें गठित करने के लिए हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान न्यायाधीशों का चुनाव करें। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामों का चुनाव और सिफारिश के बाद चुनाव आयोग अपीलों पर सुनवाई के लिए ऐसी अपीलीय ट्रिब्युनलों को अधिसूचित करेगा।

ममता ने पेंटिंग के जरिए आयोग पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : कोलकाता के मेट्रो चैनल पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के खिलाफ धरने पर बैठीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रतीकात्मक पेंटिंग बनाकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। ममता का आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले इस संशोधन प्रक्रिया की आड़ में वास्तविक मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जा रहे हैं।

धरनास्थल पर ममता ने एक हरे रंग के बोर्ड पर चाक और पेंट का सहारा लिया। उन्होंने बोर्ड के शीर्ष पर एसआइआर लिखा और बीच में सफेद रंग से वैनिश (गायब) शब्द अंकित किया। इसके बाद उन्होंने बोर्ड पर छोटे-छोटे अनियमित घेरे और एक नक्शानुमा आकृति बनाई, जिसे वह धीरे-धीरे सफेद रंग से मिटाती नजर आईं। यह इस बात का प्रतीक था कि किस तरह वैध मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है।

वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता ने शाम को पांच दिन से चल रहे धरने को समाप्त करने की घोषणा की। कहा कि आंदोलन को काफी हद तक न्याय मिला है और अब जब न्याय का दरवाजा खुल गया है तो फिलहाल धरना समाप्त किया जा सकता है। कहा कि जरूरत पड़ी तो मैं 50 दिन भी धरने पर बैठ सकती हूं।

'आयकर अधिकारी अपने अधिकार का इस्तेमाल विनम्रता और संयम से करें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आयकर अधिकारियों से कहा कि उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग विनम्रता, संयम और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ करना चाहिए। आयकर अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे निर्णय लें जो न्यायसंगत, प्रभावी और व्यापार प्रक्रियाओं की गहरी समझ पर आधारित हों। भरोसा जताया कि अधिकारी देश के राजस्व की सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाए रखेंगे।

उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी को सख्ती और सहयोग, अधिकार और विनम्रता तथा तकनीकी क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। ऐसा करने से न केवल कर अनुपालन मजबूत होता है, बल्कि नागरिकों का व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ता है। जटिल वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने, अवैध धन प्रवाह का पता लगाने और कारपोरेट ढांचे को समझने में आयकर अधिकारी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

असम में 40 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचे नौ-नौ हजार रुपये

- योजना के तहत चार महीनों के पांच हजार रुपये और चार हजार रुपये का बिहू बोनस एक साथ ट्रांसफर किया

हिमंत बिस्वा सरमा

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, इसका आगामी विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं

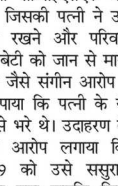

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में राज्य सरकार की 'ओरुनोदोई' (अरुणोदय) योजना के तहत मंगलवार को नौ- नौ हजार रुपये भेज दिए गए। यह राशि ऐसे समय में दी गई है, जब राज्य में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला हैं। इस चुनाव में भाजपा नीत सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता अपने पास बरकरार रखना चाहती है।

हालांकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने स्पष्ट किया कि यह "चुनाव का उपहार" नहीं है, बल्कि महिलाओं लाभार्थियों के प्रति सरकार की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो विशेष मानदंडों को पूरा करती हैं। इसका आगामी विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है।

'ओरुनोदोई' राज्य सरकार की प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है, जिसे 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत प्रति परिवार एक योग्य महिला लाभार्थी को प्रति माह 1,250 रुपये मिलते हैं।

सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, 3,600 करोड़ रुपये सीधे 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में। यह चुनाव का उपहार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की लाभार्थी हस्तांतरण योजनाओं में से एक 'ओरुनोदोई' के माध्यम से, पात्र परिवारों को 2020 से मासिक वित्तीय सहायता मिल रही है।

सरमा ने कहा, हमने चार महीनों के 'ओरुनोदोई' के लिए पांच हजार रुपये और चार हजार रुपये का बिहू बोनस एक साथ ट्रांसफर किया है। यानी कुल नौ हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

पति पर निराधार आरोप लगाना मानसिक क्रूरता : कलकत्ता हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार पर लगाए गए निराधार और गंभीर आरोप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों से न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है बल्कि अनुशासित बल में कार्यरत व्यक्ति के करियर पर भी संकट आ सकता है। पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

यह मामला सीआइएसएफ के एक जवान का है जिसकी पत्नी ने उस पर अवैध संबंध रखने और परिवार पर उनकी दूसरी बेटी को जान से मारने की कोशिश करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे। कोर्ट ने पाया कि पत्नी के ये दावे विरोधाभासों से भरे थे। उदाहरण के तौर पर पत्नी ने आरोप लगाया कि 15 फरवरी 2019 को उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया जबकि जिरह के दौरान उसने खुद स्वीकार किया कि वह दिसंबर 2018 के बाद से अपने ससुराल गई ही नहीं थी।

इंडिगो संकट के तीन महीने के बाद सीईओ पीटर एल्बर्स का इस्तीफा

- नई नियुक्ति तक कंपनी के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया संभालेंगे प्रबंधन का काम
- परिचालन संबंधी दिक्कतों के चलते डीजीसीए ने लगाया था 22 करोड़ का जुर्माना

पीटर एल्बर्स। फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र: तीन महीने पहले परिचालन संबंधी दिक्कतों का सामना करने के बाद विमानन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने मंगलवार को अचानक निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। नए सीईओ की नियुक्ति तक एयरलाइन के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया अंतरिम व्यवस्था के तहत इंडिगो के प्रबंधन का कामकाज देखेंगे।

एल्बर्स का इस्तीफा अचानक आया है। वह छह सितंबर, 2022 से इस पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने विमानन कंपनी से नोटिस पीरियड (इस्तीफे के बाद काम करने की अनिवार्य अवधि) से छूट देने का भी अनुरोध किया था। अपने इस्तीफे में डच नागरिक एल्बर्स ने कहा, 'पिछले कुछ वर्षों (सितंबर 2022 से) से सीईओ के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही है।' उन्होंने कहा, "यह विकास की एक खूबसूरत कहानी है और हमने मिलकर जो भी कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं।" उन्होंने कहा, "यदि कंपनी चाहे तो मैं किसी भी तरह के कार्यभार हस्तांतरण या बदलाव के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको और इंडिगो के बोर्ड को मुझे दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।" यह इस्तीफा तब आया है जब तीन महीने पहले एयरलाइन को बड़े पैमाने पर परिचालन संबंधी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल तीन से पांच दिसंबर के दौरान इंडिगो की 2,507 उड़ानें रद की गई थीं और 1,852 उड़ाने अपने तय समय से देर से उड़ी थीं। इससे तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए थे।

प्रबंध निदेशक ने लिखा- राहुल उर्फ मैं हूं ना : इंडिगो के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने मंगलवार को कर्मचारियों से कहा कि वह एयरलाइन के मामलों का प्रबंधन गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ करेंगे और यह भी कहा कि पिछले दिसंबर में जो हुआ वह कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक संदेश जारी किया और अंत में 'राहुल उर्फ मैं हूं ना' लिखा। 'मैं हूं ना' 2004 में रिलीज हुई शाहरुख खान अभिनीत एक बालीवुड ब्लाकबस्टर फिल्म थी।

एआइ से तैयार याचिका पर फटकार, कहा- 'जाओ कुछ स्वेटर बेचो'

- याचिका में प्रयुक्त जटिल कानूनी शब्द का अर्थ नहीं बता पाए याचिकाकर्ता
- सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा कोई भी प्रयास दंडात्मक होगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लुधियाना के एक कपड़ा व्यापारी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। व्यापारी ने याचिका का मसौदा तैयार करने के लिए एआइ का उपयोग करने की बात स्वीकार की थी और उसमें प्रयुक्त जटिल कानूनी शब्दों की व्याख्या करने में असमर्थ था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि जाओ, लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेचो, जिन लोगों का काम है ऐसी याचिका दायर करना, वो नुकसान कर देंगे, आप पर जुर्माना लगवा देंगे। जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन सहित पीठ को उस समय संदेह हुआ जब 12वीं कक्षा तक पढ़े कपड़ा व्यापारी रजनीश सिद्धू प्रधानमंत्री केयर फंड से संबंधित अपनी याचिका पर बहस करने के लिए खड़े हुए। जैसे ही सिद्धू ने लिखित पाठ पढ़कर अपनी दलीलें शुरू कीं, सीजेआइ ने उनकी शैक्षणिक और अन्य पृष्ठभूमि पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने पहले कोई याचिका दायर नहीं की थी और सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहली याचिका दायर करने आए हैं, तो सीजेआइ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, 'बड़ा बहादुरी का काम किया, सीधा लुधियाना से चलकर आ गए'।

सीजेआइ ने कहा, "मैं यहीं आपकी अंग्रेजी की परीक्षा लूंगा और अगर आप 30 प्रतिशत भी अंक प्राप्त कर लेते हैं, तो मैं मान लूंगा कि आपने यह याचिका तैयार की है।"

सुप्रीम कोर्ट का कोविड टीकाकरण के दुष्प्रभावों के लिए नो-फाल्ट मुआवजा नीति बनाने का आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कथित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव से जान गंवाने वालों के परिवारों के मुआवजा की मांग वाली याचिकाओं पर दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार को नो-फाल्ट मुआवजा बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश कोविड टीकाकरण के बाद कथित तौर पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों के मुआवजा मांगने वाली याचिकाओं पर दिए।

कोर्ट ने कहा कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के लिए नो-फाल्ट मुआवजे की नीति बनाएगी। टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी को मौजूदा तंत्र जारी रहेगा और संबंधित डेटा समय-समय पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के डाक्टर जैकब पुलियेल मामले में भी कहा था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टीके से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों की जांच के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्ति किसी नए विशेषज्ञ निकाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही निगरानी और जांच की व्यवस्था मौजूद है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि नो-फाल्ट मुआवजा नीति बनाने का मतलब यह नहीं समझा जाएगा कि केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण ने किसी गलती या जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसी नीति बनने से प्रभावित लोगों के लिए कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा लेने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने यह फैसला कोविड टीकाकरण के दुष्प्रभावों के कारण जान गंवाने वाली दो लड़कियों के माता-पिता की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनकी बेटियों की मृत्यु कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण हुई है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाने की भी मांग की थी। इसके अलावा एक अन्य याचिका केंद्र द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें केरल हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने टीकाकरण से कथित मौत के मामले में मुआवजा नीति बनाने का निर्देश दिया था।

फैशन डिजाइनर से 30 लाख की धोखाधड़ी में फंसे मप्र के एआइजी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

- पीटीआरआइ के एआइजी राजेश मिश्रा की बढ़ीं मुश्किलें

जयपुर की फैशन डिजाइनर से 30 लाख की धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश शासन ने पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआइ) के एआइजी राजेश मिश्रा को आरोप पत्र जारी किया है। उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्र बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों से महिला द्वारा लगाए गए कई आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर उन्हें आरोप पत्र थमाया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की तैयारी प्रदेश का गृह विभाग कर रहा है।

पीड़ित महिला ने 11 नवंबर 2025 को पुलिस महानिदेशक को शिकायती पत्र देकर राजेश मिश्रा पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उससे धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और पद का दुरुपयोग कर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि फरवरी 2025 में जयपुर में एक शादी समारोह में मिश्रा और उनकी पत्नी से भेंट हुई थी। इसके बाद अक्टूबर 2025 में वह पत्नी के साथ जयपुर आए। उन्होंने होटल, भोजन, ज्वेलरी आदि में उससे 30 लाख रुपये नकद और डिजिटल भुगतान में खर्च कराए फिर बातचीत बंद कर दी। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने मामले की जांच डीआइजी (गुप्तवार्ता) तरुण नायक को सौंपी थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ साक्ष्य जुटाए। लगभग दो माह पहले उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी थी।

8 मई से हल्द्वानी और नौ से धारचूला से शुरू होगी आदि कैलास व ऊं पर्वत यात्रा। श्रद्धालु निगम की वेबसाइट (www.kmvn.in) पर पंजीकरण करा सकते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 11 मार्च, 2026

राजौरी में घुसपैठ का बड़ा षड्यंत्र विफल, आतंकी ढेर

एलओसी के आसपास के जंगलों में छिपा हो सकता है दूसरा आतंकी, तलाश में अभियान जारी

घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को देना चाहते थे अंजाम

जागरण संवाददाता, राजौरी

50 आतंकी हैं सीमा पार पाक सेना व रेंजर्स की चौकियों के पास नए लांचिंग में

मारे गए आतंकी का मकसद भारत में घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था

मंगलवार को पुलवामा में बादाम के एक बाग में गश्त पर सेना का जवान। प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर मंगलवार को सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ के एक बड़े षड्यंत्र को सेना ने विफल कर दिया। इस दौरान मुठभेड़ में एक पाकिस्तान समर्थित आतंकी मारा गया और दूसरे की तलाश में एलओसी के आसपास अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार, दूसरा आतंकी आसपास के जंगलों में छिपा हो सकता है, इसलिए सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सघन सर्च आपरेशन चला रही हैं। अभियान में आधुनिक तकनीक और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

'दैनिक जागरण' ने अपने छह मार्च के अंक में पहले ही बताया था कि सीमा पार पाकिस्तानी सेना व रेंजर्स की चौकियों के पास आतंकियों के नए लांचिंग पैड बनाए गए हैं, जिनमें 50 आतंकी लाए गए हैं। इसे लेकर एक अलर्ट भी जारी किया गया था। सेना के अनुसार, मंगलवार दोपहर नौशहरा सेक्टर के झंगड़ क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई।

सैनिकों ने दो आतंकियों को देखा, जो घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर बताया कि सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। सेना ने बताया कि मारा गया आतंकी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन से जुड़ा था और उसका मकसद भारत में घुसपैठ कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। आतंकी से एक एके राइफल, तीन ग्रेनेड, दो पिस्तौल, 58 एके राइफल की गोलियां और पाकिस्तानी मुद्रा के अलावा अन्य सामान बरामद किया गया।

सेना के अधिकारियों ने बताया कि नौशहरा सेक्टर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। नियंत्रण रेखा के पास संवेदनशील इलाकों में खुफिया तंत्र को भी और सक्रिय कर दिया गया है।

40 से अधिक बारूदी सुरंगों में विस्फोट

जासं, राजौरी : एक बार फिर राजौरी जिला में एलओसी पर बालाकोट और तरकुंडी सेक्टर के बीच सीमा पार से आई आग ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। आग की चपेट में आने से अब तक 40 से अधिक बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो चुके हैं, जिसकी आवाज निकटवर्ती सीमावर्ती गांवों तक सुनी जा रही है। इन सुरंगों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि घुसपैठिये भारतीय क्षेत्र में न घुस पाएं। इसलिए पाकिस्तानी सेना और उसके पाले आतंकी संगठन सीमा पार जंगल में आग लगा देते हैं, जो हवा के साथ फैलते-फैलते भारतीय क्षेत्र तक पहुंच जाती है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क से जुड़े तीन सरकारी कर्मी बर्खास्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

- आतंकियों को हथियार, सुरक्षाबलों की रैकी सहित गतिविधियों में थे लिप्त
- तीनों जलशक्ति विभाग में अस्थायी कर्मी थे और वर्तमान में जेल में हैं बंद

सरकारी तंत्र में बैठकर आतंकियों और अलगाववादियों की मदद करने में लिप्त सफेदपोश आतंकियों पर कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को जलशक्ति विभाग के तीन कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। ये तीनों अस्थायी कर्मी थे और इस समय जेल में बंद हैं। ये आतंकियों के लिए हथियार, सुरक्षित ठिकाना, सुरक्षाबलों की रैकी और युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने सहित कई राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल थे।

मौजूदा वर्ष में यह दूसरा अवसर है, जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी इकोसिस्टम को पूरी तरह समाप्त करने के अभियान के तहत सरकारी विभागों में छिपे आतंकियों के मददगारों की सेवाएं समाप्त की हैं। इससे पहले 13 जनवरी को पांच सरकारी कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं। बीते पांच वर्ष में प्रदेश सरकार अब तक आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त 93 सरकारी कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर चुकी हैं।

जलशक्ति विभाग से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि जिन तीन

प्रतीकात्मक

कर्मियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनमें से एक शौकत जरगर जिला अनंतनाग का रहने वाला है, जबकि कौसर हुसैन और लियाकत अली जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ के रहने वाले हैं। तीनों वर्ष 2019 में पकड़े गए थे। ये आतंकियों के लिए न सिर्फ मददगार (ओवरग्राउंड वर्कर) के रूप में काम करते हुए उनके लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करते थे बल्कि उनके लिए पैसे का इंतजाम करने व हथियारों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे।

बरेली में पत्नी की पीटकर हत्या, पीठ पर लादकर श्मशान में फेंका शव

जागरण संवाददाता, बरेली: अवैध संबंध के शक में भीमसेन ने यहां अपनी दूसरी पत्नी मंजू की पीटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव पीठ पर लादकर उसे श्मशान भूमि में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पड़ोस के गांव से आरोपित को दबोचा। उसने हत्या की बात स्वीकार की है।

मजदूरी करने वाले भीमसेन की पहली पत्नी छोड़कर चली गई थी। चार साल पहले उसने मंजू को पत्नी की तरह रख लिया था। पुलिस के मुताबिक भीमसेन को मंजू पर किसी के साथ अवैध संबंध का शक था। इसलिए आए दिन झगड़ा भी होता था। सोमवार रात वह शराब पीकर आया और अवैध संबंध के शक में मंजू से झगड़ा करने लगा। झगड़े के बीच ही उसने मंजू को लाठी-डंडों और लात-घूसों से इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे भीमसेन पीठ पर उसका शव लेकर श्मशान भूमि की तरफ गया और फेंककर फरार हो गया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मंजू के शरीर पर पीटने के काफी निशान थे। हाथ के पंजे भी काले हो गए थे। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी गर्म चीज से जलाया गया हो। एक पैर भी टूटा था। उसमें काफी सूजन थी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी।

एटीएम कार्ड बदलकर 35 शहरों में खाते खाली करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा

एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते खाली करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह 35 से अधिक शहरों में वारदात कर चुका है। गिरोह के सदस्य एटीएम में फेवीक्विक लगाकर कार्ड फंसाते थे। मदद के नाम पर एटीएम कार्ड बदल देते थे। आगरा निवासी बीएसएफ के सेवानिवृत्त असिस्टेंट कमांडेंट आसिफ खान के खाते से छह माह पहले गिरोह ने 16.56 लाख रुपये पार किए थे। पकड़े गए बदमाश मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के रहने वाले हैं। इनसे विभिन्न बैंकों के 153 एटीएम कार्ड, एक लाख से अधिक रुपये, तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

आसिफ खान 13 अक्टूबर, 2025 को एटीएम से रुपये निकालने गए थे। उनका कार्ड एटीएम मशीन में फंस गया। वहां मौजूद दो युवकों ने मदद के बहाने उनका कार्ड बदल दिया। तब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह बाद

पुलिस गिरफ्त में (दाएं से) सोनू कुमार शर्मा, वैभव गोयल और आकाश त्यागी। सौ. पुलिस

जब वह दोबारा रुपये निकालने गए तो पता चला कि कार्ड बदल गया है। बैंक में जानकारी करने पर पता चला कि उनका खाता खाली हो चुका है। अलग-अलग शहरों में उनके खाते से 16.56 लाख रुपये निकाले गए थे। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य ने बताया कि एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। सोमवार रात फतेहाबाद टोल प्लाजा के पास गिरोह के सरगना सोनू कुमार (दिल्ली) और उसके साथियों वैभव गोयल (मेरठ) व आकाश त्यागी (मुजफ्फरनगर) को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने बताया कि वह बिना गार्ड वाले एटीएम पर निगाह रखते थे। वहां फेवीक्विक लगा देते थे। मशीन में जैसे ही ग्राहक कार्ड लगाता था, वह फंस जाता था। मदद के नाम पर वह कार्ड निकालकर बदल लेते थे।

सोनू पर 11 व वैभव पर दो मुकदमे दर्ज : सोनू पर गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान के शहरों के विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं। वैभव गोयल पर हापुड़ में दो मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह के सरगना सोनू कुमार शर्मा ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि अब तक कितने लोगों के एटीएम कार्ड बदल चुका है। वह महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड व बिहार के 35 से अधिक शहरों में लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों रुपये निकाल चुके हैं।

अरुणाचल में सेना का वाहन खाई में गिरा, दो सैनिकों की मौत

ईटानगर, प्रेट्र : अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरि जिले में सेना के एक वाहन के खाई में गिरने से नायब सूबेदार सहित दो जवानों की मौत हो गई।

हादसे में मारे गए सैनिकों की पहचान 56 आर्टिलरी ब्रिगेड के 908 फील्ड रेजिमेंट के नायब सूबेदार कुलवंत सिंह और उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी 18 सिख रेजिमेंट के नायक प्रदीप कुमार शर्मा के रूप में हुई है। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है।

भारतीय सेना से देर से आई रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हादसा सात मार्च को भारत-चीन सीमा के पास रेड्डी गांव के निकट उस समय हुआ जब वाहन 'आपरेशन स्नो लेपर्ड' के तहत परिचालन ड्यूटी के लिए गेलेमो से ताकसिंग जा रहा था।

अधिकारी ने बताया कि 908 फील्ड रेजिमेंट के चालक अमरजीत गुर्जर को हल्की चोटें आई हैं और उनका इलाज बोरोरुपाक स्थित फील्ड अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

पंजाब-हरियाणा में 30 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

जागरण टीम , नई दिल्ली

- तलाशी अभियान के दौरान कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली
- राजस्थान में निशाने पर पासपोर्ट आफिस और डाकघर

देश के अलग-अलग हिस्सों में कई सरकारी कार्यालयों को ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। राजस्थान में जहां मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों और डाकघरों को ये धमकियां मिलीं हैं, वहीं हरियाणा-पंजाब में स्कूलों को निशाना बनाया गया। बता दें कि मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर समेत 10 से अधिक शहरों में पासपोर्ट कार्यालयों और डाकघरों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे संदेश ई-मेल के जरिये भेजे गए थे। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, परिसरों को खाली कराया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि, तलाशी अभियान के दौरान कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

गुरुग्राम में एक बार फिर मंगलवार को 12 से ज्यादा प्रतिष्ठित स्कूलों को ई-मेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। गुरुग्राम पुलिस, डाग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी स्कूलों में गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि, कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

पंजाब में 18 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी : पंजाब के लुधियाना में 18 से अधिक स्कूलों को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरी मेल मिली। ई-मेल देखते ही स्कूल प्रबंधन ने पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डाग स्क्वाड की टीमें स्कूलों में पहुंचीं और जांच शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर कुछ स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, जबकि कई स्कूलों में सुरक्षा जांच के बाद शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षाएं करवाई गईं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक किसी भी स्कूल में संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

छत्तीसगढ़ में नए मतांतरण कानून को कैबिनेट की मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन मतांतरण रोकने के लिए नए कानून को मंजूरी दी है। यह बिल (छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026) इसी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

यदि यह कानून लागू होता है, तो स्वैच्छिक मतांतरण करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। प्रलोभन, छल-कपट या धोखाधड़ी से कराए गए मतांतरण पर 10 साल तक की जेल और भारी जुमाने का प्रविधान है। सामूहिक मतांतरण के मामले में सजा और भी कठोर होगी। मतांतरण के 60 दिनों के भीतर एक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा और प्रशासन इसकी जांच करेगा कि यह स्वेच्छा से हुआ है या नहीं। न्यायालय पीड़ित को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता है।

पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के पिता को दी जमानत

नई दिल्ली, प्रेट्र : पुणे में शराब के नशे में धुत होकर पोर्श कार चलाने वाले नाबालिग आरोपित के पिता को सुप्रीम ने जमानत दे दी है। 17 वर्षीय नाबालिग ने नशे की हालत में कार चलाते हुए दो आइटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यह घटना 19 मई, 2024 की है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने विशाल अग्रवाल को जमानत दी। उस पर नाबालिग बेटे के रक्त के नमूने बदलने की साजिश रचने का आरोप है। यह साजिश उसने इसलिए ताकि कार में सवार लोगों को 'नान अल्कोहल' रिपोर्ट आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सह-आरोपितों को राहत दी जा चुकी है। आरोपित पिछले 22 महीनों से जेल में है। निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन जमानत दी जाती है।

महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि अन्य सह-आरोपितों के साथ समानता का आधार उनके मामले में लागू नहीं होगा।

बारूद की गंध से दूर बस्तर, अब काफी की महक में खिलती है जिंदगी

अनिमेष पाल • नईदुनिया

- कभी माओवादी दस्तों का हिस्सा रहे हाथ अब हुनर और मेहनत से बना रहे जीवन

जगदलपुर : बस्तर के जंगलों में कभी जिन हाथों में बंदूक और बारूद हुआ करते थे, वही हाथ आज चाय और काफी के कप सजा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए जब फगनी उसेंडी ग्राहकों को चाय परोसती है, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि यही हाथ कभी माओवादी दस्तों संग जंगलों में लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। वर्ष 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन के दौर में 10 साल की फगनी माओवादी संगठन के संपर्क में आई।

फगनी बताती है कि ओरछा के आश्रम स्कूल में पांचवीं तक पढ़ने के बाद जब वह अबूझमाड़ के सुदूर जंगलों के बीच बसे अपने गांव डुंगा पहुंची, तो माओवादियों ने उसे अपने साथ जोड़ लिया। पहले उसे 'डाक्टर टीम' में दवाइयां देना और इंजेक्शन लगाना सिखाया गया। बाद में बोटेर गांव के रिवोल्यूशनरी पालिटिकल स्कूल (रिपोस) में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। यहां वह करीब 50 बच्चों को माओवादी विचारधारा और संगठन का इतिहास पढ़ाती थी। वर्ष 2016 में बीमारी के कारण वह मुख्यधारा में लौट आई। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लेकर अब बस्तर पंडुम कैफे में काम कर रही है। उसके साथ पदमी, कमलू और सुकालु जैसे छह अन्य आत्मसमर्पित माओवादी भी यहां काम कर रहे हैं। फगनी कहती है कि अब मैं कभी हथियार नहीं उठाना चाहती, न पुलिस के लिए और न माओवादियों के लिए॥

कभी हिड़मा की बटालियन से जुड़ा रहा मड़कम आयता अब सुकमा के तुंगल बांध में नाव चलाकर पर्यटकों को सैर कराता है। -पुलिस >>

माओवादी हिंसा
अंत का अभियान
21 दिन बाकी

बस्तर में बदलती तस्वीर

2,700 माओवादी पिछले दो वर्षों में हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे

789 आत्मसमर्पित माओवादियों को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, टेलर और ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया

589 आत्मसमर्पित माओवादी कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण ले रहे हैं

हिंसा छोड़ आत्मनिर्भरता की राह

कोंडागांव जिले के कोडलियार की रहने वाली मंगती माओवादी प्रभाव के कारण वर्ष 2015 में 16 साल की उम्र में संगठन में शामिल हो गई थी। अगले 10 वर्षों तक वह कुतुल एरिया कमेटी में काम करती रही। 2025 में अपने पति संतू उर्फ बदरू के साथ मुख्यधारा में लौट आई। आज वह अपने घर में ही सिलाई की छोटी-सी दुकान चला रही है। इसी तरह माओवादी संगठन के सबसे खतरनाक लड़ाकू दस्ते पीएलजीए बटालियन नंबर-एक का माओवादी मड़कम आयता पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण मिलने के बाद आज सुकमा के पर्यटन स्थल तुंगल बांध में नाव संचालन का काम कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा के खात्मे के लक्ष्य, सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और पुनर्वास नीति के कारण कई माओवादी अब रोजगार और सम्मान की तलाश में मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं।

जगदलपुर के बस्तर पंडुम कैफे में काफी परोसती पूर्व माओवादी फगनी उसेंडी ने की नई शुरुआत।-पुलिस

'पीड़ित एससी-एसटी है, सिर्फ इसी आधार पर एफआइआर का निर्देश देना अनिवार्य नहीं'

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि एससी-एसटी वर्ग के पीड़ित की अर्जी पर जरूरी नहीं है कि विशेष अदालत अथवा मजिस्ट्रेट एफआइआर दर्ज करने का ही निर्देश दें। कोर्ट को पहले आरोपों का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि पुलिस से विवेचना करानी है अथवा कंप्लेंट केस दर्ज कर केस आगे बढ़ाना है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने आजमगढ़ निवासी कुसुम कनौजिया की आपराधिक अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, एससी-एसटी एक्ट की धारा चार नियम पांच पुलिस अधिकारियों को एफआइआर दर्ज कर जांच करने का निर्देश देते हैं, लेकिन इससे विशेष अदालत का न्यायिक विवेकाधिकार कम नहीं होता।

अपीलार्थी ने पवन चौबे तथा चार अन्य के खिलाफ बरदह थाने में दर्ज कराए गए मामले में विशेष न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसका आवेदन 19 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया गया था।

रमजान में अल्लाह अपने बंदों पर करते हैं रहमतों की बारिश

वैसे तो साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन अल्लाह को मानने वालों के लिए साल के इन 12 महीनों में से 11 महीने तो बंदों के लिए होते हैं जबकि एक महीना जिसे रमजान कहते हैं, बंदों के लिए तोहफे के तौर पर आता है। इस महीने जो संपन्न हैं, उन्हें मौका दिया जाता है कि वे गरीबों, मजबूरों, बेसहारा, यतीमों, बेवाओं की दिल खोलकर मदद करें। इसी वजह से हमारे पूर्वज रमजान के महीने का इंतजार किया करते थे और रोजा रखने की तौफीक मांगा करते थे क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरम्यान का मामला है। जो रोजा रखता है वह तय वक्त तक न तो प्यास लगने पर पानी पी सकता है न भूख लगने पर कुछ खा सकता है। अल्लाह उसे देख रहा होता है, ऐसे में अपने बंदों की उस इबादत का अल्लाह खुद गवाह होता है और उसका मेहनताना भी अल्लाह ही तय करता है। रमजान के पहले दस दिन रहमत के होते हैं। इन दस दिनों में अल्लाह अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है जबकि इस महीने के दूसरे दस दिन जिसे दूसरा असरा कहा जाता है, अल्लाह अपने बंदों को माफ करता है, उनकी मगफिरत फरमाता है और तीसरे असरे में दोजख से निजात मिलती है, इस तरह रमजान का महीना एक पावन महीना है।

वसीम राइन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज (र)

किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी

- शादी में देसी अंदाज में राहुल का हुआ जोरदार स्वागत

<< राहुल गांधी दूध से भरा गिलास लिए हुए, साथ में तनु (दाएं)। सौ. इंटरनेट मीडिया

जागरण संवाददाता, सोनीपत

हरियाणा में गोहाना के गांव मदीना में मंगलवार को एक किसान परिवार की शादी तब खास बन गई जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसान संजय मलिक की बेटी तनु के विवाह समारोह में पहुंचे। शादी में राहुल का देसी अंदाज में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के बारे में जानकारी ली। संजय वही किसान हैं, जिनके खेत में राहुल ने ढाई साल पहले ट्रैक्टर चला धान की रोपाई की थी। किसान के परिवार की तरफ से उनको दूध के साथ चूरमा परोसा। उन्होंने महिलाओं, खेती व किसानों की समस्याओं पर भी बात की। इसके बाद मोबाइल पर बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से संजय मलिक की बेटी तनु के विवाह समारोह में पहुंचे। शादी में राहुल का देसी अंदाज में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के बारे में जानकारी ली। राहुल को खाने में बालूशाही, मिस्सी रोटी, पूड़ी, दाल, मटर पनीर की सब्जी और सलाद में टमाटर, प्याज व खीरा परोसा गया।

दौड़कर लिपटे मासूम पर मां के हाथ से गिरा गर्म दूध, गई जान

जागरण संवाददाता, कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक मासूम दौड़कर अपनी मां से लिपट गया तो इसी बीच मां के हाथ से गर्म दूध से भरा भगौना दो वर्षीय बच्चे पर गिर गया। वह गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया।

मंगल प्रसाद ने बताया कि सोमवार को वह अपने चार बच्चों में दो बेटे और एक बेटी को लेकर पड़ोस के गांव में निमंत्रण में शामिल होने गए थे। घर पर उनकी पत्नी सावित्री देवी दो वर्षीय बेटे मनु एवं जेठानी के साथ थी। रात करीब नौ बजे भगोने में दूध गर्म करके सावित्री रखने के लिए बाहर निकली। तभी बेटा मां का पैर पकड़कर लिपट गया। इससे गर्म दूध से भरा भगोना मां के हाथ से छूट गया और सारा दूध मनु के ऊपर गिर गया।

न्यायिक अधिकारियों पर सिर्फ आशंका के आधार पर नहीं चलाया जा सकता मुकदमा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा- आपराधिक प्रक्रिया को उत्पीड़न का साधन नहीं बनाया जा सकता

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पूर्व चीफ जस्टिस, एक वर्तमान हाई कोर्ट जस्टिस और राज्य की उच्च न्यायिक सेवा के कई अधिकारियों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायतों को रद कर दिया है। डिवीजन बेंच ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायपालिका और सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ केवल आशंका के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया को उत्पीड़न का साधन नहीं बनाया जा सकता।

बेंच ने यह भी कहा कि आपराधिक कानून का उपयोग किसी को परेशान करने या व्यक्तिगत शिकायतों को आपराधिक मुकदमे में बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को तलब करने के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए आपराधिक कानून को दबाव का साधन नहीं बनने दिया जा सकता।

यह मामला वर्ष 2015 की एक घटना से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता ने पति के साथ एक टोल प्लाजा पर कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उस समय शिकायतकर्ता के पति सुकमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने इस घटना की एफआइआर दर्ज की थी, हालांकि शिकायतकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, क्योंकि साजिश में न्यायिक अधिकारियों के साथ तत्कालीन चीफ जस्टिस भी शामिल थे। हाई कोर्ट ने जांच के दौरान पाया कि साजिश से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

12 बच्चे बीमार हो गए बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के बंगाली कालोनी प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार की सुबह हैंडपंप (चापाकल) का पानी पीने के बाद। कुछ बच्चे उल्टी करने लगे तो कुछ ने पेट दर्द की शिकायत की।

न्यूज गैलरी

करूर भगदड़ में विजय पूछताछ के लिए दोबारा किए गए तलब

नई दिल्ली : सीबीआइ ने टीवीके प्रमुख विजय को करूर भगदड़ मामले में 15 मार्च को दोबारा तलब किया है। एजेंसी ने जनवरी में दो बार उनसे पूछताछ की थी। नौ मार्च को अभिनेता को फिर से तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे 15 दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था। अधिकारियों के अनुसार, विजय ने राजनीतिक व्यस्तताओं का हवाला देते हुए यह भी आग्रह किया था कि पूछताछ चेन्नई या तमिलनाडु के किसी कार्यालय में की जाए। उन्होंने बताया कि सीबीआइ ने अब विजय को 15 मार्च को दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है।(प्रेट्र)

हाई कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति की जमानत याचिका खारिज की

चंडीगढ़ : पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोपों में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति रानी उर्फ ज्योति मल्होत्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोप देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे मामलों में जमानत देने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है। जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की अदालत द्वारा शनिवार को पारित आदेश की कापी मंगलवार को जारी की गई। (राब्यू, जागरण)

नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पिछले साल के पहलगाम आतंकी हमले पर इंटरनेट मीडिया पोस्ट के सिलसिले में दायर एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने इस बात पर गौर करते हुए उन्हें राहत दी कि वह अधिकारियों के समक्ष पेश हुई थीं और मामले के संबंध में अपने बयान दर्ज करा चुकी हैं। शीर्ष न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया है। (प्रेट्र)

प्रधानमंत्री ने सीआइएसएफ के स्थापना दिवस पर दी बधाई

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सीआइएसएफ के स्थापना दिवस पर सीआइएसएफ के सभी कर्मियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, स्थापना दिवस पर सीआइएसएफ के सभी कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण के लिए प्रसिद्ध, सीआइएसएफ देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआइएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दीं। (प्रेट्र)

पीएम तिरुचिरापल्ली में करेंगे कई परियोजनाओं का उद्घाटन

चेन्नई : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में लगभग 5,650 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अवसंरचना, ग्रामीण संपर्क, राजमार्ग विकास और रेलवे सेवाओं सहित प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री शाम लगभग 6:30 बजे राजग की रैली को संबोधित भी करेंगे। (प्रेट्र)

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'कंबाला' से संबंधित याचिका

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी 'कंबाला' (भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता) के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने सवाल किया कि इसे राज्य के केवल एक खास क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रखा जाए। कोर्ट पेटा)इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। (प्रेट्र)

एससी/एसटी आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' लागू करने की मांग पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा जवाब

पूर्व नौकरशाह ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रतिवादी बनाया गया

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण के भीतर 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जोयमाल्या बागची शामिल हैं, ने इस याचिका को इसी तरह की राहत की मांग करने वाली एक अन्य लंबित याचिका के साथ नत्थी कर दिया है। पूर्व नौकरशाह ज्ञानेंद्र कुमार खरे द्वारा दायर इस याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

'क्लास के भीतर क्लास' का तर्क : संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि एससी/एसटी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर को बाहर न करना "मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन" है। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय और संरचनात्मक असमानता को दूर करने के लिए एक उपचारात्मक उपाय के रूप में परिकल्पना की गई थी, इसे कभी भी स्थायी या बिना शर्त अधिकार बनाने का इरादा नहीं था।

याचिका में कहा गया है, '"क्रीमी लेयर को बाहर न करने के गंभीर राष्ट्रीय परिणाम हो रहे हैं। इससे आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के बीच नाराजगी बढ़ती है और अवसर केवल एक 'कुलीन वर्ग' के हाथों में केंद्रित हो जाते हैं।"' याचिका के अनुसार, इस कमी के कारण एससी/एसटी समुदायों के भीतर ही आंतरिक स्तरीकरण हो गया है, जिससे 'क्लास के भीतर क्लास' बन गई है। यहां तुलनात्मक रूप से उन्नत परिवार बार-बार आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जबकि सबसे वंचित तबका अभी भी हाशिए पर है।

ऐतिहासिक फैसलों का हवाला : याचिका में 'इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ' जैसे ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया गया है, जिसने ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की थी। इसके अलावा, अगस्त 2024 में 'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह' मामले में आए सात जजों की संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया गया है। उस फैसले में तत्कालीन पीठ ने स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय वर्ग नहीं हैं और उनके भीतर उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से अनुमेय है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि केंद्र और राज्य एक ऐसा तंत्र विकसित करें जो संपन्न वर्ग की पहचान कर उन्हें बाहर करे, ताकि आरक्षण का वास्तविक लाभ सबसे गरीब और जरूरतमंद सदस्यों तक पहुंच सके और राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों की वर्तमान स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बांबे हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। हाई कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया पर सरकार के विरुद्ध फर्जी और झूठे कंटेंट को रेगुलेट करने के मकसद से आइटी नियमों में 2023 के संशोधनों को रद कर दिया था और उन्हें असंवैधानिक बताया था। साथ ही इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की।

पीठ ने स्टैंड-अप कामेडियन कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और एसोसिएशन आफ इंडियन मैगजींस सहित मूल याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए। बांबे हाई कोर्ट ने 26 सितंबर, 2024 को संशोधित आइटी नियमों को रद कर दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि सरकार का इरादा कंटेंट को पूरी तरह से ब्लाक करने का नहीं, बल्कि गलत जानकारी को रेगुलेट करने का है।

'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' अध्याय पर एनसीईआरटी ने फिर मांगी माफी

- कहा- 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की सभी पाठ्यपुस्तकें वापस ले ली गई
- अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था पुस्तक पर प्रतिबंध

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनसीईआरटी ने आठवीं की पुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार पर एक अध्याय शामिल करने के लिए मंगलवार को फिर सार्वजनिक माफी मांगी। साथ ही कहा कि सभी पाठ्यपुस्तक वापस ले ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक में कहा गया था कि भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों में से हैं।

मंगलवार को एनसीईआरटी ने कहा- "नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने हाल ही में कक्षा आठवीं के लिए 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियांड' नामक सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें अध्याय चार 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' शीर्षक से था। इसमें आगे कहा गया- एनसीईआरटी के निदेशक और सदस्यों ने इस अध्याय चार के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। सभी पुस्तक वापस ले ली गई हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा इस मामले को तात्कालिक विचार के लिए उठाने के बाद एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में

प्रतीकात्मक

न्यायपालिका के बारे में "आपत्तिजनक" टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया था।

सीजेआइ ने पाठ्यपुस्तक में न्यायिक भ्रष्टाचार पर अध्याय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि धरती पर किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी अखंडता को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही शीर्ष अदालत ने सामाजिक विज्ञान की इस पाठ्यपुस्तक के आगे प्रकाशन, पुनर्मुद्रण या डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने भी पुस्तक में इस विवादास्पद अंश को शामिल करने पर दुख जताया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी रूपरेखा तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ जवाबदेही तय करने और कार्रवाई करने का वादा किया था।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार को 645 करोड़ रुपये लौटाए

- बैंक ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में दी पैसा लौटाने की जानकारी
- पिछले महीने 590 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने चंडीगढ़ की एक शाखा में हुई धोखाधड़ी से जुड़े मामले का निपटान कर दिया है और हरियाणा सरकार को 645 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं। अब इस मामले में उसे कोई और गड़बड़ी नहीं मिली है। बैंक ने पिछले महीने बताया था कि चंडीगढ़ की एक खास ब्रांच में कुछ कर्मचारियों और दूसरे लोगों ने हरियाणा राज्य सरकार के कुछ खास खातों में 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। बैंक ने मंगलवार को रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा कि 590 करोड़ रुपये के शुरुआती अनुमान के मुकाबले उसने 645 करोड़ रुपये का शुद्ध मूलधन चुकाया है जो वास्तविक अनुमान से 55 करोड़ रुपये ज्यादा है। बैंक ने कहाकि यह दावे उसी घटना से जुड़े हैं और उसी शाखा से जुड़े हैं, न कि किसी नई घटना से। कोई और दावा लंबित नहीं है। बैंक ने कहा कि वह बकाया वसूलने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। बैंक ने

प्रतीकात्मक

2026 के बाद से चंडीगढ़ शाखा या देश भर में किसी और इकाई से कोई और दावा नहीं मिला है। आइडीएफसी फर्स्ट ने कहा कि बैंक का कुल जमा बकाया स्थिर बना रहा और 28 फरवरी, 2026 तक यह 2,92,381 करोड़ रुपये था, जबकि 31 दिसंबर, 2025 तक यह 2,91,133 करोड़ रुपये था। बैंक ने उम्मीद जताई है कि आगे चलकर जमा और लोन में पुराने रुझानों के अनुसार बढ़ोतरी होगी।

बरेली में भड़के दंगे के आधा दर्जन आरोपितों की याचिकाएं खारिज

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली दंगे के आधा दर्जन आरोपितों को राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। याचीगण ने घटना से संबंधित प्राथमिकी रद कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने आरोपित आशू, अजमल राफी, मोहम्मद नईम कुरैशी, मोहम्मद मोवीन, मोहम्मद फैजान व मो. साजिद उर्फ साजिद सकलानी की याचिकाओं पर दिया है। बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि 200-250 लोगों की भीड़ में सिर्फ 28 लोगों की पहचान असंभव है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को दरकिनार कर दिया।

अभियोजन के अनुसार 26 सितंबर, 2025 को मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोग मुस्लिम युवाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के विरोध में प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग 'सर तन से जुदा' जैसा आपत्तिजनक नारा लगाने लगे।

सीबीएसई की कक्षा 12 के प्रश्नपत्र का क्यूआर कोड स्कैन करने पर बजा गाना

जागरण संवाददाता, मेरठ

- इंटरनेट मीडिया पर उठे सवालों के बीच बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण
- कहा, प्रश्नपत्र पूरी तरह विश्वसनीय, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हुआ

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12 की एप्लाइड मैथमैटिक्स की परीक्षा प्रश्नों के कारण नहीं, बल्कि प्रश्नपत्र पर छपे क्यूआर कोड की वजह से चर्चा में है। नौ मार्च को मेरठ समेत कई परीक्षा केंद्रों पर जब क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो सत्यापन की जानकारी की जगह यूट्यूब का म्यूजिक वीडियो खुल गया। यह वीडियो ब्रिटिश सिंगर रिक एस्टली का 1987 में रिलीज हुआ मशहूर गीत 'नेवर गाना गिव यू अप' से जुड़ा बताया जा रहा है।

आमतौर पर प्रश्नपत्रों पर दिया गया क्यूआर कोड उसकी प्रामाणिकता जांचने और पेपर कोड की पुष्टि के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने से परीक्षार्थियों और अभिभावकों ने व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, इंटरनेट मीडिया पर भी इस मामले को लेकर कई पोस्ट साझा की जा रही हैं। लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने मीम और मजाक के साथ लिखा कि

सीबीएसई कक्षा 12वीं एप्लाइड गणित के प्रश्नपत्र पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर खुला यह वीडियो। सो : शिक्षक

सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के बीच पूरी एक पीढ़ी को रिकरोल कर दिया। हालांकि, सभी परीक्षा केंद्रों पर ऐसा अनुभव नहीं रहा। दिल्ली-एनसीआर समेत कई केंद्रों के छात्रों का कहना है कि उनके प्रश्नपत्र पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करने पर केवल ए या क्यू जैसे साधारण अल्फाबेट मार्कर ही दिखाई दिए और कोई बाहरी लिंक नहीं खुला।

सीबीएसई ने इस मामले में मंगलवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा के प्रश्नपत्रों में कई सुरक्षा फीचर दिए गए हैं, जिनमें क्यूआर कोड भी शामिल है। बोर्ड के अनुसार, कक्षा 12 की एप्लाइड मैथमैटिक्स के कुछ प्रश्नपत्र सेट में क्यूआर कोड स्कैन करने पर यू-ट्यूब वीडियो खुलने की जानकारी सामने आई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच शंका पैदा हुई। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रश्नपत्र पूरी तरह से प्रामाणिक हैं और उनकी सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डा. संयम भारद्वाज ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

भोजशाला के 244 शिलालेखों से छेड़छाड़, रहस्य छुपाने को छेनी से मिटाए गए थे अक्षर

प्रेमविजय पाटिल ● नईदुनिया

- एएसआइ की मैसूर टीम के सर्वे से मिली चौंकाने वाली जानकारियां
- 12वीं से 16वीं सदी के शिलालेखों को नष्ट करने का हुआ था प्रयास

धार: ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर इतिहास के सबसे संवेदनशील सवालों के केंद्र में है। एएसआइ की मैसूर स्थित एपिग्राफी (पत्थरों, धातुओं, सिक्कों या लकड़ियों जैसी कठोर सतहों पर उकेरे गए प्राचीन अभिलेखों का वैज्ञानिक अध्ययन) शाखा ने 2024 के सर्वे के दौरान यहां 244 शिलालेखों का विस्तृत अध्ययन किया था। ये शिलालेख 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के हैं। इन पर नागरी लिपि में संस्कृत, प्राकृत तथा स्थानीय बोली में रचनाएं अंकित हैं। सर्वे की सबसे चौंकाने वाली बात ये हैं कि कई शिलालेखों के अक्षर जानबूझकर छेनी से मिटाए गए और उन्हें भवन के अलग-अलग हिस्सों में पुनः इस्तेमाल कर लिया गया। ये जानकारियां मप्र हाई कोर्ट में प्रस्तुत एएसआइ की रिपोर्ट में दर्ज हैं। रिपोर्ट पर 16 मार्च को सुनवाई होनी है।

याची आशीष गोयल के अनुसार, अभिलेखविदों ने रिपोर्ट में बताया है कि ये खंड कभी बड़े शिलालेखों का हिस्सा थे, जिनमें साहित्यिक रचनाएं अंकित थीं। अक्षरों को जानबूझकर मिटाना मध्यकालीन सांस्कृतिक धरोहर पर गंभीर आघात रहा। हालिया सर्वे में 50 नए शिलालेख खंड और एक टूटी हुई प्रतिमा के टुकड़े का भी परीक्षण किया गया है।

भोजशाला का एक हिस्सा। फाइल/ नईदुनिया

पारिजात-मंजरी से नागबंध तक सम्राट भोज का वैभव : सर्वे में तीन शिलालेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए गए हैं। पहला, पारिजात-मंजरी नाटिका शिलालेख बताता है कि इस नाटक की रचना धार के राजा अर्जुनवर्मन के गुरु मदन ने की थी। इसका पहला मंचन 'शारदा देवी के सदन' में हुआ था। दूसरा, अवनि कूर्मशतकम् शिलालेख में प्राकृत भाषा के दो काव्य हैं। प्रत्येक में 109 श्लोक हैं और दोनों की रचना सम्राट भोजदेव द्वारा की गई। तीसरा, नागबंध शिलालेख व्याकरण और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

सर्वे में 34 छोटे उत्कीर्ण नाम भी सामने आए। 13वीं सदी के शिल्पकारों में मदन, माधव और जकिजु के नाम हैं, जबकि 16वीं सदी में मोहिला, कामदेव, सोमदेव, रणपाल और परमार सहित डेढ़ दर्जन से अधिक शिल्पकारों के नाम मिले हैं। बता दें, भोजशाला से जुड़े शिलालेखों का पहला अध्ययन वर्ष 1951 में हुआ था। इसके बाद वर्ष 1970, 1972, 1978, 1989 और 1994 में हुए सर्वे रिपोर्टों के आधार 135 शिलालेखों की प्रतिलिपि तैयार की जा चुकी है। यह खोदाई केवल पत्थरों का अध्ययन नहीं, यह उस सांस्कृतिक स्मृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी।

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर

- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 साल बाद दुष्कर्म के आरोपित को किया दोषमुक्त
- जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई थी सात साल कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 20 साल के बाद दुष्कर्म के आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है। इस मामले में पीड़िता की उम्र घटना के समय लगभग 26 वर्ष थी और उसे संबंधों के परिणामों की जानकारी थी। इस आधार पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद कर दिया।

सरगुजा की एक युवती ने 2004 में याची के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। युवती ने सितंबर 2000 से अप्रैल 2004 तक शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। सत्र न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की कैद और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। फाइल

अदालत ने कहा कि पीड़िता की उम्र और उसकी सहमति को देखते हुए शादी का बहाना बनाकर बनाए गए संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आते। हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के निर्णय को गैर-कानूनी बताते हुए रद कर दिया। युवक को अगस्त 2004 में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2005 में सत्र न्यायालय ने निर्णय सुनाया, जिसके बाद वह जनवरी 2006 में जमानत पर बाहर आया। अब वह 20 वर्षों के बाद वह दोषमुक्त हो गया है।

एयर इंडिया के काकपिट में बैठा अनधिकृत व्यक्ति, होगी जांच

नई दिल्ली, प्रेट्र : एयर इंडिया ने इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित एक वीडियो को लेकर आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वीडियो में एयरलाइन की एक पूर्व केबिन क्रू सदस्य को उड़ान के दौरान विमान के काकपिट में बैठे हुए देखा जा रहा है।

एयरलाइन ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो की जानकारी है, जिसमें पूर्व केबिन क्रू सदस्य काकपिट के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक अन्य व्यक्ति काकपिट के अंदर का दृश्य और बाहर का नजारा रिकार्ड करता दिखाई दे रहा है।

सूत्रों के मुताबिक संबंधित केबिन क्रू सदस्य पिछले महीने ही एयरलाइन छोड़ चुके हैं। एयर इंडिया ने कहा कि फिलहाल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की जा रही है, लेकिन पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।

एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि केबिन क्रू को पायलट या काकपिट क्रू की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं होती, खासकर तब जब विमान आसमान में हो।

यूपीएससी

यूपीएससी ने घोषित किए सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंकों के विवरण, दूसरे स्थान पर रही राजेश्वरी सुवे एम को मिले 52.69 प्रतिशत अंक

सिविल सेवा परीक्षा में टापर अनुज ने प्राप्त किए 52.88 % अंक

- अनुज ने मुख्य लिखित परीक्षा में 867 अंक और साक्षात्कार में 204 अंक शामिल
- दूसरे स्थान पर रही राजेश्वरी सुवे एम ने 52.69 प्रतिशत अंक प्राप्त किए

14,161 मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए, 2,736 परीक्षा के साक्षात्कार के लिए क्वालीफाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में टाप करने वाले अनुज अग्निहोत्री ने 52.88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। यूपीएससी ने मंगलवार को अंकों के विवरण जारी किए। अनुज एम्स जोधपुर से स्नातक हैं। कुल 958 उम्मीदवार - 659 पुरुष और 299 महिलाएं - इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) आदि के लिए अधिकारियों के चयन हेतुसिविल सेवा परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष तीन चरणों में किया जाता है। इन तीन चरणों में प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) शामिल हैं।

अनुज ने कुल 1,071 अंक प्राप्त किए हैं। इनमें मुख्य लिखित परीक्षा में 867 अंक और साक्षात्कार में 204 अंक शामिल हैं। मेरिट कुल 2,025 अंकों में से निर्धारित की जाती है। लिखित या मुख्य परीक्षा 1,750 अंकों की होती है और साक्षात्कार 275 अंकों का होता है। अनुज ने जोधपुर स्थित आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) से एमबीबीएस (बैचलर आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी) किया है।

दूसरे स्थान पर रही राजेश्वरी सुवे एम ने 52.69 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने लिखित परीक्षा में 865 और साक्षात्कार में 202 अंकों समेत कुल 1,067 अंक प्राप्त किए। राजेश्वरी ने अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर आफ इंजीनियरिंग (बीई) की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने ने अपने पांचवें प्रयास में समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले एकांश ढुल ने 52.19 प्रतिशत अंक हासिल किए। उन्हें लिखित परीक्षा में 864 और

अनुज अग्निहोत्री। फाइल

साक्षात्कार में 193 अंकों समेत कुल 1,057 अंक मिले। चौथे स्थान पर रहे राघव झुनझुनवाला ने 51.45 प्रतिशत और पांचवें स्थान पर रहे ईशान भटनागर ने 51.25 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। राघव झुनझुनवाला ने लिखित परीक्षा में 847 और साक्षात्कार में 195 अंकों समेत कुल 1,042 अंक प्राप्त किए। ईशान भटनागर ने लिखित परीक्षा में 823 और साक्षात्कार में 215 अंकों समेत कुल 1,038 अंक प्राप्त किए। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 का आयोजन पिछले वर्ष 25 मई को किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 9,37,876 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 5,76,793 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। 14,161 उम्मीदवारों ने लिखित (मुख्य) परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए। लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में हुई थी। इनमें से 2,736 उम्मीदवारों ने परीक्षा के साक्षात्कार के लिए क्वालीफाई किया।

रबी सीजन में 12.02 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र: फसल वर्ष 2025-26 के दौरान देश में 12.02 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है। मंगलवार को जारी सरकारी डाटा के अनुसार, यह पिछले फसल वर्ष के 11.79 करोड़ टन के मुकाबले दो प्रतिशत ज्यादा है। गेहूं रबी की मुख्य फसल है और इसकी कटाई शुरू हो चुकी है।

कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2025-26 के दौरान कुल रबी फसल उत्पादन 3.16 प्रतिशत बढ़कर 17.45 करोड़ टन रहने का अनुमान है।

पिछले फसल वर्ष के दौरान 16.91 करोड़ टन रबी फसलों का उत्पादन हुआ था। इस रबी सीजन में दालों का उत्पादन सात प्रतिशत बढ़कर 1.62 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो पिछले फसल वर्ष में 1.52 करोड़ टन था। चने का उत्पादन 1.17 करोड़ टन रहने का अनुमान है जो पिछले वर्ष के 1.11 करोड़ टन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। जबकि मसूर का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.5 लाख टन के मुकाबले 17.3 लाख टन होने का अनुमान है।

हालांकि, उड़द का उत्पादन पिछले वर्ष के 5.53 लाख टन से घटकर 5.08 लाख टन और मूंग का उत्पादन एक लाख टन से घटकर 87 हजार टन रहने का अनुमान है। तिलहन में इस वर्ष सरसों का उत्पादन 1.33 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 1.26 करोड़ टन था। मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के 6.78 लाख टन के मुकाबले इस वर्ष 7.97 लाख टन होने का अनुमान है।

दैनिक जागरण

धैर्य ही विपत्ति में ढाल बनता है

आवश्यक वस्तु अधिनियम

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते देश में रसोई गैस के साथ वाहनों में प्रयुक्त होने वाली गैस की किल्लत रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का जो फैसला किया, वह यही बताता है कि गैस की कमी होने की आशंका उभर आई है और सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश की तमाम रिफाइनरियों और पेट्रो केमिकल यूनिट्स को अपने अन्य उत्पादों की तुलना में एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा सरकारी तंत्र को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि गैस की न तो जमाखोरी होने पाए और न ही उसकी कालाबाजारी। यह शुभ संकेत नहीं कि देश के कुछ शहरों में रसोई गैस की कालाबाजारी होने की आशंका उभर आई है। इसके अलावा इसका भी खतरा पैदा हो गया है कि मुनाफाखोर रसोई गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर सकते हैं। सरकारी तंत्र को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि गैस की किल्लत को लेकर अफवाहें न फैलने पाएं, क्योंकि जब ऐसा होता है, तब लोग अनावश्यक रूप से चिंतित हो जाते हैं। इस चिंता के कारण ही कहीं-कहीं गैस सिलेंडरों के लिए लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं। स्पष्ट है कि लोगों को भी धैर्य धारण करना होगा और अफवाहों को लेकर सचेत रहना होगा। यह ध्यान रहे कि चंद दिनों पहले पेट्रोल एवं डीजल की कोई कमी न होने के बाद भी कुछ जगह ऐसी अफवाह फैल गई थी कि उनकी कमी होने जा रही है। इस स्थिति से तभी बचा जा सकता है, जब अफवाहों को फैलने से रोका जाए और संबंधित प्रशासन की ओर से आवश्यक सूचनाएं समय पर प्रसारित की जाती रहें।

आखिर जब संबंधित मंत्रालय और विभागों की ओर से इसके लिए आशवस्त किया जा रहा है कि फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं, तब फिर किसी को बिना जरूरत अतिरिक्त गैस सिलेंडर पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यह सही है कि पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है, क्योंकि उनकी आपूर्ति करने वाला होर्मुज जल मार्ग ठप हो गया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि सरकार रूस, कनाडा के अलावा अफ्रीकी देशों से तेल के साथ गैस की आपूर्ति के हरसंभव जतन कर रही है। गैस की कमी रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी सचेत रहना होगा। उचित यह होगा कि जैसे केंद्र सरकार ने जमाखोरी-कालाबाजारी पर निगरानी के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की, वैसी ही समितियां राज्य सरकारें भी गठित करें। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न तो घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर में कमी आने पाए और न ही कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत होने पाए, क्योंकि इससे होटल-रेस्त्रां उद्योग प्रभावित होंगे और इसका असर अन्य अनेक लोगों पर भी पड़ेगा।

विकास की निरंतरता

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में उठे मुद्दों ने संकेत दिया है कि अब विकास की दिशा केवल नई घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं को गति देना भी उतना ही आवश्यक है। झज्जर के मातनहेल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित करने की पहल इसी सोच को प्रतिबिंबित करती है। पंचायत द्वारा 61 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की तत्परता और सरकार की पहल यह दर्शाती है कि समाज और शासन एक साथ आगे बढ़ें तो लंबे समय से प्रतीक्षित संस्थान भी साकार हो सकते हैं। इससे क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की सैन्य शिक्षा के अवसर मिलेंगे और स्थानीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी। पानीपत और इंद्री में बाईपास निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक और शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का प्रयास हैं। इससे यातायात दबाव कम होने के साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलने की संभावना है। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कैंसर डे-केयर सेंटर स्थापित करने की पहल इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से सुलभ बनाया जा रहा है। इससे मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। राज्य की प्रगति का मूल्यांकन घोषणाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से किया जाता है। योजनाओं को समयबद्धता, पारदर्शिता और स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलन के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह दृष्टि हरियाणा में विकास की विश्वसनीयता को और मजबूत कर सकती है।

विकास का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब योजनाएं शिलान्यास और घोषणाओं की सीमा पार कर धरातल पर आकार लेने लगती हैं

सफलता को व्यापक स्वरूप देने का समय

तरुण गुप्त

सफेद गेंद क्रिकेट में शानदार सफलता को अन्य खेलों में दोहराने के लिए खेल संस्कृति के विकास की भी प्रतीक्षा है

अवधेश राजपूत

भारत में आज क्रिकेट लेखक एक सुखद दुविधा से गुजर रहे हैं। जैसे-जैसे हमारे क्रिकेटर नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेखकों को उनकी जीत और इस ऐतिहासिक निरंतरता के गुणगान के लिए शब्दकोशों में नए विशेषणों, ताजा अभिव्यक्तियों और सटीक मुहावरों की तलाश करनी पड़ रही है। पिछले तीन वर्षों में सीमित ओवरों की भारतीय टीम ने आकाशीय ऊंचाइयों को छुआ है। 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल की हृदयविदारक हार के बाद से हमारी सफलता का ग्राफ निरंतर ऊपर ही रहा है। हमने 2024 का टी-20 विश्व कप जीता, मार्च 2025 में चैंपियंस ट्राफी, अक्टूबर 2025 में एशिया कप और अब सफलतापूर्वक अपने टी-20 खिताब का बचाव किया है। इस हालिया जीत से कई उपलब्धियां पहली बार हासिल हुईं। भारत ने रिकार्ड तीसरा टी-20 विश्व कप खिताब जीता और हम खिताब का बचाव करने वाली और पहली विजेता मेजबान टीम बने। पिछले पांच बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में से हमने चार जीते और उनमें हमारा जीत-हार का रिकार्ड 37-2 रहा है। यह वास्तव में भारतीय टीम की निरंतरता और प्रभुत्व का ठोस प्रमाण है। हर सफलता कुछ शौर्यगाथाओं को जन्म देती है। सुखद यह है कि इस विजयगाथा में योगदान देने वाले इतने अधिक खिलाड़ी हैं कि सभी को याद रखना या कुछ की प्रशंसा करना कठिन हो जाता है। यह एक बेहतरीन स्थिति है। आखिरकार क्रिकेट एक टीम खेल ही है, जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम की सफलता मायने रखती है-वह दर्शन जिस पर जोर देने का कोई अवसर कोच गंभीर कभी नहीं छोड़ते।

खेल से जुड़े उतार-चढ़ाव भी इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाई दिए। संजू सैमसन, जो मूल टीम का हिस्सा भी नहीं थे, 'प्लेयर आफ द टूर्नामेंट' बनकर उभरे। अभिषेक शर्मा, जो हमारे प्रमुख बल्लेबाज के रूप में टूर्नामेंट में गए थे, शुरुआती खराब फार्म के दौर से गुजरे। जब उनकी जगह पर सवाल उठने लगे, तब उन्होंने फाइनल में एक शानदार पारी खेली। इशान किशन ने चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और व्यक्तिगत दुख के बावजूद फाइनल में हमारे सलामी बल्लेबाजों द्वारा प्रदान की गई लय को आगे बढ़ाया। हमारी यह जीत कप्तान के महत्वपूर्ण योगदान के बिना भी (सिवाय अमेरिका के विरुद्ध पहले मैच में) संभव हो सकी। इसमें जहां तिलक वर्मा और पांड्या ने कुछ अवसरों पर स्थिति को संभाला, वहीं शिवम दुबे ने एक फिनिशर के रूप में अपने प्रदर्शन से निरंतरता की छाप छोड़ी। बुमराह बेशक एक अभूतपूर्व खिलाड़ी बने हुए हैं। वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 'आल फार्मेट' गेंदबाज हैं। भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया भर के बल्लेबाज अब तक उनकी काट नहीं ढूंढ़ पाए हैं। वहीं, अक्षर पटेल ने गेंद के साथ-साथ मैदान पर अपनी सूझबूझ और फुर्ती से महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रशंसा के लिए तो पूरी टीम का उल्लेख आवश्यक है। यह हमारी सामूहिक शक्ति और खेल में गहरी पैठ का प्रमाण है। यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी निरंतर मेहनत और प्रदर्शन के प्रति सचेत रहें। यहां पुरानी उपलब्धियों पर सुकून से बैठने का समय नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली युवाओं की कतार हमेशा जगह लेने के लिए तैयार रहती है। इससे असुरक्षा या दबाव पैदा हो सकता है, पर यही भाव क्रिकेटरों को शिथिलता से परहेज करने के लिए प्रेरित करता है, जो लंबे करियर के लिए एक आवश्यक तत्व है।

जीत जश्न मनाने का अवसर है, लेकिन निरंतरता के लिए आत्मनिरीक्षण भी जरूरी है। सीमित ओवरों के क्रिकेट में हमने विशेष सफलता हासिल की है, लेकिन खेल के मूल यानी टेस्ट प्रारूप का क्या? 2025 के इंग्लैंड के दौरे को छोड़ दें, तो पिछले डेढ़ साल में टेस्ट प्रारूप में हमारा प्रदर्शन औसत से नीचे रहा है। हम आस्ट्रेलिया में हारे और घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूपड़ा साफ होने की जिल्लत झेलनी पड़ी। वह शायद भारतीय टेस्ट टीम के लिए सबसे निचला स्तर था। अतीत की महान टीमें चाहे वह सत्तर और अस्सी के दशक की वेस्टइंडीज हो या 2000 के दशक की आस्ट्रेलिया-हर परिस्थिति में सभी प्रारूपों पर राज करती थीं। यह प्रशासकों के सोचने का विषय है कि जहां आइपीएल सीमित ओवरों की प्रतिभा निखारने का बेहतरीन माध्यम है, वहीं पांच दिवसीय क्रिकेट में इसे दोहराने के लिए हमें घरेलू क्रिकेट-वही पुराने रणजी ट्राफी, दलीप ट्राफी और ईरानी कप-पर अधिक ध्यान देना होगा। हमारी बल्लेबाजी में तो गहराई है, पर गेंदबाजी को और पैना करने की जरूरत है। हम बुमराह पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और अश्विन की विदाई ने एक ऐसी रिक्तता पैदा की है, जिसे भरना कठिन है।

22 गज की पट्टी से परे देखें तो एक खेल राष्ट्र के रूप में भारत का उदय अभी अधूरा है। जनसंख्या और आर्थिकी को देखते हुए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं से काफी कम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही खेल में उत्कृष्टता-जहां हम सबसे बड़ी वित्तीय शक्ति हैं-और कुछ अन्य खेलों में छिटपुट सफलता समग्र निराशाजनक परिणाम की भरपाई नहीं कर सकती। एक व्यापक रणनीतिक योजना आवश्यक है, ताकि समय के साथ प्रभावी प्रगति और निरंतर सफलता सुनिश्चित हो सके। हमारी जनसांख्यिकी में आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) की जो कमी हो सकती है, उसे प्रशिक्षण, अनुकूलन और पोषण के माध्यम से दूर करना होगा। बदलाव आने में पीढ़ियां लगती हैं और निरंतर ठोस प्रयासों का कोई विकल्प नहीं होता। कहते हैं कि 'हजार मील की यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है।' लेकिन इससे पहले कि हम इस यात्रा पर निकलें, एक खेल संस्कृति विकसित करना आवश्यक है। एक समाज का खेलों के प्रति केवल 'उपयोगितावादी' दृष्टिकोण नहीं हो सकता। हर कोई पेशेवर खिलाड़ी नहीं बनेगा, न ही हर व्यक्ति खेल में श्रेष्ठता के माध्यम से शिक्षा संस्थानों में प्रवेश या रोजगार नियुक्ति सुनिश्चित कर पाएगा। फिर भी, केवल खेलने के आनंद के लिए खेलना और खेल के आंतरिक लाभों को आत्मसात करना आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है, 'आपके पास जो भी प्रतिभा है, उसका उपयोग करें। याद रहे कि जंगल खामोश हो जाएंगे यदि केवल वही पक्षी गाएंगे, जो सबसे अच्छा गाते हैं।'

(लेखक दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक हैं)

response@jagran.com

सुहाने सपने दिखाते सिविल सेवक

राजीव सचान

ऐसे तमाम सिविल सेवक हैं, जिन्होंने समाज सेवा की बड़ी बातें तो की थीं, पर बाद में वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए

बदलाव की मांग करती सिविल सेवा। फाइल

संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा को देश ही नहीं, दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसी कारण इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के नाम सबका ध्यान खींचते हैं। सफल अभ्यर्थी और विशेष रूप से शीर्ष स्थान अर्जित करने वाले अपने माता-पिता और शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करते हैं। जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी सफलता पूरे समुदाय में गर्व का भाव जगाती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय समाज में आइएएस और विशेष रूप से कलेक्टर यानी डीएम बनना प्रतिष्ठा का परिचायक रहा है। यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा पास करना प्रतिष्ठा का कितना बड़ा विषय है, इसे इससे समझा जा सकता है कि कई जगह सफल अभ्यर्थियों का गाजे-बाजे के साथ स्वागत-सत्कार होता है।

बीते दिनों यूपीएससी परीक्षा में सफल रहे कई अभ्यर्थियों का उनके गांव-घर में कुछ उसी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जैसे किसी नवनिर्वाचित नेता के चुनाव जीत लेने पर होता है। एक अभ्यर्थी ने अपने स्वागत के समय कार में सवार होकर जनता का अभिवादन किया और लोगों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाईं। एक के स्वागत में लोग संगीत की धुन पर नाचते और अभ्यर्थी को नोटों की माला पहनाते दिखे। एक अन्य के काफिले में लैंड रोवर, डिफेंडर जैसी लक्जरी गाड़ियां नजर आईं। कुछ पुराने सिविल सेवकों ने सफल अभ्यर्थियों के नेताओं सरीखे ऐसे भव्य स्वागत पर असहमति और अप्रसन्नता प्रकट की। कुछ ने उन्हें नसीहत दी कि यूपीएससी परीक्षा पास करना मात्र कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं कि उनका ढोल बजाकर स्वागत किया जाए। इस असहमति का कुछ मूल्य-महत्व हो सकता है, लेकिन क्या कोई उस पर ध्यान देगा?

आने वाले दिनों में यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के ऐसे साक्षात्कार पढ़ने-सुनने को मिल सकते हैं, जिनमें वे बताएंगे कि कैसे देश और समाज सेवा के जज्बे ने उन्हें सिविल सेवक बनने को प्रेरित किया। लगभग हर सफल अभ्यर्थी का स्वर यही होता है कि वह समाज के लिए कुछ करना चाहता था और इसका सबसे उत्तम उपाय सिविल सेवा में जाना था। इसमें संदेह नहीं कि आइएएस, आइपीएस जैसे पद सबसे सामर्थ्यवान हैं। इन पर आसीन होने वाले अपने विभाग या क्षेत्र की तस्वीर और लोगों का भाग्य बदल सकने में समर्थ होते हैं, पर क्या औसत सिविल सेवक ऐसा कर पा रहे हैं? यह वह प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

सिविल सेवकों को प्रशासनिक सेवा की रीढ़ माना जाता है। प्रशासन में उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1947 में इसी तिथि को सरदार पटेल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रथम बैच के अधिकारियों को संबोधित किया था। इसी संबोधन में उन्होंने सिविल सेवकों को इस्पाती ढांचे की संज्ञा दी थी, पर पिछले काफी समय से यह स्वर उभर रहा है कि इस इस्पाती ढांचे को जंग लग चुकी है। इसी के साथ सिविल सेवकों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता भी जताई जा रही है। कहना कठिन है कि इस आवश्यकता की पूर्ति होगी या नहीं, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय जिस प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, उसकी सिफारिशों पर आज तक अमल नहीं हुआ। यह अमल मोदी सरकार की ओर से बार-बार यह कहते रहने के बाद भी नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई गई है। इस कथित जीरो टालरेंस नीति के बावजूद नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

नौकरशाहों के साथ नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। आम तौर पर नेता तभी भ्रष्टाचार करने में समर्थ होते हैं, जब उन्हें भ्रष्ट नौकरशाहों का साथ मिलता है। अपने देश में भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई मुश्किल से ही पाती है। कई बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप से घिरे नेताओं को तो राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसे ही आरोपों से दो-चार नौकरशाहों का मुश्किल से ही कुछ बिगड़ पाता है। एक तो उनके भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जांच बहुत मुश्किल से हो पाती है और दूसरे, जांच में कठिनाई से ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाता है। ऐसे सिविल सेवकों की गिनती करना कठिन है, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास करते समय समाज सेवा करने की बड़ी-बड़ी बातें की थीं, लेकिन बाद में वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। विडंबना यह कि इनमें से कुछ वे भी रहे, जो अपने बैच के टापर थे या फिर जिनकी ख्याति इसलिए हुई थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में प्रथम 10 या 20 सफल अभ्यर्थियों में स्थान हासिल किया था अथवा सबसे कम उम्र के सफल अभ्यर्थी बने थे। निःसंदेह ईमानदार और कर्मठ सिविल सेवकों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वही प्रशासन की इज्जत बचाए हुए हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि भ्रष्ट सिविल सेवक निष्ठावान सिविल सेवकों की बदनामी का कारण बनते हैं। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि भ्रष्ट सिविल सेवकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अपना काम सही से करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। महिमामंडन भी उन्हीं का होना चाहिए, न कि केवल सुहाने सपने दिखाने वालों का।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिष्कार

परिष्कार से आशय है-किसी वस्तु, विचार, व्यवहार या व्यक्तित्व को और अधिक परिमार्जित करके शुद्धता एवं उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर तक ले जाना। यह वस्तुतः आंतरिक गुणों के निखार की प्रक्रिया है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निरंतर परिष्कार नितांत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पूर्ण नहीं होता। वह संभावनाओं का एक बीज लेकर इस संसार में आता है। इन संभावनाओं को विकसित करने के लिए शिक्षा, संस्कार, अनुभव और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार, विचार और कार्यों का सतत मूल्यांकन करता रहे और उनमें सुधार लाने का प्रयास करता रहे, तो उसका व्यक्तित्व धीरे-धीरे निखरता रहेगा। परिष्कार की सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य के विचारों को होती है, क्योंकि विचार ही कर्म का आधार होते हैं। यदि विचार शुद्ध, सकारात्मक और उदात्त हों, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। अतः विचारों का परिष्कार अत्यंत आवश्यक है।

शिक्षा को परिष्कार का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य में विवेक, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी का भाव जगाती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में-सत्य, करुणा, सहिष्णुता, दया और सहयोग का निरंतर परिष्कार करते रहें। परिष्कार की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास ही जीवन में वास्तविक प्रगति का निमित्त बन पाता है। परिष्कार व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को आत्ममंथन के द्वारा निरंतर सुधारने का प्रयास करता है, तब उसका व्यक्तित्व उज्ज्वल और प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए हमें जीवन के हर क्षेत्र में परिष्कार की प्रक्रिया को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है।

प्रेरणा अवस्थी

चिंतित करती समय से पहले आई गर्मी

देवेंद्रराज सुथार

यह संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है

मार्च का महीना सामान्यतः भारत में वसंत ऋतु का समय माना जाता है, जब तापमान अपेक्षाकृत संतुलित रहता है और गर्मी धीरे-धीरे बढ़ती है। किंतु हाल के वर्षों में यह पारंपरिक जलवायु चक्र तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2026 की शुरुआत में ही देश के कई हिस्सों में समय से पहले हीटवेव जैसी स्थिति बनने लगी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। कई शहरों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय के औसत तापमान से काफी अधिक है।

भारत पहले से ही हीटवेव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देशों में शामिल है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1981 से 2020 के बीच देश में हीटवेव की घटनाओं की आवृत्ति और अवधि दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में भारत ने पिछले 122 वर्षों का सबसे गर्म मार्च दर्ज किया था। उसी वर्ष अप्रैल में देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। विश्व मौसम संगठन और अंतरसरकारी पैनल आन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट भी बताती हैं कि वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता बढ़ रही है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में इसका प्रभाव और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। समय से पहले आने वाली हीटवेव का प्रभाव केवल तापमान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर डालता है। कृषि क्षेत्र भी इस असामान्य गर्मी से प्रभावित होता है। वर्ष 2022 में इसी कारण गेहूं उत्पादन पर असर पड़ा था और सरकार को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था।

इन परिस्थितियों में समय से पहले आने वाली हीटवेव को केवल मौसमी उतार-चढ़ाव मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि वर्तमान की चुनौती बन चुका है। इसके समाधान के लिए दो स्तरों पर कार्य करना आवश्यक है। पहला, दीर्घकालिक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और टिकाऊ विकास नीतियों को अपनाना। दूसरा, तात्कालिक स्तर पर अनुकूलन उपायों को मजबूत करना, जैसे हीट एक्शन प्लान, शहरी हरित क्षेत्र का विस्तार, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की तैयारी। भारत के कई शहर जैसे अहमदाबाद पहले ही प्रभावी हीट एक्शन प्लान लागू कर चुके हैं, जिससे गर्मी से होने वाली मौतों में कमी आई है। अब आवश्यकता है कि ऐसे माडल को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से लागू किया जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

समग्रता में होना चाहिए विमर्श

जगमोहन सिंह राजपूत ने अपने लेख 'तूल न दें एनसीईआरटी की भूल को' में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय पर लिखे गए कुछ अंशों को त्रुटि बताते हुए उसे भूल जाने की बात कही है। यह सही है कि अतीत में एनसीईआरटी की पुस्तकों में त्रुटियां हुई हैं और उन्हें सुधारा भी गया है, किंतु इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाठ्यपुस्तक के कुछ अंशों पर सीधे न्यायपालिका की प्रतिक्रिया सामने आई, जो अपने आप में असामान्य स्थिति है। न्यायिक भ्रष्टाचार का प्रश्न केवल किसी संस्था की प्रतिष्ठा का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। यदि इस पर चर्चा को पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास माना जाए, तो फिर उसी तर्क से राजनेताओं या नौकरशाही पर उठने वाले प्रश्नों को भी अस्वीकार करना पड़ेगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच विकसित करना भी है। ऐसे में एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करने के बजाय मुक्त विमर्श और सामाजिक वास्तविकताओं पर विचार की परंपरा को प्रोत्साहित करना अधिक उचित होगा।

आशीष राजपूत, शोधार्थी, गुरुग्राम

रोबोट के भविष्य से जुड़ी संभावनाएं

पूरे विश्व की तरह अब भारत में भी रोबोटिक्स का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अब यह केवल शोध केंद्रों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उद्योगों, फैक्टिरयों और गोदामों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज ऐसे रोबोट विकसित किए जा रहे हैं जो कठिन और जोखिम भरे कार्य भी कर सकेंगे। उदाहरण के लिए चार पैरों वाले रोबोट ऊबड़-खाबड़ जमीन और सीढ़ियों पर भी आसानी से चलने में सक्षम हैं। हालांकि रोबोट की बढ़ती भागीदारी के कारण कुछ नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है, विशेष रूप से वे कार्य जो सरल और बार-बार दोहराए जाने वाले होते हैं। इसके बावजूद रोबोटिक्स उद्योग में नई प्रकार की नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे, जैसे रोबोटिक्स इंजीनियर, आटोमेशन विशेषज्ञ और डाटा विश्लेषक। भारत में रोबोटिक्स उद्योग को बढ़ावा देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इस क्षेत्र में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

dharmendranath.rastogi@gmail.com

राष्ट्रपति के प्रति मुख्यमंत्री की उदासीनता

विगत सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की बंगाल यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिखाई गई उदासीनता निर्धारित प्रोटोकाल का जानबूझकर किया गया उल्लंघन प्रतीत होती है, जिसमें किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र में संवैधानिक मर्यादाओं और शिष्टाचार का पालन शासन व्यवस्था की आधारशिला होता है। राष्ट्रपति का पद सदैव दलगत राजनीति से ऊपर माना जाता है और यह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है। ऐसे में राष्ट्रपति की हालिया बंगाल यात्रा के दौरान दिखाई गई उदासीनता संसदीय परंपराओं और संवैधानिक शिष्टाचार के प्रति असम्मान का संकेत देती है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद जगजाहिर हैं। किंतु इन मतभेदों की छाया देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति पर नहीं पड़नी चाहिए थी। ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक समीकरणों और वोट बैंक की राजनीति के कारण कई बार प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रति आक्रामक रुख अपनाना पड़ता है, लेकिन यहां आगमन राष्ट्रपति का था, जो दलगत राजनीति से परे हैं। ऐसे में किसी भी वर्ग के नाराज होने की आशंका भी नहीं थी। मुख्यमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व होता है कि राज्य के दौरे पर आए राष्ट्रप्रमुख का सम्मानपूर्वक स्वागत और सत्कार करें। दुर्भाग्यवश, यहां अनावश्यक राजनीतिक विरोध प्रशासनिक शिष्टाचार के आड़े आता हुआ दिखाई दिया। इससे शासन की प्रशासनिक परिपक्वता पर भी प्रश्न उठते हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीतिक कुंठा अधिक उजागर होती दिखती है।

sushil23dec@gmail.com

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

डा. जगदीप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कालेज, नारायणगढ़

आजकल

डिजिटल लत से मुक्ति की पहल

कर्नाटक सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का यह निर्णय बच्चों को डिजिटल जाल से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाने का एक साहसिक प्रयास है। यह नीति न केवल बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करेगी, बल्कि उन्हें रचनात्मक, शारीरिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगी। अन्य राज्य भी इस माडल का अनुसरण करें

नई पीढ़ी को डिजिटल व्यसन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित करना आवश्यक। प्रतीकात्मक

कर्नाटक सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय न केवल दूरदर्शी है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक और समग्र विकास की रक्षा हेतु एक सशक्त संदेश भी है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में इस ऐतिहासिक नीति की घोषणा की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य नई पीढ़ी को डिजिटल व्यसन के दुष्प्रभावों से सुरक्षित करना है। भारत के तकनीकी केंद्र बेंगलुरु जैसे शहर में इस प्रकार का प्रतिबंध एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों है। वर्तमान में इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स ने बच्चों के जीवन में इस कदर पैठ बना ली है कि वे वास्तविक दुनिया से कटते जा रहे हैं। पढ़ाई, आउटडोर खेल और पारिवारिक संवाद के स्थान पर वर्चुअल दुनिया का प्रभुत्व बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने बार-बार चेतावनी दी है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों में निम्नलिखित समस्याओं का कारण बन रहा है: मानसिक स्वास्थ्य- अवसाद, चिंता और आत्मसम्मान में कमी। शारीरिक स्वास्थ्य-नींद की भारी कमी, आंखों की कमजोरी और शारीरिक सक्रियता का अभाव। सामाजिक जोखिम- साइबरबुलिंग, अनुपयुक्त सामग्री तक पहुंच और वास्तविक सामाजिक कौशल का ह्रास। भारत में इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। जहां अधिकांश बच्चे प्रतिदिन औसतन 3 से 5 घंटे इंटरनेट मीडिया पर व्यतीत कर रहे हैं, वहां यह नीति उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। हालांकि इस प्रतिबंध का क्रियान्वयन एक जटिल कार्य होगा, जिसमें तकनीकी प्लेटफार्म्स के सहयोग और माता-पिता की जागरूकता की अहम भूमिका होगी।

कर्नाटक सरकार के इस फैसले का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ेगा। इंटरनेट मीडिया की अंतहीन स्क्रालिंग बच्चों के मस्तिष्क को इंसटेंट ग्रेटिफिकेशन (त्वरित संतुष्टि) का आदी बना देती है। यह प्रवृत्ति उनकी एकाग्रता को खंडित करती है, धैर्य को समाप्त करती है और गहन चिंतन की क्षमता को सीमित कर देती है। जब बच्चे आभासी दुनिया के शोर से दूर होंगे, तब उन्हें आत्म-खोज का अवसर मिलेगा। इंटरनेट मीडिया से मिलने वाली राहत उन्हें पुस्तकों की दुनिया, संगीत की साधना, रचनात्मक लेखन और खेल के मैदान की ओर पुनः आकर्षित करेगी। शोध स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल मीडिया के सीमित उपयोग से न केवल अवसाद के लक्षणों में कमी आती है, बल्कि बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होता है। कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्य में जहां शिक्षा और तकनीक का अद्भुत संगम है, यह प्रतिबंध बच्चों को वास्तविक दुनिया की ओर लौटने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करेगा। यह उनके व्यक्तित्व को केवल यूजर के रूप में नहीं, बल्कि एक विचारशील नागरिक के रूप में गढ़ने में सहायक होगा। इसके साथ ही यह अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की प्रेरणा देगा। पारिवारिक संवाद की यह पुनर्स्थापना बच्चों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना को सुदृढ़ करेगी, जो अंततः एक स्वस्थ समाज की नींव रखेगा।

शारीरिक विकास के संदर्भ में कर्नाटक सरकार का यह निर्णय किसी क्रांति से कम नहीं है। आज की पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा निरंतर स्क्रीन के सामने बैठे रहने के कारण डिजिटल रुग्णता का शिकार हो रहा है। कम उम्र में ही बच्चों में मोटापा, दृष्टि दोष, टेक-नेक (गर्दन का दर्द) और रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं। इंटरनेट मीडिया की लत ने बच्चों को घर की चारदीवारी में कैद कर दिया है, जिससे उनका नैसर्गिक शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया है। इस प्रतिबंध का सबसे सुखद परिणाम यह होगा कि बच्चे आभासी खेलों को छोड़कर वास्तविक खेल के मैदानों की ओर रुख करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार विकासशील बच्चों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक घंटे की तीव्र शारीरिक गतिविधि अनिवार्य है। इंटरनेट मीडिया के अभाव में यह समय स्वतः ही खेलकूद के लिए उपलब्ध होगा। इससे न केवल कबड्डी, खो-खो और क्रिकेट जैसे पारंपरिक खेलों को संजीवनी मिलेगी, बल्कि योग जैसी प्राचीन पद्धतियां भी उनके जीवन का हिस्सा बनेंगी। ये गतिविधियां न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाती हैं, बल्कि बच्चों को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और टीम वर्क की भावना से भी जोड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शारीरिक श्रम के दौरान मस्तिष्क में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे रसायनों का प्राकृतिक स्राव होता है, जो तनाव को कम कर आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिबंध केवल एक रोक नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन के निवास की नींव रखने वाला एक युगांतकारी कदम है।

कर्नाटक सरकार का यह साहसी निर्णय भारत के अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय माडल और पथ-प्रदर्शक है। अब समय आ गया है कि इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक नीति के रूप में अपनाया जाए। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही इस दिशा में सक्रियता दिखा रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों द्वारा केंद्र सरकार को भी आयु-आधारित डिजिटल पहुंच नीतियां बनाने का सुझाव दिया जा रहा है। अन्य राज्यों को कर्नाटक के इस प्रतिमान का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे-जागरूकता अभियान-स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों को डिजिटल खतरों के प्रति सचेत करना। तकनीकी नियंत्रण-पैरेंटल कंट्रोल टूल्स को अनिवार्य बनाना और सख्त आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना। पाठ्यक्रम में बदलाव-डिजिटल साक्षरता और साइबर हाइजीन को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना। निश्चित ही इस कानून का प्रवर्तन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती होगी, जहां इंटरनेट की अनियंत्रित पहुंच और डार्क एप्स का खतरा बना रहता है। किंतु सामुदायिक सहयोग और तकनीकी कड़ाई से इन्हें दूर किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के फ्लोरिडा जैसे प्रांतों में इसी प्रकार के प्रतिबंधों की सफलता भारत के लिए एक सशक्त प्रेरणा है। यदि भारत के सभी राज्य एकजुट होकर और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस दिशा में कार्य करेंगे तो हम करोड़ों बच्चों के भविष्य को डिजिटल दलदल से बचाकर एक स्वस्थ और संतुलित दिशा प्रदान कर सकेंगे। यह केवल एक प्रतिबंध नहीं, बल्कि एक स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण का राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए।

कुल मिलाकर कर्नाटक सरकार का यह निर्णय बच्चों को डिजिटल जाल से मुक्त कर वास्तविक जीवन की ओर ले जाने का एक साहसिक और युगांतकारी प्रयास है। यह नीति न केवल बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को न्यूनतम करेगी, बल्कि उन्हें रचनात्मक, शारीरिक रूप से सक्रिय और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगी। आज समय की मांग है कि अन्य राज्य भी बिना किसी विलंब के इस माडल का अनुसरण करें। भारत के हर बच्चे को यह अधिकार है कि उसका बचपन इंटरनेट मीडिया की लत की भेंट चढ़ने के बजाय पुस्तकों की महक, खेल के मैदानों की ऊर्जा और परिवार के स्नेहपूर्ण सान्निध्य में बीते। एक संतुलित और खुशहाल बचपन ही भविष्य के जिम्मेदार नागरिक गढ़ सकता है। अंततः स्वस्थ और संस्कारित बच्चे ही एक समर्थ राष्ट्र की आधारशिला होते हैं और यह फैसला उसी नींव को अभेद्य बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध की व्यावहारिक चुनौतियां

कर्नाटक सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया प्रतिबंध की घोषणा ने एक नई राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया है। जहां यह निर्णय बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनिवार्य जान पड़ता है, वहीं इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर कई जटिल प्रश्न भी खड़े होते हैं। एक तकनीकी हब के रूप में कर्नाटक के लिए यह नीति केवल एक कानूनी रोक नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस की एक बड़ी परीक्षा है।

इस प्रतिबंध की सबसे बड़ी चुनौती एज-गेटिंग की है। वर्तमान में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स पर उम्र छिपाकर अकाउंट बनाना बेहद आसान है। सरकार को इन टेक-दिग्गजों को मजबूर करना होगा कि वे फेस-स्कैनिंग या आधार-लिंक्ड वेरिफिकेशन जैसे कड़े मानक अपनाएं। इसके बिना यह कानून केवल कागजी बनकर रह जाएगा। साथ ही डार्क वेब और वीपीएन के बढ़ते उपयोग से बच्चों को दूर रखना एक बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी चुनौती होगी।

विद्वानों का एक वर्ग यह भी तर्क देता है कि पूर्ण प्रतिबंध के बजाय डिजिटल साक्षरता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को इंटरनेट मीडिया से पूरी तरह काटने के बजाय उन्हें इसके सुरक्षित उपयोग और एल्गोरिदम के प्रभाव को समझना सिखाना दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में साइबर हाइजीन को शामिल करना और बच्चों को डिजिटल नागरिकता के प्रति जागरूक करना इस नीति को सफल बनाने के लिए आवश्यक है।

यह नीति तभी सफल हो सकती है जब अभिभावक स्वयं डिजिटल डिटाक्स का उदाहरण पेश करें। घर के भीतर नो-गैजेट जोन और सक्रिय निगरानी तंत्र का अभाव किसी भी कानून को विफल कर सकता है। अंततः सरकार केवल दिशा-निर्देश दे सकती है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण परिवार और समाज के सामूहिक विवेक से ही संभव है। कर्नाटक की यह पहल भविष्य में एक ऐसी डिजिटल संस्कृति की नींव रख सकती है जहां तकनीक दास हो, स्वामी नहीं।

खरी-खरी

नोबेल पुरस्कार का अधिग्रहण

डा. प्रदीप मिश्र

'अरे ओ कमांडर..!' कमांडर-इन-चीफ ने हांक लगाई। कमांडर ने सल्यूट बजाया-'जो आज्ञा, श्रीमान!' चीफ बोले, 'तुम अभी इसी वक्त दो-ढाई सौ मिसाइलें नार्वे की तरफ मोड़ लो।' 'यस सर!' इसके अलावा कमांडर के पास कोई जवाब भी कहां होता है? चीफ कमांडर ने कहा, 'पच्चीस-तीस मिसाइलें तो तुम सीधे नोबेल पुरस्कार वाले दफ्तर पर फेंक देना। तुम्हारा टारगेट नोबेल को मेरे पास लाना है।' 'जिंदा या मुर्दा? किस हालत में लाना है, श्रीमान?' 'जिंदा लाना है, बंधक बनाकर।'

'कौन-कौन से नोबेल लाने हैं, महोदय?' कमांडर ने पूछा। चीफ कमांडर बोले, 'तुम वहां नोबेलों की छंटाई मत करना। जितने मिलें, सब ले आना। यहां हम अपनी पसंद के छांट लेंगे।' 'यस सर!' यह कहते हुए कमांडर ने मिसाइल को कमांड दिया-'चार्ली! एक्स डाट...डाट...वाई डिग्री फोकस्ड नार्वे। ओवर! चार्ली डम-चार्ली पम, कंडक्ट आपरेशन आन नोबेल आफिस। जितने मिलें, सारे नोबेल बटोरिए। ओवर।'

टीवी पर एंकर ने खबर दी-'निकली हुई मिसाइलें अपना काम करने के बाद म्यान में लौट आई हैं। वे भांति-भांति के नोबेल पुरस्कारों से लदी हुई हैं। मिसाइलों से उतारकर नोबेल पुरस्कारों को गोदाम में रखा जा रहा है, जहां उनकी छंटाई भी शुरू हो गई है। ट्रंप जी जिस-जिस साल के जो-जो नोबेल चाहेंगे, उनके लिए एलान किया जाएगा। सूत्रों से खबर मिली है कि ट्रंप जी ने कुछ नोबेल पुरस्कार अपने लिए फाइनल भी कर लिए हैं-2026 से 2126 तक के शांति के सभी नोबेल, 2026 से 2100 तक के अर्थशास्त्र के सभी नोबेल, 2026 से 2109 तक के सभी मेडिसिन नोबेल और 2026 से 2128 तक के सभी साहित्य के नोबेल। रसायन, भौतिकी और जीवविज्ञान के कई नोबेल भी ट्रंप ने पसंद किए हैं। बचे-खुचे नोबेल योग्य लोगों में बांटने के बजाय मुनीर और शहबाज को दे दिए जाएंगे।' ट्रंप समर्थक झूम उठे हैं। सबका मानना है कि 'शक्तिशाली नेता नोबेल के लिए याचना नहीं करते, रण करते हैं। आवेदन नहीं, अधिग्रहण करते हैं!'

पोस्ट

रसोई गैस की किल्लत को लेकर हो रहे दुष्प्रचार और उससे मच रही अफरा-तफरी रोकने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि नियमित रूप से प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से वैसे ही जानकारियां साझा की जाएं, जैसा कोविड के समय किया जा रहा था।

ऐश्वर्या मुदगिल@AishwaryakiRai

जब तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहेगा, तब तक ऐसे संकट उसे परेशान करते रहेंगे। ऊर्जा के वैकल्पिक और नवीकरणीय स्रोतों पर हमें अपनी निर्भरता बढ़ानी ही होगी। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं। साथ ही जीवनशैली में बदलाव की भी आवश्यकता है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

टी-20 विश्व कप जीत की खुमारी में हमें जान राइट को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने विजय हजारे ट्राफी खेल रहे जसप्रीत बुमराह की प्रतिभा को पहचान कर मुंबई इंडियंस से अनुशंसा की थी कि उन्हें तराशा जाए। अब बुमराह राष्ट्रीय धरोहर से कम नहीं।

मकरंद वेंगणकर@wmakarand

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या ईरान के जवाबी हमले अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं?

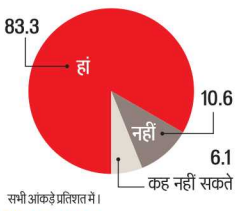

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होने से आपूर्ति श्रृंखला सुगम बनी रहेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गोबर का कंडा जले नहीं चाहिए गैस,
हर घर में हर गांव के पलें गाय और भैंस।
पलें गाय और भैंस आत्मनिर्भर हो भारत,
जाय भाड़ में तेल-गैस की कठिन तिजारत!
चरखे से हम लोग किये गोरों को ठंडा,
अब हम छोड़ें गैस चुनें गोबर का कंडा!!

- ओमप्रकाश तिवारी

जड़ी-बूटियों की खेती को मिले प्रोत्साहन

अरविंद कुमार मिश्रा
लोक नीति विश्लेषक

आगामी वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना तथा आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण की घोषणा की गई है। गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर स्थापित वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन की भी योजना है। इन कदमों को आयुष उत्पादों के प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है, जिससे औषधीय उत्पादों के प्रमाणन और निर्यात को मजबूती मिलेगी। इसका लाभ औषधीय फसल उगाने वाले किसानों और प्रसंस्करण से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी मिलेगा।

औषधीय वनस्पतियां आयुर्वेद सहित कई पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और घरेलू उपचार प्रणालियों का आधार हैं। विश्व की लगभग 80 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में पारंपरिक औषधीय पौधों से तैयार दवाओं का उपयोग करती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इनका महत्व बना हुआ है, क्योंकि लगभग 40 प्रतिशत फार्मास्यूटिकल उत्पादों में पारंपरिक औषधियां मुख्य घटक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। औषधीय पौधों की खेती किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि इनकी कई प्रजातियां कम उपजाऊ मिट्टी में भी उगाई जा सकती हैं।

भारत में औषधीय वनस्पतियों की लगभग 8,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। दुर्लभ और संकटग्रस्त औषधीय पौधों की पहचान के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआइ) द्वारा व्यापक अध्ययन किया गया है। देश का लगभग 38 प्रतिशत भूभाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, जहां बहुउपयोगी औषधीय वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। वर्तमान में औषधीय प्रजातियों की कुल आवश्यकता का केवल एक छोटा हिस्सा ही खेती से प्राप्त होता है, जबकि शेष वनों, पहाड़ी क्षेत्रों और चारागाहों से एकत्र किया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत मुलेठी, शतावरी, श्वेत मुसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, पिप्पली और चिरायता जैसे औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आयुर्वेद के मूल ग्रंथ चरक संहिता में अनेक औषधीय वनस्पतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि प्रकृति में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी औषधि का गुणधर्म जाने बिना उसका प्रयोग हानिकारक हो सकता है।

खराब जीवनशैली जनित बीमारियों के उपचार के लिए आयुर्वेद की बढ़ती मांग। प्रतीकात्मक

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) औषधीय पौधों के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। क्षेत्रीय-सह-सुविधा केंद्रों के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। औषधीय पौधों के विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए ई-चरक मोबाइल एप और वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो किसानों और अन्य हितधारकों को बाजार की जानकारी उपलब्ध कराता है। देश में औषधीय पौधों पर आधारित उपचार पद्धतियों को वैज्ञानिक आधार देने के लिए कई अनुसंधान परियोजनाएं भी चल रही हैं। विशेष रूप से कैंसररोधी क्षमता वाले पौधों पर शोध किया जा रहा है। आज भी देश में लगभग 70 हजार पारंपरिक वैद्य अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उपचार करते हैं, लेकिन इस परंपरागत ज्ञान को पर्याप्त महत्व न मिलने के कारण यह विरासत धीरे-धीरे लुप्त हो रही है। यदि इन वैद्यों को शोध और प्रशिक्षण से जोड़ा जाए तो स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती मिल सकती है।

वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई पहचान मिली है। आयुष रिसर्च पोर्टल पर 43 हजार से अधिक शोध प्रकाशन उपलब्ध हैं, जो औषधीय वनस्पतियों के महत्व को रेखांकित करते हैं। हर्बल उत्पादों का वैश्विक बाजार 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है और भारत से लगभग 6500 करोड़ रुपये के आयुष उत्पादों का निर्यात हो रहा है।

बदलती जीवनशैली के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं और चिकित्सा सेवाएं महंगी होती जा रही हैं। ऐसे समय में औषधीय वनस्पतियों की खेती न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने में सहायक हो सकती है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

मंथन

चिंता बढ़ाता ऊर्जा संकट

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की अस्तित्वगत अनिवार्यता बन गई है

प्रो. आरके जैन
अध्यापक

पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका एवं इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध ने दुनिया को ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। तेल के वैश्विक बाजार में आई इस उथल-पुथल ने केवल अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को ही नहीं बदला है, बल्कि भारत के महानगरों के सामान्य जनजीवन और देश की आर्थिक स्थिरता के सामने एक विकराल चुनौती पेश कर दी है। आज भारत का शहरी जीवन जिस संकट का सामना कर रहा है, वह स्पष्ट करता है कि वैश्विक राजनीति और आम आदमी की थाली के बीच का संबंध कितना गहरा और संवेदनशील है। इस वैश्विक समस्या का सबसे तात्कालिक और स्थानीय उदाहरण दक्षिण भारत के प्रमुख तकनीकी केंद्र बेंगलुरु में देखने को मिला है। शहर के हजारों रेस्तरां और भोजनालयों द्वारा शहरव्यापी बंद की दी गई चेतावनी इस संकट की गंभीरता का जीवंत प्रमाण है। होटल उद्योग का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है। यह एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक संकट है, जो हजारों कर्मचारियों के रोजगार और लाखों लोगों की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार में मची इस खलबली की वास्तविक पृष्ठभूमि युद्ध की आग में झुलसता पश्चिम एशिया है। कूटनीतिक वार्ताओं की विफलता और बढ़ते सैन्य टकराव ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को भंग कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में घबराहट का आलम यह है कि ब्रेंट क्रूड आयल की कीमतें संघर्ष के शुरुआती दिनों में ही उछलकर 119.50 डालर प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक जा पहुंचीं। युद्ध के शुरुआती हफ्तों में कीमतों में हुई 35 से 40 प्रतिशत की यह वृद्धि सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए एक खतरे की घंटी है। इस संकट का सबसे संवेदनशील भौगोलिक केंद्र स्ट्रेट आफ होर्मुज है। दुनिया के इस संकीर्ण, लेकिन सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा और प्राकृतिक गैस की एक विशाल मात्रा गुजरती है। युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग पर बढ़ते सुरक्षा जोखिमों ने शिपिंग कंपनियों को अपनी सेवाएं सीमित करने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों के बीमा प्रीमियम में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी ने परिवहन लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है। जब दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन ही अनिश्चितता के घेरे में हो तो तेल की कीमतों में स्थिरता की कल्पना करना बेमानी है।

भारत के लिए यह स्थिति किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग 85 से 90 प्रतिशत आयात करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा इसी अशांत पश्चिम एशिया से आता है। ऐसे में वैश्विक कीमतों में होने वाली प्रत्येक डालर की वृद्धि भारत की आर्थिक सेहत पर सीधा प्रहार करती है। तेल महंगा होने का सीधा अर्थ है-विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से क्षरण। इससे देश का चालू खाता घाटा बढ़ता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये की विनिमय दर पर दबाव बढ़ जाता है। तेल की कीमतों का प्रभाव मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसा होता है। कच्चा तेल महंगा होते ही देश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई और परिवहन लागत भी बढ़ जाती है, जिससे सब्जियों, अनाज और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में आग लग जाती है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमतों में प्रति 10 डालर की वृद्धि भारत की महंगाई दर को 0.2 से 0.25 प्रतिशत तक बढ़ा देती है। भारत सरकार के लिए यह एक अत्यंत जटिल चुनौती है। यदि सरकार तेल की कीमतों को घरेलू बाजार में नियंत्रित करने के लिए उत्पाद शुल्क कम करती है तो उसका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि तेल की कीमतें लंबे समय तक 100 डालर प्रति बैरल से ऊपर बनी रहीं तो भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.15 से 0.4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह स्थिति न केवल निवेश को प्रभावित करेगी, बल्कि शेयर बाजार में भी भारी अस्थिरता पैदा करेगी।

होर्मुज जल मार्ग बाधित होने से प्रभावित हुई कच्चे तेल की आपूर्ति। फाइल

इसके समाधान के लिए भारत को बहुआयामी रणनीति पर काम करना होगा। हमें ऊर्जा आयात के लिए केवल एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्षमता बढ़ानी होगी, ताकि आपातकाल में कम से कम 90 दिनों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनाल ब्लेंडिंग और हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में चल रहे कार्यों को और अधिक तीव्र करना होगा। यदि भारत को अपनी आर्थिक संप्रभुता और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा को युद्धस्तर पर प्राथमिकता देनी होगी। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की अस्तित्वगत अनिवार्यता बन गई है।

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 11 मार्च, 2026
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

राजपूताना स्टेनलेस के आइपीओ को 42% अभिदान

नई दिल्ली: लंबे और फ्लैट स्टेनलेस-स्टील उत्पाद बनाने वाली कंपनी, राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड के आइपीओ को मंगलवार को बोली के दूसरे दिन 42 प्रतिशत अभिदान मिला। एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आईपीओ को 2,09,00,000 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 88,17,270 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआइबी) की श्रेणी को 99 प्रतिशत अभिदान मिला। (प्रेट)

व्यक्तिगत निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स के पास अब निफ्टी 50 कंपनियों के फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण का करीब 36 प्रतिशत हिस्सा है।
— तुहिन कांत पांडे, सेबी चेयरमैन

सेंसेक्स	78,205.98 ▲ 639.82	निफ्टी	24,261.60 ▲ 233.55	सोना प्रति दस ग्राम	₹1,64,700 ▲ ₹400	चांदी प्रति किलोग्राम	₹2,79,275 ▲ ₹10,975	डालर	₹91.85 ▼ ₹0.36	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$90.26

एक नजर में

जनवरी-फरवरी में चीन का निर्यात 22 प्रतिशत बढ़ा

हांग कांग: अमेरिका से ट्रेड वार के बावजूद जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान चीन के निर्यात में वार्षिक आधार पर करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इस वृद्धि में कंप्यूटर चिप्स, आटो और इलेक्ट्रानिक्स का प्रमुख योगदान रहा है। चीन के सीमा शुल्क विभाग की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले दो महीनों में अमेरिका को उसका निर्यात घटकर 11 प्रतिशत रहा है। दिसंबर 2026 में अमेरिका को चीन के निर्यात में 30 प्रतिशत की गिरावट रही थी। (एपी)

वर्ष 2025 में सऊदी अरामको का लाभ घटा

दुबई: सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको ने मंगलवार को बताया कि कैलेंडर वर्ष 2025 में उसका लाभ घटकर 10 अरब डालर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान कंपनी को 110 अरब डालर का लाभ हुआ था। इसी तरह पिछले वर्ष कंपनी का राजस्व भी घटकर 445 अरब डालर रहा है, जो 2024 के दौरान 480 अरब डालर रहा था। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरामको के तेल संयंत्रों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया जा रहा है। (एपी)

अतिरिक्त एसटीटी की जानकारी दें स्टाक ब्रोकर

मुंबई: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) ने मंगलवार को अपने ट्रेडिंग मेंबर्स- ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स को निर्देश दिया कि वे आयकर विभाग के निर्देशों के बाद वित्त वर्ष 2023-24 और उससे पहले के सालों के लिए इकट्ठा किए गए अतिरिक्त सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) की जानकारी दें। इसमें वो टैक्स शामिल है जो सरकार के पास जमा नहीं किया गया है। सभी ट्रेडिंग मेंबर्स को इकट्ठा किए गए एसटीटी को हर महीने की देरी के लिए एक प्रतिशत ब्याज के साथ एनएसई के भेजने के लिए कहा गया है। बाद में यह रकम सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी। (आइएएनएस)

फरवरी में इक्विटी एमएफ निवेश आठ प्रतिशत बढ़ा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति बनने से पिछले माह इक्विटी योजनाओं को 25,978 करोड़ मिले

नई दिल्ली, प्रेट: इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं में फरवरी के दौरान शुद्ध निवेश आठ प्रतिशत बढ़कर 25,978 करोड़ रुपये हो गया। इस निवेश के साथ ही म्यूचुअल फंड उद्योग की कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) फरवरी महीने में बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपये हो गईं। जनवरी में इसका एयूएम 81 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, एसआइपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में निवेश पिछले महीने के 31,000 करोड़ रुपये से थोड़ा कम होकर फरवरी में लगभग 29,845 करोड़ रुपये रह गया। विशेषज्ञों के मुताबिक, फरवरी में एसआइपी कलेक्शन पर महीने के छोटा होने का असर पड़ा, क्योंकि 29, 30 और 31 तारीख के लिए तय किस्तें आमतौर पर मार्च की शुरुआत में प्रोसेस होती हैं, जिससे योगदान का एक हिस्सा अगले महीने के लिए थोड़ा टल जाता है।

- एसआइपी निवेश जनवरी के 31 हजार करोड़ से घटकर फरवरी में 29,845 करोड़ रुपये रह गया
- म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल एयूएम फरवरी में 82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

'एसोसिएशन आफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया' (एम्फी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी वेंकट एन चलसानी ने कहा कि इक्विटी योजनाओं में सकारात्मक प्रवाह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति बनने के कारण बढ़े निवेशक भरोसे का नतीजा हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े पश्चिम एशिया के बढ़ते संघर्ष के कारण इस महीने म्यूचुअल फंड बाजार में कुछ अस्थिरता देखी जा सकती है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक वृद्धि की कहानी मजबूत बनी रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी में इक्विटी योजनाओं में 24,028 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था, जो फरवरी में बढ़कर 25,978 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर में इक्विटी इनफ्लो 28,054 करोड़ रुपये और नवंबर में 29,911 करोड़ रुपये था। इक्विटी श्रेणी में फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे अधिक 6,924.65 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया। इसके बाद मिडकैप फंड में 4,003 करोड़ रुपये और स्मालकैप फंड में 3,881 करोड़ रुपये का निवेश हुआ। क्षेत्रीय एवं विषयगत फंड में 2,987 करोड़ रुपये और लार्जकैप फंड में 2,112 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया। हालांकि कर-बचत वाली ईएलएसएस योजनाओं से 650 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी हुई। कुल मिलाकर, म्यूचुअल फंड उद्योग में फरवरी के दौरान 94,530 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश आया।

सोने-चांदी में अस्थिरता से ईटीएफ में निवेश तेजी से घटा

गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में फरवरी के दौरान 5,255 करोड़ रुपये का निवेश आया, जबकि जनवरी में यह 24,040 करोड़ रुपये और दिसंबर में 11,647 करोड़ रुपये था। जर्मिनेट इन्वेस्टर सर्विसेज के सीईओ संतोष जोसेफ ने कहा, "सोने और चांदी में आई अस्थिरता और मजबूत रिटर्न ने निवेशकों का ध्यान काफी खींचा और कीमती धातुओं वाले ईटीएफ से मौजूदा आउटफ्लो एक मज़बूत तेजी के बाद मुनाफावसूली का एक दौर लगता है।'

ऋण-आधारित डेट म्यूचुअल फंड योजनाओं में भी पिछले महीने 42,106 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया, जो जनवरी के 74,827 करोड़ रुपये से कम है।

फरवरी 2026 बाजारों के लिए एक और उतार-चढ़ाव वाला महीना रहा। हालांकि, इसके बावजूद भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जबरदस्त मजबूत दिखाई। यह एक साफ संकेत है कि निवेशक अब ज्यादा से ज्यादा लंबी अवधि पर ध्यान दे रहे हैं और छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव को नजरअंदाज कर रहे हैं।
-वरुण गुप्ता, सीईओ, ग्रो म्यूचुअल फंड

कच्चे तेल के दाम में नरमी से बाजार में लौटी तेजी

मुंबई, प्रेट: स्थानीय शेयर बाजारों में मंगलवार को दो दिन से जारी भारी गिरावट पर अंकुश लगा और सेंसेक्स और निफ्टी लगभग एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 639.82 अंक बढ़कर 78,205.98 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 960.09 अंक चढ़कर 78,526.25 अंक पर पहुंच गया था। वहीं, एनएसई निफ्टी 233.55 अंक चढ़कर 24,261.60 अंक पर बंद हुआ।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के जल्द समाप्त होने की उम्मीद के बीच कच्चे तेल के दाम में नरमी और दुनिया के अन्य प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी से घरेलू बाजार पर सकारात्मक असर हुआ। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 9.03 प्रतिशत टूटकर 90.26 डालर प्रति बैरल पर आ गया है।

सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति, आइसीआइसीआइ बैंक, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में बढ़त रही। वहीं इटरनल, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल के शेयर में गिरावट रही। सेंसेक्स सोमवार को 1,352.74 अंक टूटकर 77,566.16 अंक पर रहा था जबकि एनएसई निफ्टी 422.40 अंक की गिरावट के साथ 24,028.05 अंक पर बंद हुआ था। एशियाई बाजारों की बात करें दक्षिण कोरिया का कास्पी इंडेक्स 5.35 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त के साथ ऊपर चढ़ा जबकि जापान का निक्केई225 इंडेक्स 2.88 प्रतिशत ऊपर गया। शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसैंग भी बढ़त के साथ बंद हुए।

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव कम होने के संकेतों के बाद बाजार में उछाल आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के शीघ्र समाप्त होने के संकेत दिए हैं। इसने दुनिया में बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंताओं को कम किया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट लाकर जोखिम धारणा को स्थिर करने में मदद की है।

639.82 अंक बढ़कर 78,205.98 अंक पर बंद हुआ बीएसई सेंसेक्स

233.55 अंक चढ़कर 24,261.60 पर बंद हुआ एनएसई का निफ्टी

डालर के मुकाबले 36 पैसे बढ़ा भारतीय रुपया

मुंबई, प्रेट: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कम होने की उम्मीद में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट के चलते रुपया 36 पैसे की बढ़त के साथ 91.85 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, घरेलू शेयर बाजारों में आई तेज बढ़त और डालर के कमजोर पड़ने से घरेलू मुद्रा को और भी सहारा मिला। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डालर के मुकाबले 91.92 पर खुला और 91.71-92.19 की सीमा में कारोबार करने के बाद 91.85 पर बंद हुआ, जो इसके पिछले बंद भाव से 36 पैसे ज़्यादा था। मिराए एसेट शेयरखान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी ने कहा, "वैश्विक बाज़ारों में जोखिम कम होने की भावनाएं शांत होने के बाद रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से उबर गया। हमें उम्मीद है कि डालर कमजोर पड़ने के कारण रुपया थोड़ी सकारात्मक बढ़त के साथ कारोबार करेगा।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

15 मार्च तक जमा कर दें एडवांस टैक्स, चूकने पर देना होगा ब्याज

जागरण संवाददाता, कानपुर : वित्त वर्ष 2025-26 (कर निर्धारण वर्ष 2026-27) के लिए एडवांस टैक्स की चौथी व अंतिम किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित है। यदि किसी करदाता की सभी कटौती के बाद कुल कर देयता 10 हजार रुपये या उससे अधिक है, तो उन्हें एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। समय से टैक्स नहीं जमा करने वालों को एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देना पड़ेगा।

कर सलाहकार अधिवक्ता संतोष गुप्ता ने बताया कि आयकर कानून की धारा 207 से 219 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2026-27 का किसी भी करदाता का 15 मार्च तक अनुमानित कर योग्य आय पर देय संपूर्ण एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए। इस नियम में 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी कारोबार या पेशे से कोई आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स के दायरे से मुक्त रखा गया है। टैक्स आडिट (धारा 44 एबी) के दायरे में आने वाली सभी कंपनियों के लिए टैक्स आनलाइन जमा करना अनिवार्य है, जबकि अन्य करदाता बैंकों में चालान के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगर चारों किस्तों में निर्धारित राशि से कम भुगतान किया गया है तो कम राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज समेत रकम जमा करनी होगी। 31 मार्च तक कुल देय टैक्स का 90 प्रतिशत से कम हिस्सा जमा करने पर एक अप्रैल, 2026 से शेष राशि पर ही ब्याज देना पड़ेगा।

- 10 हजार रुपये से अधिक कर देयता पर एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी
- टैक्स जमा नहीं करने पर प्रतिमाह एक प्रतिशत तक देना पड़ सकता है ब्याज

चांदी 10,975, सोना 400 रुपये बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट: मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतों में 10,975 रुपये की तेजी आई और यह 2,79,275 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोने की कीमत में 400 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह भू-राजनीतिक घटनाक्रम थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संभावित समाधान की ओर इशारा किया था।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर चांदी की कीमतों में 1.38 डालर या 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 88.33 डालर प्रति औंस पर पहुंच गई। वहीं, सोना लगभग एक प्रतिशत की तेजी के साथ 5,172.86 डालर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

पिछले साल देश में आइफोन का उत्पादन 53 प्रतिशत ज्यादा रहा

नई दिल्ली, आइएएनएस: अमेरिका की दिग्गज तकनीकी कंपनी एपल ने पिछले साल यानी 2025 में भारत में आइफोन का उत्पादन करीब 53 प्रतिशत बढ़ा दिया। 2024 के 3.6 करोड़ यूनिट के मुकाबले 2025 में 5.5 करोड़ यूनिट असेंबल किए गए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी चीन पर लगने वाले टैरिफ से बचने के लिए अपने फ्लैगशिप उत्पादन का एक चौथाई हिस्सा भारत में बनाती है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि एपल हर साल दुनियाभर में करीब 22-23 करोड़ आइफोन बनाती है। इसमें भारत का हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा समर्थित 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआइ) योजना है। इस तरह की योजनाओं ने चीन के मुकाबले कमजोर सप्लाई चेन और लाजिस्टिक से जुड़ी चुनौतियों जैसी ढांचागत लागत संबंधी कमियों को दूर करने में मदद की है। कंपनी अब आइफोन-17 सीरीज के सभी माडल को भारत में ही करती है असेंबल

- 2024 के 3.6 करोड़ यूनिट के मुकाबले 2025 में 5.5 करोड़ यूनिट असेंबल किए गए
- कंपनी अब आइफोन-17 सीरीज के सभी माडल को भारत में ही करती है असेंबल

अब आइफोन-17 सीरीज के सभी माडल को भारत में ही असेंबल करती है। आइफोन 15 और 16 जैसे पुराने माडल का उत्पादन भी घरेलू बिक्री और निर्यात के लिए स्थानीय स्तर पर ही जारी है। देश में एपल के स्टोर की संख्या बढ़कर छह हो गई है। देश में कंपनी की कुल बिक्री नौ अरब डालर के आंकड़े को पार कर गई है।

अंतरराष्ट्रीय

विकास कूटनीति के जरिये भारत से रिश्ते मजबूत करेगी आरएसपी: रवि लामिछाने

- आरएसपी अध्यक्ष ने पार्टी की चुनावी सफलता पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया धन्यवाद
- कहा, हमारी सरकार आपसी सम्मान, साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहेगी

रवि लामिछाने। फाइल

काठमांडू, प्रेट : नेपाल के संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया है। लामिछाने ने कहा कि उनकी पार्टी 'विकास कूटनीति' को प्राथमिकता देते हुए नेपाल और भारत के संबंधों को सुदृढ़ करेगी। यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरएसपी की चुनावी सफलता पर दी गई बधाई के जवाब में आया है।

लामिछाने ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, '"राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और हमारी सरकार आपसी सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहेगी। हम भारत के साथ ऐसी साझेदारी की उम्मीद करते हैं जो कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार में सहयोग के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुए।"'

चुनावी नतीजों में आरएसपी का दबदबा : नेपाल में 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' यानी प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत मतगणना मंगलवार को संपन्न हो गई। कुल 165 प्रत्यक्ष सीटों में से आरएसपी ने 125 सीटों पर भारी जीत दर्ज की है। अन्य दलों की स्थिति देखें तो नेपाली कांग्रेस को 18, कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (सीपीएन-यूएमएल) को नौ व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) को आठ सीटें मिली हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत भी आरएसपी सबसे आगे चल रही है, जिसे अब तक 49 लाख से अधिक वोट मिल चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में आरएसपी की कुल सदस्य संख्या 175 के आसपास पहुंच जाएगी, जिससे वह स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में होगी।

> हम भारत के साथ ऐसी साझेदारी की उम्मीद करते हैं जो कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार में सहयोग के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छुए। - रवि लामिछाने, आरएसपी अध्यक्ष

क्षेत्रीय राजनीति में नए युग की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी ने रवि लामिछाने के साथ-साथ बालेंद्र शाह को भी उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी। उल्लेखनीय है कि बालेंद्र शाह नेपाल के पहले मधेशी प्रधानमंत्री और देश के सबसे कम उम्र के निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनने की राह पर हैं। मोदी ने विश्वास जताया कि दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों से भारत-नेपाल संबंध आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूएंगे। नेपाल निर्वाचन आयोग के अनुसार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत अंतिम परिणामों की घोषणा में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन वर्तमान रुझान स्पष्ट रूप से आरएसपी के पक्ष में हैं। लामिछाने ने मोदी द्वारा नेपाली जनता के लोकतांत्रिक जनादेश को मान्यता देने की सराहना करते हुए दोनों देशों के नागरिकों के समृद्ध भविष्य की कामना की है।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन: भारत

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट : भारत ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। कहा, रमजान में नागरिकों की जान लेने वाले हमले करते समय इस्लामी एकजुटता का आह्वान करना पाखंड है। 'हम इन कृत्यों की निंदा करते हुए, अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता व स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं।'

सोमवार को अफगानिस्तान की स्थिति पर सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अमल व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के यूएन महासचिव के आह्वान के प्रति नई दिल्ली के समर्थन को दोहराया।

कहा, अफगानिस्तान पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर व देश की संप्रभुता के सिद्धांत का घोर उल्लंघन हैं। एक ओर अंतरराष्ट्रीय कानून व इस्लामी एकजुटता के उच्च सिद्धांतों का समर्थन करना,दूसरी ओर रमजान के पवित्र माह में बर्बर हवाई हमले करना पाखंड है। इन हमलों में छह मार्च तक 185 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। इनमें से 55 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे हैं। हमलों के कारण एक लाख लोग विस्थापित हुए हैं। **अमेरिका ने अफगानिस्तान को अवैध तरीके से हिरासत में रखने वाला देश घोषित किया:** अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगानिस्तान को रांगफुल डिटेंशन स्टेट (अवैध तरीके से हिरासत में रखने वाला देश) घोषित किया। यूएन में अमेरिकी राजदूत ने अफगानिस्तान पर बंधक कूटनीति में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। इसके साथ अफगानिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें अमेरिकियों को हिरासत में लेने के लिए निशाना बनाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर लिखा, 'मैं अफगानिस्तान को अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों का स्टेट स्पान्सर घोषित कर रहा हूं। तालिबान पालिसी में छूट पाने को आतंकी तरीकों का प्रयोग करता है, पर यह नहीं चलेगा। तालिबान सरकार को डेनिस कोयल समेत गलत तरीके से हिरासत में लिए गए सभी अमेरिकियों को रिहा करना होगा।

- रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर हमले की भारत ने की कड़ी निंदा

हरीश पर्वतनेनी।

पाकिस्तान द्वारा इस्लामी एकजुटता के आह्वान को पाखंड करार दिया

टोरंटो में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में गोलीबारी

कनाडा के टोरंटो में मंगलवार तड़के डाउनटाउन स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद बाहर तैनात पुलिसकर्मी। रायटर

टोरंटो, एपी: टोरंटो में मंगलवार तड़के डाउनटाउन स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी हुई। इस घटना में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। कनाडा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टोरंटो पुलिस ने मंगलवार को बताया कि उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे सूचना मिली कि किसी ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोली चलाई है। इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में पुलिस ने बताया कि वे यूनिवर्सिटी एवेन्यू और क्वीन स्ट्रीट वेस्ट के पास घटनास्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने पोस्ट में कहा कि गोलीबारी के सुबूत मिले हैं। संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने एक बयान में कहा कि आज सुबह अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में हुई गोलीबारी हमारे अमेरिकी मित्रों और पड़ोसियों को लक्षित हिंसा और धमकी का एक बिल्कुल अस्वीकार्य कृत्य है।

अमेरिका-द. कोरिया के सैन्य अभ्यास पर भड़की किम जोंग उन की बहन

सियोल, एपी : उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने अमेरिका व दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाते हैं और यदि उत्तर कोरिया की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं।

यह बयान उस समय आया जब फ्रीडम शील्ड नामक 11 दिनी संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, जिसमें हजारों सैनिक भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास अमेरिका, दक्षिण कोरिया की संयुक्त सैन्य क्षमता व संभावित युद्ध स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखने के लिए आयोजित किया जाता है। इसके साथ फील्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम 'वारियर शील्ड' भी चलाया जा रहा है। किम ने कहा, वैश्विक स्तर पर सुरक्षा ढांचा तेजी से कमजोर हो रहा है और

राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता से दूर होंगी वैश्विक अनिश्चितताएं: कीर्ति वर्धन सिंह

लंदन, प्रेट: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मौजूदा संघर्षों के कारण वैश्विक व्यवस्था में उत्पन्न व्यवधान दूर करने के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। कहा,लोकतांत्रिक देशों का यह सबसे बड़ा समूह (राष्ट्रमंडल) अपने संसाधनों को साझा कर भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकता है। लंदन में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंह ने कहा, राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता से वैश्विक अनिश्चितताएं दूर हो सकती हैं।

जलवायु संरक्षण पर किंग चार्ल्स तृतीय से चर्चा: कीर्ति वर्धन ने अपनी यात्रा के दौरान सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित विशेष रिसेप्शन में किंग चार्ल्स तृतीय से भेंट की। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग का कार्यभार संभाल रहे सिंह ने चार्ल्स के साथ जलवायु संबंधी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। किंग ने कहा, हमें यह कार्य इसलिए करना होगा ताकि हमारी भावी पीढ़ियों को कष्ट न सहना पड़े।

- लंदन में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया
- किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात में जलवायु संबंधी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की

लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में सोमवार को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा आयोजित विशेष रिसेप्शन में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। प्रेट्र

वैश्विक चुनौतियों और सुधारों पर जोर: कीर्ति वर्धन ने पश्चिम एशिया के संघर्षों व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा की। कहा, सदस्य देशों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का उपयोग टिकाऊ विकास के लिए करना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा समूह हैं। हमें मानव व प्राकृतिक संसाधनों को साथ लाकर आगे बढ़ना होगा। साथ मिलकर हम आपूर्ति श्रृंखला व ऊर्जा सुरक्षा जैसी अनिश्चितताओं को हल कर सकते हैं। भारत मजबूत आइटी क्षेत्र व डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के जरिये अन्य विकासशील देशों के लिए अहम संसाधन बन सकता है। सिंह ने ब्रिटेन की मंत्री सीमा मल्होत्रा से भी भेंट की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

कनाडा गोलीबारी मामले में छात्रा के परिवार ने ओपन एआइ पर किया मुकदमा

वैंकूवर, एपी: कनाडा में स्कूल में 10 फरवरी को हुई गोलीबारी कांड में घायल छात्रा के स्वजन ने ओपनएआइ के खिलाफ केस दायर किया है। परिवार का आरोप है कि हमलावर ने हमले की योजना बनाने के लिए चैटजीपीटी का प्रयोग किया था। कंपनी ने जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दी।

आरोप है कि हमलावर जेसी वैन रोस्टसेलर ने गोलीबारी में आठ लोगों की हत्या कर दी। बाद में खुद भी जान दे दी। मुकदमे में कहा गया है कि इस घटना में घायल छात्रा को तीन गोलियां लगीं, जिससे उसे सिर पर गंभीर चोट पहुंची है और वह स्थायी शारीरिक व मानसिक विकलांगता का सामना कर सकती है। कंपनी ने पहले कहा था कि हमलावर का चैटजीपीटी अकाउंट बंद कर दिया गया था, पर उसने दूसरा अकाउंट बनाकर प्लेटफार्म का प्रयोग जारी रखा। मामले में ओपनएआइ ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

ईरान में गहराया जल संकट, युद्ध के बीच पानी को लेकर बढ़ी चिंता

जंग के बीच सूखे की मार, 'डे-जीरो' की आहट से सहमा देश

न्यूयार्क टाइम्स से

गोलियों से ज्यादा खतरनाक हो सकती है पानी की कमी

वाशिंगटन : ईरान इस समय दोहरी मार झेल रहा है एक तरफ युद्ध का दबाव और दूसरी तरफ गहराता जल संकट। जलवायु परिवर्तन, खेती में अत्यधिक पानी की खपत और दशकों के कुप्रबंधन ने पहले ही देश को सूखे की कगार पर पहुंचा दिया था। अब युद्ध ने इस संकट को और खतरनाक बना दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पानी की कमी ईरान के लिए किसी बड़े मानवीय संकट का रूप ले सकती है।

हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर केशम द्वीप स्थित डिसेलिनेशन प्लांट पर बमबारी का आरोप लगाया। यह संयंत्र समुद्री पानी को मीठा बनाकर आसपास के इलाकों में आपूर्ति करता था। हमले के बाद करीब 30 गांवों की जल आपूर्ति प्रभावित होने की बात कही गई है। हालांकि अमेरिका ने इस आरोप से इनकार किया है। इसके बाद ईरान ने बहरीन में एक डिसेलिनेशन संयंत्र पर हमला कर जवाब दिया, जिससे पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र में जल ढांचे पर हमलों की आशंका और बढ़ गई है।

ईरान में गहराया पानी का संकट। इंटरनेट मीडिया

सूखे की चपेट में तेहरान

करीब एक करोड़ की आबादी वाला तेहरान पिछले कई वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। पिछले साल देश में औसत वर्षा सामान्य से लगभग 45 प्रतिशत कम रही। राजधानी को पानी देने वाले कई बांध और जलाशय अब न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। ईरान के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कई शहर वाटर डे-जीरो की स्थिति के करीब हैं यानी वह समय जब जल आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने यहां तक कहा था कि घटते जल संसाधनों और पर्यावरणीय दबावों के कारण तेहरान धीरे-धीरे रहने योग्य नहीं रह गया है और राजधानी को कहीं और स्थानांतरित करने पर भी विचार करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का मत : कुप्रबंधन ने बढ़ाई मुसीबत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट सिर्फ मौसम की देन नहीं है, बल्कि दशकों की गलत नीतियों का नतीजा भी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जल आत्मनिर्भरता के नाम पर ईरान में बड़े पैमाने पर बांध व जलाशय बनाए गए, पर कई परियोजनाएं गलत स्थानों पर खड़ी कर दी गईं। बढ़ती गर्मी ने इन जलाशयों में पानी के तेजी से वाष्पीकरण को और बढ़ा दिया। 2024 के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के 50 सबसे अधिक दोहन किए जा रहे भूजल भंडारों में से 32 अकेले ईरान में हैं। यानी देश अपने भूमिगत जल को तेजी से खाली कर रहा है। संकट से निपटने को सरकार ने ओमान की खाड़ी से पानी आयात करने जैसे दीर्घकालिक उपायों की चर्चा जरूर की है, लेकिन अभी तक इस दिशा में ठोस प्रयास नहीं हो पाए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि युद्ध और सूखा साथ-साथ बढ़ते रहे तो ईरान में खाद्य संकट, आर्थिक दबाव और बड़े पैमाने पर पलायन की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में ईरान के सामने केवल युद्ध की चुनौती ही नहीं, बल्कि पानी की जंग भी खड़ी है।

अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान में काली और अम्लीय बारिश

- बारिश में मौजूद रासायनिक कण अत्यंत खतरनाक
- ईरानी नागरिकों ने सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई

मेलबर्न, द कन्वरसेशन: अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों के बाद ईरान के कुछ हिस्सों में काले रंग की बारिश होने की खबरें आई हैं। मीडिया की कुछ खबरों में इसे अम्लीय बारिश कहा गया है। इसके कारण ईरानी नागरिकों ने सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई होने और इमारतों एवं वाहनों पर तेल मिश्रित पानी गिरने की शिकायतें की हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि इस बारिश में मौजूद रासायनिक यौगिक अत्यंत खतरनाक और अम्लीय हो सकते हैं।

एक वायुमंडलीय रसायन विशेषज्ञ और रासायनिक इंजीनियर के अनुसार, यह बारिश केवल अम्लीय नहीं है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल तो होंगे ही, साथ ही अन्य कई हानिकारक रसायन भी मिल सकते हैं। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रूप से खतरनाक हैं। तेल डिपो पर हमलों से उठे धुएं में हाइड्रोकार्बन, अल्ट्राफाइन कण (पीएम2.5), पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (पीएएचएस) और भारी धातुएं शामिल हो सकती हैं। इन प्रदूषकों के बारिश में मिलने से यह और भी हानिकारक हो जाती है। धुएं में सल्फर डाइआक्साइड और नाइट्रोजन डाइआक्साइड भी होते हैं, जो वायुमंडल में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। यही अम्ल पानी की बूंदों में घुलकर अम्लीय बारिश बनाता है।

ईरान में हो रही अम्लीय वर्षा।

लोगों को मास्क पहनने, घर में रहने की सलाह

स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा उपाय भी बताए गए हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि प्रभावित लोग मास्क पहनें, घर में रहें, दरवाजे व खिड़कियां बंद रखें। बाहर की हवा को भीतर न आने दें। सतहों को नियमित रूप से साफ करना भी जरूरी है। हालांकि युद्ध की स्थिति में इन उपायों को लागू करना कठिन है। पूर्व में हुए युद्धों के अनुभव जैसे इराक व कुवैत में तेल के कुओं को नष्ट करना, जलने वाले विशाल स्थलों से उठने वाला धुआं, यह दिखाता है कि युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव और स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक असर गहरा होता है। वर्तमान परिस्थितियों में ईरानी स्थानीय आबादी को भी गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

डब्ल्यूएचओ ने दी स्वास्थ्य संबंधी खतरों की चेतावनी

रायटर के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी दी कि तेल सुविधाओं पर हमलों के बाद ईरान में काली बारिश व हवा में मौजूद जहरीले कणों के कारण श्वसन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसने लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह करने वाली सलाह का समर्थन किया। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमीयर ने जिनेवा में कहा कि काली बारिश और इसके साथ आने वाली अम्लीय बारिश आबादी के लिए एक खतरा है।

कैंसर, हृदय रोग और मानसिक विकार जैसी बीमारियों का खतरा : विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश सामान्य अम्लीय बारिश से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि इसमें कई विषाक्त और कैंसरकारी तत्व शामिल हैं। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। लोग सिरदर्द, सांस लेने में कठिनाई और अस्थमा जैसी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। विशेषकर वृद्ध, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और असमर्थ लोग अधिक जोखिम में हैं। लंबे समय में अल्ट्राफाइन कण रक्त प्रवाह में प्रवेश कर कैंसर, हृदय रोग और मानसिक विकार जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्रदूषक जब जल स्रोतों में पहुंचते हैं, तो यह पानी और जलजीवों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं।

ट्रंप को चेतावनी, हमें खत्म करने के चक्कर में कहीं आप ही न खत्म हो जाएं

प्रथम पृष्ठ से आगे

ईरानी सुरक्षा अधिकारी लारिजानी ने ट्रंप को चेताया कि सतर्क रहें, हमें खत्म करने के चक्कर में कहीं आप ही न खत्म हो जाएं। हम अमेरिका की खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं।

रायटर के अनुसार, इजरायल के यरूशलम व तेल अवीव में मंगलवार को ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। वहीं बहरीन की राजधानी मनामा में एक आवासीय इमारत पर हुए ईरानी हमले में 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। सऊदी अरब ने दो ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जबकि कुवैत ने छह ड्रोन नष्ट करने की जानकारी दी। यूएई के रुवैस औद्योगिक क्षेत्र में ड्रोन हमले के बाद एक तेल डिपो में आग लग गई। कतर ने ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी है। उधर, इराक के किर्कुक शहर में ईरान समर्थित पापुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के ठिकाने पर हुए हवाई हमले में कम से कम पांच लड़ाकों की मौत हो गई। न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा, युद्ध के पहले दस दिनों में सेना ने ईरान के 5000 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। एपी के अनुसार, इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में कई सैन्य व अनुसंधान ठिकानों पर हवाई हमले किए।

रूस की मध्यस्थता की पेशकश, ट्रंप ने पुतिन से की बात : रूस ने इस संकट के समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश दोहराई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद भी रूस की मध्यस्थता की पेशकश कायम है। ज्ञात हो, पुतिन ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा सकता है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से तेल और गैस आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा था कि रूस ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए सहयोग करने को तैयार है। युद्ध की तीव्रता के बावजूद वैश्विक बाजारों में निवेशकों को उम्मीद है कि ट्रंप जल्द ही इस संघर्ष को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के चलते सोमवार को तेज उछाल के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में कुछ गिरावट आई और एशियाई व यूरोपीय शेयर बाजारों में भी सुधार देखने को मिला। एएनआइ के अनुसार, अमेरिका रूस के तेल पर लगे प्रतिबंधों को आंशिक रूप से कम करने पर भी विचार कर रहा है, ताकि बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके और कीमतों को स्थिर किया जा सके।

युद्ध का असर, महंगा हुआ हवाई सफर

- तेल की आग से जल उठा एविएशन सेक्टर, दुनिया भर में बढ़े टिकट के दाम
- पश्चिम एशिया के आसमान में तनाव, लंबा रास्ता और महंगा सफर झेलेंगे यात्री

नई दिल्ली, रायटर: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब लोगों की जेब पर साफ दिखने लगा है। क्रूड आयल(कच्चे तेल) व जेट फ्यूल की कीमतों में आई भारी उछाल के कारण दुनिया की कई बड़ी विमानन कंपनियों ने मंगलवार को टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। आस्ट्रेलिया की कंपनी क्वांटास, स्कैंडिनेविया की एसएएस व एयर न्यूजीलैंड ने किराए में वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा, युद्ध से पहले जेट फ्यूल की कीमत 85-90 डालर प्रति बैरल थी, जो अब 150 से 200 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसे में उड़ान संचालन पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है। एयर न्यूजीलैंड ने तो अनिश्चितता के कारण 2026 के वित्तीय अनुमान तक को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

टिकट क्यों हो रहे महंगे: जेट फ्यूल एयरलाइंस का मजदूरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है। आम तौर पर कुल परिचालन लागत का 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। तेल की कीमत बढ़ते ही एयरलाइंस के लिए किराया बढ़ाना मजबूरी बन जाता है। एयर न्यूजीलैंड ने घरेलू उड़ानों में 10 न्यूजीलैंड डालर, छोटी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 व लंबी दूरी की उड़ानों में 90 डालर तक किराया बढ़ाया है। वहीं, हांगकांग एयरलाइंस ने ईंधन सरचार्ज में 35.2 प्रतिशत तक वृद्धि की है।

युद्ध से आसमान में भी अफरातफरी : पश्चिम एशिया के आसमान में भी तनाव का असर दिखने लगा है। उड़ानों को संभावित मिसाइल हमलों से बचाने के लिए कई विमानों को रास्ता बदलना पड़ रहा है। मंगलवार को दुबई पहुंचने वाले कुछ विमानों को संभावित खतरे के कारण कुछ समय के लिए हवा में ही रोकना पड़ा। इस बीच कई एयरलाइंस पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रही हैं। क्वांटास ने कहा है कि वह अपनी कुछ उड़ानों की क्षमता यूरोप की ओर शिफ्ट करने के विकल्प तलाश रही है।

कुछ उड़ानें रद्द भी: ब्रिटिश एयरवेज ने अनिश्चित हालात के कारण अबू धाबी के लिए अपनी सर्दियों की उड़ानें समय से पहले बंद करने का फैसला किया है।

भारतीय एयरलाइंस पर ईरान जंग की दोहरी मार

- पाकिस्तान के एयरस्पेस प्रतिबंध के बाद पश्चिम एशिया के तनाव ने बढ़ाई मुश्किल
- लंबे रूट, ज्यादा ईंधन और रद्द उड़ानें, एयरलाइंस की लागत पर भारी दबाव

नई दिल्ली, रायटर : ईरान युद्ध ने भारतीय एयरलाइंस की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहले से ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध झेल रही भारतीय कंपनियों को अब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण उड़ानों के रास्ते बदलने पड़ रहे हैं। इससे यात्रा का समय बढ़ रहा है और ईंधन खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। विमानन डेटा कंपनी सिरीयम के अनुसार गत 10 दिनों में पश्चिम एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका के लिए तय 1,230 उड़ानों में से करीब 64 प्रतिशत उड़ानें संचालित नहीं हो सकीं। ज्ञात हो, पाक ने गत वर्ष अप्रैल में सैन्य तनाव के बाद भारतीय विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने पर रोक लगा दी थी। अब ईरान युद्ध के कारण पश्चिम एशिया के आसमान में भी जोखिम बढ़ गया है।

लंबा रास्ता, बढ़ती लागत : ब्रोकरेज कंपनी एसएसबीसी का कहना है कि मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव भारतीय एयरलाइंस की लागत व मुनाफे पर बोझ डाल सकता है। प्रभावित क्षेत्रों में यदि सात दिन तक उड़ानें रद रहती हैं तो एयरलाइंस के वार्षिक कर-पूर्व लाभ में 1.2 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।

इंडिगो को खास चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप के लिए लंबी दूरी की उड़ानों में वह नार्स अटलांटिक एयरवेज से लीज पर लिए गए बोइंग विमानों का प्रयोग करती है। इन विमानों पर यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी की सलाह लागू होती है, जिसमें ईरान, इराक, इजरायल, कुवैत, लेबनान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से बचने को कहा गया है। इस कारण इंडिगो को कई उड़ानों के लिए अफ्रीका के रास्ते लंबा मार्ग अपनाना पड़ रहा है, जिससे कुछ मामलों में यात्रा समय दो घंटे तक बढ़ गया है। हाल ही में दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की एक उड़ान को हवाई क्षेत्र की अनुमति न मिलने के कारण 13 घंटे बाद वापस दिल्ली लौटना पड़ा, जबकि लंदन से मुंबई आ रही एक अन्य उड़ान को काहिरा की ओर मोड़ना पड़ा।

प्रतीकात्मक

एयर इंडिया की भी बढ़ीं चुनौतियां : एयर इंडिया ने भारत-यूरोप और अमेरिका मार्गों पर बढ़ती मांग को देखते हुए अगले सप्ताह 78 अतिरिक्त उड़ानें चलाने की घोषणा की है। हालांकि लंबे रास्तों के कारण कई उड़ानों का समय काफी बढ़ गया है। सोमवार को एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयार्क उड़ान को रोम में रोकना पड़ा, जिससे कुल यात्रा समय 22 घंटे हो गया। इससे पहले यही उड़ान इराक और तुर्किये के रास्ते करीब 17 घंटे में बिना रुके अमेरिका पहुंच जाती थी।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया पहले ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध के कारण हर साल करीब 60 करोड़ डालर के नुकसान का अनुमान जता चुकी है। अब ईरान युद्ध के कारण लंबा रास्ता और बढ़ता ईंधन खर्च भारतीय एयरलाइंस पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल सकता है।

अप्रैल तक चलने वाली कई सेवाएं अब साल के अंत तक रद्द कर दी गई हैं।

शेयर बाजार में हल्की राहत: मंगलवार को तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट के बाद एयरलाइन कंपनियों के शेयरों में सुधार दिखा। यूरोप में कई एयरलाइन कंपनियों के शेयर चार से सात प्रतिशत तक बढ़े। अमेरिका की कुछ बड़ी एयरलाइंस के शेयर शुरुआती कारोबार में दो से चार प्रतिशत नीचे रहे।

हवाई रास्ते भी हो रहे कम : युद्ध के कारण ईंधन ही नहीं, बल्कि हवाई रास्तों की उपलब्धता भी कम होती जा रही है। पहले यूक्रेन युद्ध के कारण कई एयरलाइंस रूसी हवाई क्षेत्र से बचकर लंबा रास्ता तय कर रही थीं। अब पश्चिम एशिया में युद्ध ने विकल्प और सीमित कर दिए हैं। विशेषज्ञों का कहना है, संघर्ष लंबा चला तो दुनिया भर में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है। आने वाले महीनों में यात्रियों को टिकट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं और कई लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सीट मिलना भी मुश्किल हो सकता है।

ईरान पर हमले के पहले 48 घंटे में अमेरिका ने झोंके 5.6 अरब डालर के हथियार

- सीमित भंडार वाले उन्नत हथियारों की तेज खपत पर अमेरिकी कांग्रेस में चिंता
- इस हफ्ते संसद में आ सकता है दसियों अरब डालर का पूरक रक्षा बजट प्रस्ताव

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान के शुरुआती चरण में अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियारों का प्रयोग किया। हमले के पहले 48 घंटों में ही अमेरिका ने करीब 5.6 अरब डालर के हथियार व गोला-बारूद खर्च कर दिए। इससे अमेरिका के सबसे उन्नत हथियारों के भंडार के तेजी से घटने पर अफसरों में चिंता बढ़ गई है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनुमान सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष रखा गया। इसके बाद ट्रंप प्रशासन के उस दावे पर बहस तेज हो गई है जिसमें कहा गया था कि ईरान के खिलाफ अभियान अमेरिकी सेना की युद्ध-तैयारी या हथियार भंडार को जल्दी प्रभावित नहीं करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अत्याधुनिक मिसाइलों, लंबी दूरी के मारक हथियारों व अन्य उच्च तकनीकी आयुधों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों की उपलब्धता सीमित होती है और इन्हें तैयार करने में भी लंबा समय लगता है।

ईरान युद्ध में अमेरिकी हथियार। इंटरनेट मीडिया

पूरक रक्षा बजट की तैयारी : ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को जारी रखने के लिए व्हाइट हाउस इस हफ्ते पूरक रक्षा बजट का प्रस्ताव रखने की तैयारी में है। अनुमान है कि इसकी राशि दसियों अरब डालर तक पहुंच सकती है।

हालांकि, पेंटागन ने राष्ट्रीय हथियार भंडार को लेकर किसी भी प्रकार की कमी की आशंका को खारिज किया है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा, रक्षा विभाग के पास इतनी क्षमता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए किसी भी स्थान और समय पर मिशन को पूरा कर सकता है। सेना के पास अभियान को जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन व हथियार हैं, जरूरत पड़ने पर उत्पादन व आपूर्ति प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकता है।

आगे लेजर-गाइडेड बमों के इस्तेमाल की तैयारी: यदि संघर्ष आगे बढ़कर ईरान के भीतर जमीनी इलाकों तक पहुंचता है तो अमेरिका-इजरायल लेजर-गाइडेड बमों का प्रयोग बढ़ा सकते हैं। ये बम सटीक लक्ष्यभेदी होते हैं और पारंपरिक बमों की तुलना में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। बड़ी संख्या में उपलब्ध होने से लंबे सैन्य अभियानों में इनका प्रयोग आसान होता है।

हमलों के विरोध में अधिकांश अमेरिकी

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद अमेरिका के भीतर ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्व के सैन्य संघर्षों के विपरीत, इस बार अमेरिकी जनता युद्ध के पक्ष में उतनी एकजुट नजर नहीं आ रही है। ताजा सर्वेक्षणों के अनुसार, अधिकांश अमेरिकी ईरान पर हमलों का विरोध कर रहे हैं। रायटर/इप्सोस और फाक्स न्यूज के सर्वे बताते हैं कि इस सैन्य कार्रवाई को मिलने वाला समर्थन 27 से 50 प्रतिशत के बीच झूल रहा है।

ऐतिहासिक युद्धों और वर्तमान स्थिति का अंतर : अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो द्वितीय विश्व युद्ध, कोरिया के साथ युद्ध या इराक के खिलाफ जंग की शुरुआत में अमेरिकी जनता का समर्थन अभूतपूर्व था। 'गैलप' के सर्वे के अनुसार, पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तब 97 प्रतिशत जनता सरकार के साथ थी। इसी तरह, अफगानिस्तान में सेना भेजने के फैसले को 92 प्रतिशत अमेरिकियों का समर्थन प्राप्त था। इराक पर सैन्य कार्रवाई पर 76 प्रतिशत अमेरिकियों ने मुहर लगाई थी।

राजनीतिक ध्रुवीकरण और 'रैली अराउंड द फ्लैग' का अंत : विशेषज्ञों का मानना है कि इस कम समर्थन के पीछे अमेरिका में बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह है। शोधकर्ता इसे 'रैली अराउंड द फ्लैग' प्रभाव कहते हैं, जहां संकट के समय विपक्षी दल के लोग भी राष्ट्रपति के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन पिछले 30 वर्षों में यह प्रभाव काफी कम हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू बाम का कहना है कि डेमोक्रेट्स अब ट्रंप के पीछे एकजुट होने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं, '"जहां तक राष्ट्रपति के अपने आधार का सवाल है, उनके समर्थक यह मानते हैं कि उन्होंने ट्रंप को युद्धों से बाहर निकलने के लिए चुना था, न कि नए युद्ध शुरू करने के लिए।"' इतिहास गवाह है कि वियतनाम युद्ध की शुरुआत में 60 प्रतिशत लोग इसके समर्थन में थे, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ने के साथ ही 1969 तक बहुमत इसे 'गलती' मानने लगा था। आज स्थिति यह है कि राजनीति अब "देश की सीमा" पर आकर नहीं रुकती; वह सैन्य फैसलों के साथ भी गहराई से जुड़ गई है।

बांग्लादेश में संकट, भारत ने भेजा 5000 टन डीजल

- भारत से पाइपलाइन के जरिये भेजा डीजल, चीन से 27,000 टन की खेप चटगांव पहुंची
- बांग्लादेश सरकार ने ईंधन राशनिंग लागू की, कई विश्वविद्यालय अस्थायी तौर पर बंद

ढाका में मंगलवार को पेट्रोल पंप पर लगी कतारें। रायटर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण तेल आपूर्ति बाधित होने से बांग्लादेश में डीजल व ऊर्जा संकट गहराने लगा है। हालात संभालने के लिए भारत व चीन ने बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू की है, जिससे फिलहाल देश की लगभग एक महीने की जरूरत पूरी हो सकेगी।

रायटर के अनुसार, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिये पांच हजार टन डीजल बांग्लादेश भेजा गया है। चीनी कंपनी पेट्रोचाइना की 27 हजार टन डीजल की खेप सोमवार को चटगांव पहुंच गई। वैश्विक ऊर्जा व्यापारी विटोल का 28 हजार टन ईंधन लेकर टैंकर बंदरगाह के बाहर खड़ा है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कारपोरेशन के चेयरमैन रेजानुर रहमान ने कहा,भारत से समझौते के तहत बांग्लादेश को हर साल 1,80,000 टन डीजल मिलता है। वहीं, बांग्लादेश सरकार ने वाहनों के लिए ईंधन राशनिंग लागू कर दी है, डीजल बिक्री पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। कई विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरत का लगभग 95 प्रतिशत आयात करता है।

रिवर्स इंजीनियरिंग का चेन रिएक्शन, बदल गया युद्ध का मैदान

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग हो या रूस- यूक्रेन युद्ध। इनमें मिसाइलों के साथ दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला दूसरा हथियार ड्रोन है। ईरान का शाहेद ड्रोन इसमें प्रमुख है। ईरान ने अमेरिकी तकनीक को कापी करके यह आत्मघाती हमलावर ड्रोन तैयार किया और अब इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही कर रहा है। इस रिवर्स इंजीनियरिंग का जवाब अमेरिका अपने अंदाज में दे रहा है, आइये जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी...

ईरान का रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा

अमेरिकी ड्रोन पकड़ने के कुछ महीनों बाद ईरानी अधिकारियों ने इसकी तस्वीरें दिखाईं और घोषणा की कि वे इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ईरान ने कहा कि वह ड्रोन के डिजाइन का विश्लेषण करेगा और इस विमान के स्वदेशी संस्करण तैयार करेगा। समय के साथ, ईरानी मीडिया ने कई ऐसे ड्रोनों के विकास की खबरें दीं, जिनके बारे में कहा गया कि वे सेंटिनल पर ही आधारित हैं। इनमें शाहेद-171, सिमार्ग और साएघेह शामिल थे। ये दोनों ही फ्लाइंग-विंग ड्रोन हैं, जो देखने में आरक्यू-170 जैसे लगते हैं। बाद में ईरानी अधिकारियों ने बताया कि साएघेह चार प्रेसिजन गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है।

शाहेद ड्रोन का उभार

आज ईरान के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले ड्रोन में से एक है शाहेद-136। यह एक तिकोना लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। बड़े सर्विलांस ड्रोन के उलट ये सिस्टम काफी सस्ते होते हैं। इनका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में ईरान-समर्थित गुटों ने किया है और यूक्रेन- युद्ध में रूस भी इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रहा है।

ईरानी डिजाइन से ही ईरान पर हमला

अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के शाहेद-136 से प्रेरित एक नया आत्मघाती ड्रोन लुकास तैनात करना शुरू कर दिया है। यह एक कम लागत वाला मानवरहित हमलावर ड्रोन है, जो देखने में शाहेद 136 जैसा लगता है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के कमांडर, एडमिरल ब्रैड कूपर का कहना है कि यह एक असली ईरानी ड्रोन का डिजाइन है। हमने इसे कब्जे में लिया, इसके अंदर के पुर्जे निकाल लिए, इसे अमेरिका वापस भेजा और इस पर छोटा सा मेड इन अमेरिका का लेबल लगा दिया। अब हम इसी से ईरानियों पर हमला कर रहे हैं।

सर्विलांस ड्रोन सेंटिनल

2007 में अमेरिका ने अपनी वायुसेना में स्टेल्थ सर्विलांस ड्रोन शामिल किया। इसका नाम था आरक्यू 170 सेंटिनल। लाकहिड मार्टिन ने इसे बनाया था। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल हवाई निगरानी और जासूसी के लिए कर रही थी। ड्रोन को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में किसी की नजर में आए बिना घुसने, तथा टोही तस्वीरें और सिग्नल इंटेलिजेंस जुटाने के लिए डिजाइन किया गया था।

बेस पर नहीं लौटा सेंटिनल

एक दिसंबर,2011 को सेंटिनल ने एक दिन कंधार एयरफील्ड से मिशन के लिए उड़ान भरी लेकिन वापस बेस पर लौटने के बजाए ड्रोन ने ईरान में लैंड किया। यहीं से रिवर्स इंजीनियरिंग और तकनीक की कापी करने का एक चक्र शुरू हुआ है, जिसने दुनिया में आज के ड्रोन युद्ध के तौर तरीकों को आकार दिया।

ईरान के कब्जे में आया सेंटिनल

ईरान ने 4 दिसंबर, 2011 को बताया कि उसके सशस्त्र बलों ने एक स्टेल्थ टोही ड्रोन को अपने कब्जे में लिया है। यह ड्रोन ईरानी क्षेत्र में काफी अंदर आ गया था। ईरान ने दावा किया कि ड्रोन लाकहिड मार्टिन द्वारा बनाया गया आरक्यू 170सेंटिनल है और इसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए आपरेट कर रही थी। इसके बाद अमेरिका ने भी स्वीकार किया कि उसका एक ड्रोन ईरानी सीमा के नजदीक खो गया है।

लादेन को मारने में भी हुआ स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल

2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराने वाली रेड से पहले सीआइए ने पाकिस्तान के एबटाबाद के ऊपर बार-बार गुप्त निगरानी उड़ानें भरने के लिए आरक्यू-170 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यहीं पर अल-कायदा का मुखिया ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। रेड वाली रात को भी स्टेल्थ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ड्रोन ने वीडियो फुटेज मुहैया कराया, जिसे राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों ने रियल-टाइम में देखा।

कम कीमत में प्रभावी हथियार

शाहेद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने की एक वजह इनकी कम कीमत भी है। जहां एमक्यू-9 रीपर जैसे एडवांस्ड ड्रोन की कीमत लगभग 1.6 करोड़ डालर तक है,वहीं शाहेद जैसे छोटे हमलावर ड्रोन की कीमत इसके मुकाबले काफी कम है। शाहेद-136 के डिजाइन को बड़े पैमाने पर कापी किया गया और कापी का यह चक्र अब विपरीत दिशा में चल रहा है।

जागरण रिसर्च

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
बुधवार 11 मार्च, 2026
12
www.jagran.com

मुझे नहीं पता आगे कि जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी। अब आपका सपना पूरा हो गया है। काश आप मेरे पास होते। हर छोटी बड़ी खुशी में आपको बहुत मिस करूंगा पापा।
— रिंकु सिंह, भारतीय क्रिकेटर

आइजीपीएल 2026 के आकर्षण का केंद्र होंगे भुल्लर

चंडीगढ़, प्रेट्र: मौजूदा चैंपियन गगनजीत भुल्लर 11 से 13 मार्च तक होने वाले इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आइजीपीएल) के पहले चरण में आकर्षण का केंद्र होंगे। इसमें कई अन्य शीर्ष खिलाड़ी भी भाग लेंगे। भुल्लर ने 2025 में आइजीपीएल में खिताब जीता था और इस बार उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाह टिकी रहेगी। एशियाई टूर में 11 जीत के साथ भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे भुल्लर के अलावा इस प्रतियोगिता में पुखराज सिंह गिल भी भाग लेंगे।

टी-20 से ज्यादा वनडे खेलेंगे बुमराह

वनडे विश्व कप 2027 के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत के कार्यभार प्रबंधन पर किया जाएगा फोकस

नई दिल्ली, प्रेट्र: टी-20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारतीय टीम की जीत में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रही थी। उन्होंने अपने सटीक और घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिसके चलते विपक्षी टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। बुमराह के इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक हैं। अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) उनके कार्यभार यानी वर्कलोड को लेकर विशेष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, ताकि आने वाले वर्षों में उनकी फिटनेस और प्रदर्शन दोनों बरकरार रह सकें।

सूत्रों के अनुसार, भारतीय तेज आक्रमण की अगुआई करने वाले बुमराह अगले लगभग डेढ़ साल में टी-20 अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय सीरीज की तुलना में ज्यादा वनडे मुकाबले खेल सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए उनकी तैयारियों को सही दिशा में बनाए रखना है। इसी कारण अक्टूबर-नवंबर 2027 तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों को अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता दी जा सकती है। हालांकि, इस दौरान द्विपक्षीय सीरीज का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। इसी अवधि में जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में भी क्रिकेट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं। वहीं, जानकारी यह भी सामने आई है कि बुमराह समेत कई वरिष्ठ भारतीय खिलाड़ी 2028 में लास एंजेलिस में होने वाले ओलिंपिक में खेलने के इच्छुक हैं, जहां क्रिकेट को टी-20 प्रारूप में शामिल किया जाएगा। इसके बावजूद 2027 वनडे विश्व कप तक सीमित ओवरों के क्रिकेट में बुमराह का मुख्य ध्यान वनडे प्रारूप पर ही रहेगा।

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ● फाइल फोटो, प्रेट्र

टी-20 विश्व कप में की घातक गेंदबाजी

टी-20 विश्व कप में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की थी। उन्होंने आठ मैचों में 6.21 की किफायती इकोनामी रेट से कुल 14 विकेट हासिल किए थे। इस दौरान वह भारत के वरुण चक्रवर्ती (14) के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

डब्ल्यूटीसी के मैच अहम

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के मुकाबले बुमराह के लिए बेहद अहम हैं। इन मैचों में उनका खेलना लगभग तय माना जा रहा है। उनके कार्यभार प्रबंधन की रणनीति 2023-2026 के दौर जैसी हो सकती है, जब उन्होंने एक भी वनडे मैच नहीं खेला था। वनडे विश्व कप फाइनल के बाद से बुमराह अब तक कुल 42 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, जिनमें 21 टेस्ट और 21 टी-20 मुकाबले शामिल हैं।

अगला लक्ष्य ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतना: सूर्य

मुंबई: भारत की टी-20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनका अगला लक्ष्य देश के लिए ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। टी-20 विश्व कप जीतने के बाद मुंबई के देवनार स्थित अपने घर लौटने पर पत्रकारों से बातचीत में सूर्यकुमार ने कहा कि हमारे पास अच्छा मोमेंटम है। अब हमारा लक्ष्य 2028 ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि उसी वर्ष टी-20 विश्व कप भी खेला जाएगा और उसे जीतकर भारतीय टीम हैटट्रिक पूरी करना चाहेगी। सूर्यकुमार ने कहा कि उसी साल (2028) टी-20 विश्व कप भी होगा। अगर हम उसे भी जीत लेते हैं तो हमारी खिताबों की हैटट्रिक पूरी हो जाएगी। सूर्यकुमार ने कहा कि भारत को विश्व कप जिताने वाले कप्तानों की विशिष्ट सूची में शामिल होना उनके लिए बेहद खास अनुभव है। उन्होंने कहा कि वह टीम और देश की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व कप जिताने वाले कप्तानों के विशिष्ट समूह में शामिल होना मेरे लिए बहुत खास एहसास है। मैं उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। सूर्यकुमार ने 2024 में भारत में खेले गए टी-20 विश्व कप की जीत को भी याद करते हुए कहा कि अपने ही देश में ट्राफी जीतना बेहद खास अनुभव था।

आइपीएल के बाद वनडे विश्व कप की तैयारियां होंगी तेज: भारतीय टीम की 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियां इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के दो महीने लंबे और व्यस्त सत्र के बाद तेज होने की संभावना है।

खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ व अन्य सहयोगियों में राशि होगी वितरित

विश्व विजेता टीम पर होगी धनवर्षा बीसीसीआइ देगा 131 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआइ) ने मंगलवार को तीसरी बार पुरुष टी-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार राशि 15 खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ में वितरित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का बड़ा हिस्सा मिलना तय है, जबकि सहयोगी स्टाफ के सदस्यों के लिए पुरस्कार राशि उनके पद के अनुसार तय की जाएगी। यह राशि 2024 में रोहित शर्मा की अगुआई वाली चैंपियन टीम को दिए गए 125 करोड़ रुपये से छह करोड़ रुपये अधिक है। बीसीसीआइ सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ के सदस्यों और चयनकर्ताओं को एक बार फिर बधाई देता है और भविष्य में उनकी निरंतर सफलता की कामना करता है। भारत ने रविवार को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर यह ट्राफी अपने नाम की थी। वह टी-20 विश्व कप में खिताब का सफल बचाव करने वाली पहली टीम है। भारतीय टीम ने तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता। यह कारनामा करने वाली वह पहली टीम बन गई।

बीसीसीआइ पुरस्कार समारोह 15 मार्च को: बीसीसीआइ 15 मार्च को नई दिल्ली में अपने वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें पिछले एक वर्ष में आइसीसी ट्राफी जीतने वाली भारत की पांच टीमों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी बीसीसीआइ सचिव देवजीत सैकिया ने दी। 'नमन' नामक इस पुरस्कार समारोह में विभिन्न आयु वर्गों और प्रारूपों में आइसीसी प्रतियोगिताओं में भारत की हालिया सफलताओं का जश्न मनाया जाएगा।

एयरपोर्ट से निकलते सूर्य ● वीडियो वीब

संजू सैमसन ● आइएएनएस

सूर्य-इशान का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत

नई दिल्ली: भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज इशान किशन मंगलवार को टी-20 विश्व कप में अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने के बाद अपने होमटाउन पटना पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहीं भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का भी भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान इशान ने कहा कि टीम भविष्य में और खिताब जीतने के लिए पक्का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भारतीस टीम जीत गई है, यह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत अच्छा पल है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी खेलते रहेंगे और जीतेंगे। इशान ने फाइनल में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। वहीं, सूर्या ने कहा कि उनका फिलहाल प्लान यह है कि वह घर लौटेंगे, कुछ अच्छा खाएंगे और आने वाली चुनौतियों पर ध्यान देने से पहले जरूरी आराम करेंगे।

पटना एयरपोर्ट पर इशान किशन ● प्रेट्र

खेल डायरी

अर्शदीप पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना

दुबई, प्रेट्र: भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर अहमदाबाद में आइसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप के फाइनल के दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल पर आक्रामक और अनुचित तरीके से गेंद फेंकने के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा अर्शदीप के अनुशासनात्मक रिकार्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है, जो 24 महीने के समय में उनका पहला अपराध है। आइसीसी ने कहा कि अर्शदीप को आइसीसी की खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से संबंधित आचार संहिता के नियम 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में अर्शदीप ने गेंद फेंकने के बाद शाट खेलने पर गेंद को रोका और फिर आक्रामक तरीके से फेंका, जो मिशेल के पैड पर लगी।

क्रिकेटर कुलदीप यादव मसूरी में करेंगे शादी

जागरण संवाददाता, मसूरी: क्रिकेटर कुलदीप यादव मसूरी के लाइब्रेरी बाजार स्थित होटल सेवाय में परिणय सूत्र में बंधेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, होटल में 13 और 14 मार्च के लिए सभी रूम बुक किए गए हैं। 14 मार्च को शादी करने के बाद 15 मार्च को वह वापसी करेंगे। मेहमानों के लिए होटल जेडब्ल्यू मैरिएट में भी कमरे बुक हैं। शादी में भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, आइसीसी चेयरमैन जय शाह सहित भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों के आने की उम्मीद है।

गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजी कोच बने हेडन

अहमदाबाद, प्रेट्र: गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के आगामी सत्र के लिए आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रारंभिक बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। दो बार के वनडे विश्व कप विजेता और अपने जमाने के सबसे प्रभावशाली प्रारंभिक बल्लेबाजों में से एक हेडन का अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार रहा है। उन्हें टी-20 में बल्लेबाजी का व्यापक अनुभव है। हेडन ने सभी प्रारूपों में 273 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 15,000 से अधिक रन बनाए और आइसीसी के कई टूर्नामेंट में जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मनु भाकर 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष पर

नई दिल्ली, प्रेट्र: ओलिंपियन मनु भाकर मंगलवार को संपन्न राष्ट्रीय चयन ट्रायल तीन (ग्रुप ए) की महिला 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में शीर्ष पर रहीं। ट्रायल दो की विजेता संयम दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि ईशा सिंह ने आठ निशानेबाजों के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल किया। अंतिम क्वालीफायर के रूप में फाइनल में जगह बनाने वाली मनु ने दूसरी सीरीज के अंत में बढ़त बनाई और फिर 246.1 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने संयम को 4.2 अंक से पछाड़ा जिन्होंने 241.9 अंक जुटाए। एशियाई चैंपियनशिप की स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता ईशा 220.6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। ईशा ने क्वालीफिकेशन में 580 अंक के साथ शीर्ष पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।

स्वीटी और चानू चोटिल, अस्पताल में भर्ती

सिडनी, प्रेट्र: भारतीय फुटबाल टीम की कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चानू मंगलवार को एएफसी महिला एशियाई कप के अपने आखिरी ग्रुप लीग मैच में चीनी ताइपे से 1-3 से हार के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस हार के साथ ही प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट में भारत का सफर समाप्त हो गया। टीम इससे पहले अपने पहले दो मैचों में वियतनाम और जापान से हार चुकी थी। मैच के दौरान चोट लगने के बाद एलांगबाम पंथोई चानू और स्वीटी देवी नगनबाम को अस्पताल ले जाया गया है। दोनों आपस में टकराकर घायल हो गईं।

कई पहलू पर काम करने की जरूरत: लक्ष्य

लक्ष्य सेन

शेखर झा ● जागरण

नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन हाल के समय में अपने प्रदर्शन को लेकर संघर्ष करते नजर आए हैं। हालांकि, इसके बावजूद उन्होंने आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। खिताबी मुकाबले में उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आखिरकार उन्हें चीनी ताइपे के लिन चुन-यी के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा और खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया।

24 वर्षीय लक्ष्य ने फाइनल में हार के बाद कहा कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई कठिन मुकाबले जीते और लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचे। ट्राफी जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन अंत में परिणाम उनके पक्ष में नहीं जा सका। लक्ष्य ने कहा कि अभी भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर उन्हें काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह सप्ताह उनके लिए अच्छा रहा, लेकिन भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण भी था। फाइनल तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है, लेकिन खिताब नहीं जीत पाने की निराशा भी स्वाभाविक है। लक्ष्य का मानना है कि आज के दौर में बैडमिंटन मुकाबले बेहद तेज और शारीरिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। इसके साथ ही उम्र बढ़ने के साथ खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और रिकवरी को लेकर अधिक सतर्क रहना पड़ता है।

लक्ष्य सेन को आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में चीनी ताइपे खिलाड़ी से मिली थी शिकस्त

22 साल बाद अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा भारत

कोलकाता, प्रेट्र: दिल्ली को 2027 में होने वाले एशिया कप तीरंदाजी के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है, जिससे भारत 22 साल में पहली बार किसी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। विश्व तीरंदाजी एशिया की यहां हुई बैठक में मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार को इसकी घोषणा की गई। भारत ने पिछली बार 2005 में दिल्ली में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के रूप में पिछली बार किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। विश्व तीरंदाजी एशिया के अध्यक्ष काजी राजिब उद्दीन अहमद चपोल और भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर अंतिम फैसला किया।

विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में हिस्सा लेंगे 257 खिलाड़ी

नई दिल्ली एएनआइ: नई दिल्ली 2026 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आगाज बुधवार से होगा। 13 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत सहित आठ देशों के 257 एथलीट अपना दम दिखाएंगे। पैरालंपिक कमेटी आफ इंडिया (पीसीआइ) ने मंगलवार को इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

ग्रैंड प्रिक्स में भारत, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया, मिस्र और न्यूट्रल पैरा एथलीट शामिल होंगे। इसमें भारत ट्रैक और फील्ड इवेंट में लगभग 219 एथलीटों का सबसे बड़ा ग्रुप उतारेगा, जिसमें पैरालिंपिक चैंपियन मरियप्पन थंगावेलु, सुमित अंतिल

नई दिल्ली में आज से होगा आगाज, भारत सहित आठ देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे दम

और प्रवीण कुमार सहित भारत के अन्य बड़े पैरा एथलीट शामिल होंगे। पैरालिंपिक कमेटी आफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ग्लोबल पैरा स्पोर्ट में भारत के बढ़ते रुतबे को दिखाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स के अध्यक्ष पाल फिट्जगेराल्ड ने कहा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स पहले ग्रैंड प्रिक्स के एक साल बाद और विश्व चैंपियनशिप होस्ट करने के पांच महीने बाद नई दिल्ली लौटने के लिए उत्साहित है।

भारतीय फुटबाल को संवारने में जुटा एक 'ईरानी हिंदुस्तानी'

विशाल श्रेष्ठ ● जागरण

कोलकाता: 80 के दशक में ईरान से 18 साल का एक नौजवान क्लब फुटबाल खेलने भारत आया। यहां की परंपरा व कला-संस्कृति उसे इतनी रास आई कि यहीं बस गया और सारी उम्र भारतीय फुटबाल की सेवा में गुजार दी। आज 67 की उम्र में भी वे देश की फुटबाल प्रतिभाओं को निखारने में जुटे हैं। उनके हाथों तैयार ढेरों फुटबालर आज कई बड़े क्लबों के लिए खेल रहे हैं। ये हैं जमशीद नासिरी। पिछले तीन दशक से कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में रह रहे जमशीद देश के दो प्रमुख फुटबाल क्लब ईस्ट बंगाल व मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए खेल चुके हैं। भारत आने से पहले वे ईरान की अंडर-12, राज्य व राष्ट्रीय टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जमशीद भारत में विभिन्न टूर्नामेंटों में 100 गोल करने वाले पहले विदेशी फुटबालर हैं। एक समय वे देश के सबसे महंगे फुटबालरों में से एक थे। ईरान के खोर्रमशहर में जन्मे जमशीद ने कहा कि फुटबाल खेलने के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में गया। हर जगह मिले लोगों के अपार प्यार से मैं अभिभूत हो गया। भारत व ईरान की परंपरा व कला-संस्कृति एक जैसी हैं।

जमशीद को ईरान में रह रहे भाइयों की होती है चिंता

जमशीद ने कहा कि ईरान अब मेरा देश नहीं है लेकिन मेरे भाई वहां रहते हैं। युद्ध को लेकर उनकी चिंता होना स्वाभाविक है। मैंने उनकी खबर लेता रहता हूं। वे सकुशल हैं। मैं युद्ध को लेकर किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहता। बस यही कहूंगा कि लड़ाई बंद होनी चाहिए। यह किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में शांति व सद्भाव कायम होना चाहिए। इसी से दुनिया आगे बढ़ सकती है।

ईरान से आए जमशीद ने सारी उम्र भारतीय फुटबाल की सेवा में गुजार दी, कहा- बंद हो युद्ध, इससे नहीं निकल सकता किसी समस्या का समाधान

बेटे कियान के साथ जमशीद नासिरी ● फाइल फोटो

भारत को फुटबाल विश्वकप खेलते देखने की इच्छा

पिछले 37 वर्षों से कोचिंग करते आ रहे जमशीद को विश्वास है कि जैसे इटली-स्काटलैंड जैसे मुख्यतः फुटबाल खेलने वाले देशों ने हालिया संपन्न टी20 क्रिकेट विश्व कप खेला है, वैसे ही भारत भी एक दिन फुटबाल विश्वकप खेलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में फुटबाल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्हें ठीक से ग्रूम करने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय फुटबाल से जुड़े सबको साथ मिलकर काम करना होगा। जमशीद वर्तमान में फुटबाल क्लब कलकत्ता एफसी के हेड कोच हैं। परिवार में पत्नी सुजेन व दो बेटे जोशुआ व कियान हैं।

विंडीज-द. अफ्रीका टीम के लिए व्यावसायिक उड़ानों की बुकिंग

कोलकाता, प्रेट्र: आइसीसी ने भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए अलग-अलग व्यावसायिक उड़ानों में बुकिंग की है, क्योंकि कोलकाता से उड़ान भरने वाली उनकी चार्टर्ड उड़ान रद्द हो गई थी। जानकारी है कि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों की अलग-अलग व्यावसायिक विमान कंपनियों की उड़ान में बुकिंग की गई है। सभी की बुकिंग एक ही उड़ान में नहीं हो सकती, लेकिन आइसीसी ने व्यक्तिगत बुकिंग का ध्यान रखा है। आइसीसी चेयरमैन जय शाह ने खुद बात की है और खिलाड़ियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिलाया है।

जोकोविक प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

इंडियन वेल्स, रायटर: तीसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविक ने दूसरे सेट में हार झेलने के बावजूद अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्जेंडर कोवाचेविच को 6-4, 1-6, 6-4 से हराकर इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम-16 में जगह बना ली। इस जीत के साथ उनका मुकाबला मौजूदा चैंपियन जैक ड्रेपर से तय हो गया, जिन्होंने 19वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 6-1, 7-5 से हराया।

24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविक ने कैलिफोर्निया के इस टूर्नामेंट में रिकार्ड की बराबरी करते हुए पांच बार खिताब जीता है। वहीं, ब्रिटेन के जैक ड्रेपर ने पहला सेट आसानी से जीत लिया और दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की चुनौती को भी पार कर लिया। सीनियाकोवा ने किया उलटफेर: महिला वर्ग में कतेरीना सीनियाकोवा ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए गत चैंपियन मीरा एंड्रीवा को 4-6, 7-6(5), 6-3 से हराया। स्वियातेक ने मारिया सक्कारी को 6-3, 6-2 से हराया।

शाट लगाते हुए नोवाक जोकोविक ● प्रेट्र

एफए कप में सिटी-लिवरपूल की होगी भिड़ंत

लंदन, एपी: मैनचेस्टर सिटी एफए कप फुटबाल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल की मेजबानी करेगा, जबकि चेल्सी का सामना तीसरी श्रेणी की टीम पोर्ट वेल से होगा। सोमवार रात वेस्ट हैम की ब्रेंटफोर्ड पर पेनाल्टी शूटआउट में जीत के बाद टूर्नामेंट के अंतिम-8 के ड्रा घोषित कर दिए गए। शूटआउट में वेस्ट हैम के गोलकीपर अल्फोंस एरोला ने डैंगो औटारा के पेनेंका के शाट को शानदार तरीके से रोककर अपनी टीम की जीत पक्की की। वेस्ट हैम ने ब्रेंटफोर्ड को पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर एक दशक में पहली बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। निर्धारित समय और अतिरिक्त समय के बाद दोनों टीम 2-2 से बराबरी पर थीं। अब क्वार्टर फाइनल में वेस्ट हैम का सामना लीड्स से होगा।

पेनाल्टी शूटआउट में गोल रोकते वेस्ट हैम के गोलकीपर अल्फोंस एरोला ● रायटर

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

जीवनशैली

मोटापे के बोझ में दबता बचपन

डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की शुरुआत मोटापे से होती है और मोटापे की शुरुआत अगर बचपन में ही हो जाए, तो सेहतमंद जीवन दांव पर लग सकता है। बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए जागरूक होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्रियता भी अनिवार्य है। कितनी गंभीर है यह समस्या और कैसे होगा बचाव, बता रहे हैं ब्रह्मानंद मिश्र...

• फ्रीपिक

जीवनशैली से उपजा मोटापा ऐसा विकार है, जो भागदौड़, तनाव, अव्यवस्थित दिनचर्या और खराब खानपान के साथ अनियंत्रित होता जाता है। ऐसे में कोई बचपन से मोटापे का शिकार हो जाए, तो जवानी और बुढ़ापे में बीमारी की पटकथा पहले से ही तैयार हो जाती है। डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों के बढ़ते बोझ और हर साल इससे होने वाली लाखों मौतों के पीछे मोटापे की केंद्रीय भूमिका होती है। हाल में जारी 'वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस' के अनुसार, बच्चों में मोटापे के मामले में भारत अब चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2025 तक के अनुमानित आंकड़ों की मानें तो चार करोड़ से अधिक बच्चों का वजन (बाडी मास इंडेक्स) सामान्य से अधिक हो चुका है और लगभग डेढ़ करोड़ बच्चे मोटापाग्रस्त हैं।

बीमारियों के संभावित शिकार हैं दो करोड़ बच्चे: एटलस के अनुसार, 2040 तक भारत में दो करोड़ बच्चे मोटापाग्रस्त होंगे और 5.6 करोड़ बच्चों का बाडी मास इंडेक्स तय दायरे के बाहर जा चुका होगा यानी पांच से 19 वर्ष के बच्चों को अगर गैर संचारी रोगों से बचाना है, तो अभी से प्रयास बढ़ाना होगा। रिपोर्ट का ही अनुमान है कि 5.7 करोड़ बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों (उच्च ट्राइग्लिसिराइड) और 4.3 करोड़ बच्चों में हाइपरटेंशन के शुरुआती लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। इसका प्राथमिक कारण है 11-17 वर्ष के तीन चौथाई बच्चे पर्याप्त शारीरिक गतिविधियों से दूर हैं। ऐसे बच्चे शुगर वाले पेय और डिब्बाबंद भोजन के आदी भी हो चुके हैं। बच्चों को मोटापे से बचाना है तो स्वस्थ भोजन और शारीरिक सक्रियता दोनों के लिए तैयार होना होगा। ओबिसिटी एटलस को भारत के लिए भविष्य की एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। स्कूलों में हानिकारक पैकेटबंद भोजन, शुगर की अधिकता वाले बेवरेज को लेकर सख्त होने की जरूरत है।

दो तरह का होता है मोटापा: डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अत्यधिक और असंतुलित रूप से शरीर में वसा के जमाव को मोटापा कहा जाता है। इसे बाडी मास इंडेक्स (व्यक्ति के कुल वजन (किग्रा.) में लंबाई (वर्ग मी.) से भाग देकर प्राप्त होता है) में मापा जाता है। गत वर्ष लांसेट कमीशन ने मोटापे को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया- क्लीनिकल मोटापा और प्री-क्लीनिकल मोटापा। नई परिभाषा में वजन, लंबाई, कमर का घेरा, मांसपेशियों के द्रव्यमान और अन्य अंगों की कार्यक्षमता आदि को भी शामिल किया गया है।

क्लीनिकल मोटापा: इसमें डाक्टर सांस फूलने, घरघराहट, स्लीप एप्निया, उच्च ट्राइ ग्लिसिराइड, मेटाबोलिक समस्याएं, फैटी लिवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बदलाव को भी देखते हैं।

प्री-क्लीनिकल मोटापा: इसे मोटापा के बजाय अत्यधिक वजन मान सकते हैं यानी उससे पूर्व की अवस्था। ऐसे लोगों के शरीर में वसा का जमाव बढ़ जाता लेकिन इससे बीमारी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। शुरुआती तौर पर बचाव के कुछ जरूरी उपाय किए जा सकते हैं ताकि संभावित बीमारियों को रोका जा सके।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

किस तरह के हैं जोखिम

- टाइप-2 डायबिटीज
- उच्च कोलेस्ट्राल, हाइपरटेंशन और हार्ट की समस्या
- जोड़ों और हड्डियों का दर्द
- सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और स्लीप एप्निया
- आत्मविश्वास में कमी
- डिप्रेशन और एंग्जाइटी

बचाव के लिए क्या हैं उपाय

- बच्चों को पैकेटबंद भोजन के बजाय फल, सब्जियां और अनाज खिलाएं।
- अधिक मीठे स्नैक्स या ड्रिंक्स के बजाय प्राकृतिक भोजन दें।
- बाहर के बजाय बच्चों को घर में बना भोजन खिलाना चाहिए।
- साइकिलिंग, स्किपिंग, रनिंग जैसी एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें।
- बैठकर टीवी देखने या गेम खेलने के बजाय उन्हें एक्टिव रखें।
- बच्चों के सोने-जागने का समय तय करें और सोने से पहले इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों से दूर रखें।

बचपन में मोटापे के कारण

अस्वस्थ भोजन: उच्च कैलोरी वाले स्नैक्स, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड बच्चों में मोटापे का कारण बन रहे हैं। पोषणयुक्त और घर के बने भोजन को लेकर बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है।

सक्रियता की कमी: अधिक कैलोरी वाले आहार, खेलकूद में कमी नुकसानदेह साबित हो रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे पढ़ाई से लेकर मनोरंजन तक मोबाइल/लैपटाप पर करते हैं। जबकि कम से कम दो घंटे की खेलकूद जैसी एक्टिविटी जरूरी है।

अच्छी नींद का अभाव: सोने-जागने का समय तय नहीं होने और खराब नींद के चलते मेटाबोलिज्म प्रभावित होता है। इससे बच्चों को थकान लगती है, जिससे वे शारीरिक गतिविधियों से दूर भागते हैं।

आनुवंशिक और पारिवारिक कारण: कुछ बच्चों को आनुवंशिक कारणों से यह समस्या होती है। कुछ परिवारों में खानपान और दिनचर्या की अव्यवस्थित आदतों का असर बच्चों पर भी होता है, जिससे वे आसानी से मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं।

परिवार जागरूक और स्कूल बनें सहयोगी

डा. आशीष गौतम
प्रिंसिपल डायरेक्टर, रोबोटिक व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मैक्स हास्पिटल, नई दिल्ली

पांच से 19 वर्ष आयु के बच्चों में तेजी से मोटापा बढ़ने का मूल कारण यही है कि बीते 20 वर्षों में उनके खाने, खेलने और पालन-पोषण का तरीका बिल्कुल बदल गया है। आज लोग अत्यधिक प्रसंस्करित भोजन कर रहे हैं, जिसमें शुगर, नमक और नुकसानदेह वसा की अधिकता होती है। लोगों का चलना-फिरना कम हो गया है, बैठे रहने व स्क्रीन देखने में वे घंटों बिता देते हैं। बच्चे कैलोरी बर्न करने से अधिक ग्रहण कर रहे हैं। इस असंतुलन के चलते मोटापा बढ़ रहा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स और शुगर वाले पेय आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि स्वस्थ आहार के विकल्प कम हो गए हैं। बचपन से ही ऐसे भोजन की आदत लग जाने से जल्दी यह छूटती नहीं। ज्यादातर जगहों पर ताजे, सेहत वाले भोजन की उपलब्धता कम हो गई है। साथ ही तनाव, खराब नींद और परिवार में खराब दिनचर्या जैसे कारण भी मोटापे के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनेक स्तरों पर सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। परिवार में संतुलित भोजन, सीमित मीठे पेय पदार्थ, सोने की सही आदत और नियमित व्यायाम जैसे उपायों पर गौर करना होगा। स्कूलों में जंक फूड पर रोक और बच्चों के लिए शारीरिक सक्रियता की व्यवस्था करनी होगी। बच्चों को मोटापे से बचाना है तो परिवारों को जागरूक, स्कूलों को सहयोगी बनना होगा।

बच्चों के टिफिन में हो स्वस्थ भोजन

डा. दिव्या मलिक
सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, दिल्ली

बच्चों के लंच बाक्स में ऐसा भोजन हो, जो स्वाद के साथ पौष्टिक भी हो। चिप्स, बिस्किट, पैकेज्ड फूड में स्वाद तो है, लेकिन सेहत नहीं...

अगर टिफिन में कुछ टेस्टी खाने की चीजें न हों तो बच्चे टिफिन वापस ले आते हैं या फिर अधूरा ही छोड़ देते हैं। ऐसे में वे कैंटीन की जंक चीजों जैसे चिप्स, कुकीज, चाकलेट, बर्गर, केक आदि का रुख करते हैं। इससे न तो उनका पेट भरता है और न ही उन्हें संपूर्ण आहार मिलता है। नतीजा, वे कमजोर होने लगते हैं और मांओं को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चों का लंच बाक्स ऐसा होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिंस सब कुछ थोड़ी मात्रा में जरूर हो, क्योंकि उनका आधा दिन स्कूल में ही बीतता है। बच्चों को फल, पनीर, पराठे, सब्जियों से भरपूर रोल, पोहा, पुलाव या फिर इडली, उपमा आदि देना सही होता है।

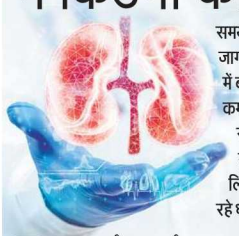

बच्चों की पसंद का टिफिन: बच्चों को पनीर, आलू या सब्जियों वाले पराठे दे सकते हैं, साथ में कोई चटनी भी। कभी कभार पनीर रोल, वेजिटेबल सैंडविच या घर में बनी टिक्की भी अच्छा विकल्प है, इनमें भरपूर प्रोटीन होता है। सूजी का उपमा या पोहा भी दे सकते हैं, इनमें सब्जियां डालने से फाइबर और विटामिंस की भरपाई हो जाती है। विविधता होने से उन्हें खाने में मजा आता है। इडली फ्राइ, ढोकला, अप्पम आदि आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। हर दिन टिफिन में प्रोटीन होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को ताकत और ऊर्जा चाहिए। कभी पनीर तो कभी दही से बनी कोई डिश, अंडा, चना, राजमा से बने आहार जरूर देने चाहिए।

विश्व किडनी दिवस (12 मार्च)

क्यों हो रही है कम उम्र में किडनी की समस्या

समय पर जांच का अभाव, जागरूकता की कमी और जीवनशैली में बरती जाने वाली लापरवाही से कम उम्र के लोगों में किडनी की समस्या बढ़ रही है। क्या है इसका मुख्य कारण और इससे बचाव के लिए दैनिक स्तर पर किन बातों का रहे ध्यान? आइए जानें...

डा. हिमांशु
विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलाजी, वीएमएमसी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

जब भूख लगी कुछ भी खा लिया, देर रात तक जगना, सिरदर्द या शरीर में होने वाले किसी भी दर्द से रोकथाम के लिए झटपट दर्दनिवारक दवाइयों का सेवन, दैनिक जीवन में सक्रियता का अभाव आदि, अनियंत्रित दिनचर्या के ये कुछ संकेत हैं जो संभव है आपके जीवन से भी गहरे जुड़े हों और आप भी किडनी की बीमारी के शिकार हो रहे हों। बता दें कि किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, यह आपको तब तक पता नहीं चलता, जब तक यह पचास प्रतिशत तक खराब न हो जाए। इसका मतलब है कि खराब होती किडनी के शुरुआती लक्षणों का पता करना कठिन होता है। अचानक एक दिन किडनी से जुड़ी कोई गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसे में किडनी की बीमारी अधिक बढ़ जाने पर ही लोग इसके उपचार के लिए चिकित्सक से संपर्क करते हैं। किडनी शरीर का एक ऐसा अंग है, जो जीवन भर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना होता है। स्वस्थ खानपान और जीवनशैली गत बीमारियों से दूर रहें, ताकि इस महत्वपूर्ण अंग पर अतिरिक्त भार न पड़े।

पथरी को अनदेखा न करें: पश्चिमी या विकसित देशों की तुलना में भारत में किडनी से जुड़ी बीमारी कम उम्र में ही होने लगती हैं। इसके कई कारणों में सबसे प्रमुख कारण हैं, उचित समय पर जांच का अभाव। समय पर जांच कराने से चिकित्सा शुरू हो जाती है और जीवनशैली में इसके अनुकूल खानपान और सजगता बढ़ा दी जाती है। युवाओं में कामकाज का बढ़ता टेंशन, नींद का अभाव, खानपान में जागरूकता की कमी से मोटापा की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इससे कम उम्र में ही हाइपरटेंशन (उच्च रक्त चाप) और मधुमेह बीमारी देखने में आ रही है। इन बीमारियों के कारण किडनी पर बुरा असर पड़ता है। डायबिटीज किडनी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण माना गया है। साथ ही पथरी की समस्या को भी लोग सामान्य मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। यह भी किडनी खराब होने का प्रमुख कारण है, इसलिए पथरी को अनदेखा नहीं करना चाहिए।

पथरी से बचाव के लिए शारीरिक सक्रियता बढ़ाएं। कसरत व प्रतिदिन टहलना सुनिश्चित करें। यदि जिम जा रहे हैं या शरीर को सुडौल बनाने के लिए स्टेरायड, प्रोटीन पाउडर, सप्लीमेंट भी अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो यह किडनी के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

बातचीत : सीमा झा

इन बातों का रहे ध्यान

- 30-35 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में एक बार पूरी स्वास्थ्य जांच करा लेनी चाहिए।
- शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे यूरिन गाढ़ा होगा और पथरी की आंशका रहेगी।
- स्वस्थ किडनी के लिए पर्याप्त पानी पिएं। यूरिन हल्का पीला व सफेद होना चाहिए।
- यूरिक एसिड बढ़ाने वाले खानपान जैसे रेड मीट, अल्कोहल, सी फूड्स से बचें।
- नमक का सेवन नियंत्रित करें। घर पर बने भोजन को प्राथमिकता दें।
- अधिक धूमपान व अल्कोहल के सेवन से किडनी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है।

बीमारी बढ़ने के संकेत

- पैरों और आंखों के आसपास सूजन आना
- रात में बार-बार यूरिन आना
- सामान्य कामकाज से भी थकान
- भूख कम लगना, तेजी से वजन गिरना आदि।

ग्लूकोमा जागरूकता सप्ताह

लाइलाज नहीं है ग्लूकोमा

डा. मोहिता शर्मा
वरिष्ठ नेत्र सर्जन व चेयर पर्सन, तिरुपति आई सेंटर, नोएडा

काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा को अनदेखा करना घातक हो सकता है। यह आंखों की रोशनी तक छीन लेने वाली बीमारी है। कैसे होता है ग्लूकोमा, क्या है इलाज, आइए जानें...

'ग्लूकोमा' आम 'मोतियाबिंद' नहीं है। इसमें आंखों की रोशनी धुंधली नहीं पड़ती बल्कि दृष्टि चली जाती है। समय पर पहचान हो जाए तो इसे रोकना संभव है।

कैसे होता है ग्लूकोमा: आंखों में एक तरफ से पानी भरता है और दूसरी ओर से निकलता है, जब यह प्रक्रिया बाधित होकर आई एंगल ब्लाक करने लगती है तो ग्लूकोमा की शुरुआत होती है। दरअसल, आंखों के अंदर मौजूद 'एक्वियस ह्यूमर' नामक तरल पदार्थ बाहर न निकलकर अंदर ही जमा होने लगता है। इससे आंखों की आप्टिक नर्व पर दबाव बढ़ता है और दृष्टि कम होने लगती है। उम्र बढ़ना, रक्तचाप, मधुमेह, आनुवंशिकता या चोट ग्लूकोमा का कारण बन सकती है।

लक्षण: शुरुआत में ग्लूकोमा के लक्षण विशेष रूप से दिखते नहीं हैं। कई लोगों को सिरदर्द, आंखों के सामने इंद्रधनुष जैसे रंग बनना या उल्टियां होने जैसी परेशानियां होती हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में तो आंखों में दर्द तक नहीं होता। जब साइड की नजर कमजोर होने लगती है तो ग्लूकोमा के लक्षण सामने आते हैं, फिर धीरे-धीरे रोशनी जाने लगती है।

ग्लूकोमा के प्रकार: ग्लूकोमा दो तरह के होते हैं। पहला, ओपन-एंगल ग्लूकोमा, जो भारत में अधिकांश लोगों को होता है, इसमें दृष्टि धीरे-धीरे जाती है, लेकिन दूसरा, एंगल-क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें बीमारी का पता चलते ही दृष्टि अचानक बाधिक होती है।

क्या है इलाज: ग्लूकोमा का इलाज संभव है। पहले नसों के दबाव की जांच होती है और ग्लूकोमा का पता लगाया जाता है। आंखों की हालत देखकर डाक्टर आई ड्राप देते हैं, जिसे सारी जिंदगी लेना होता है। कई बार लोग लापरवाही के चलते इसे बीच में ही छोड़ देते हैं और ग्लूकोमा वापस आ जाता है।

किन विटामिंस का रखें खयाल: आंखों की रोशनी ठीक रखने के लिए विटामिन ए, सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही एंटी-आक्सीडेंट्स युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और ओमेगा थ्री फैटी एसिड भी लेना चाहिए।

ध्यान देने वाली बातें

- आंख का आपरेशन हुआ है, तो ग्लूकोमा होने की आशंका अधिक होती है।
- एक बार आई ड्राप शुरू होने पर सारी उम्र उसे लेना अनिवार्य होता है।
- जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी होती है।

बातचीत : सुमन अग्रवाल

आज का भविष्यफल: 11 मार्च, 2026 बुधवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।
आज का दिशाशूल: उत्तर
आज का पर्व एवं त्योहार: श्री शीतला अष्टमी
विशेष: गुरु मार्गी

कल 12 मार्च, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल: दक्षिण
विशेष: नवमी तिथि की वृद्धि
विक्रम संवत 2082 शके 1948 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष की नवमी 30 घंटे 13 मिनट तक, तत्पश्चात दशमी मूल नक्षत्र 24 घंटे 44 मिनट तक, तत्पश्चात पूर्वाआषाढ़ा नक्षत्र सिद्धि योग 09 घंटे 59 तक, तत्पश्चात व्यतिपात योग धनु में चंद्रमा।

मेष: पारिवारिक एवं आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जीवनसाथी के कारण चिंतित हो सकते हैं।
वृष: भाई-बहन, पड़ोसी या अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें।
मिथुन: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा।
कर्क: रिश्तों में निकटता आएगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
सिंह: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा।
कन्या: सुख में व्यवधान आ सकता है। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।
तुला: स्वास्थ्य में सुधार होगा। पुरुषार्थ सार्थक होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
वृश्चिक: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी।
धनु: पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक प्रगति होगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा।
मकर: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा।
कुंभ: संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। सम्मान में वृद्धि होगी।
मीन: रिश्तों में निकटता आएगी। मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। क्रोध में वृद्धि हो सकती है।

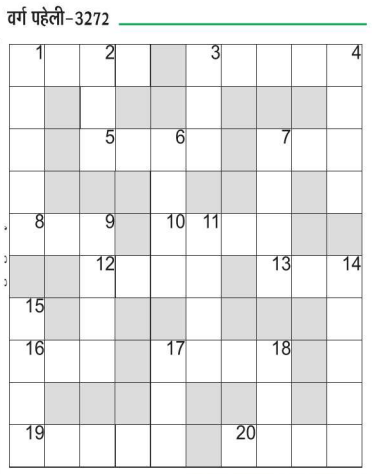

वर्ग पहेली-3272

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1. घुड़साल, घोड़ों के रहने की जगह (4)।
3. तमिल फिल्मों की एक अभिनेत्री (5)। 5. ईश्वर में अविश्वास (4)।
7. शब्द-शक्तियों के तीन भेदों में से एक (3)।
8. घोड़े के मुंह में लगाई जाने वाली बाग समेत छड़ (3)।
10. कम ताकत वाला, दुर्बल (4)।
12. इन्कार कर देना, मना करना (4)।
13. भय से कांपना (3)।
16. एक प्रकार का गीत (3)।
17. धातु के टुकड़े का बजना (4)।
19. सच्चा, विश्वसनीय (5)।
20. रसोई (4)।

ऊपर से नीचे :
1. आकाशबेल (5)।
2. निवास करना, रहना (3)।
3. विनय (3)।
4. राज्य के शासन का केंद्र (4)।
6. वेतन पर काम करने वाला (4)।
7. निष्प्रयोजन, बिना लाभ का (4)।
9. मन मुताबिक (4)।
11. मनाने की क्रिया (4)।
14. जिस घर में नाटक का अभिनय होता है (3,2)। 15. कविता, कवित्व (4)।
17. समाचार, संदेश (3)।
18 बेवजह, व्यर्थ (3)।

कल का हल

1 प	र	2 त	■	3 इ	न	का	4 र	■	5 स
■	■	6 ल	ड़	का	■	■	तौं	■	ह
7 अ	र	ब	■	8 ई	9 द	■	10 धी	11 र	ज
न	■	■	■	■	स्त	■	■	क्ष	■
म	■	12 अ	ना	13 मि	का	■	14 अ	क	15 थ
16 ना	17 या	ब	■	18 च	र	वा	हा	■	ल
■	च	■	■	ला	■	■	■	■	थ
19 वि	क	20 ल	■	21 ना	22 कु	■	23 वि	र	ल
फ	■	जा	■	■	24 म	र	ना	■	■
ल	■	25 नी	का	बि	ल	■	26 श	ला	का

सुडोकू-3272

3		5				7		8
		7	6		1	3		
1	8			3				6
	2			6				4
		1			3	8		9
	5		8				2	
7	4			1			8	3
		6	3		8	4		
9		8					5	1

कल का हल

1	2	3	7	6	5	8	4	9
4	5	6	2	8	9	7	1	3
7	8	9	4	1	3	2	5	6
9	7	2	3	4	6	1	8	5
3	6	1	8	5	2	4	9	7
5	4	8	1	9	7	3	6	2
6	3	4	5	7	1	9	2	8
2	1	5	9	3	8	6	7	4
8	9	7	6	2	4	5	3	1

राष्ट्रीय फलक

रानी दुर्गावती अभयारण्य बनेगा देश में चीतों का तीसरा घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर

देश में 17 सितंबर 2022 को शुरू किए चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है, बल्कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में यह आंकड़ा 50 पर पहुंच गया है। इन चार वर्षों के दौरान अफ्रीकी देशों से कुल 20 चीते लाए गए। वहीं, मंदसौर जिले में स्थित गांधीसागर अभयारण्य में तीन चीतों को शिफ्ट किया जा चुका है।

चीतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर ही पिछले दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने कहा गया था कि सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक चीतों की संख्या 50 पहुंचाने का है। इसके बाद अन्यत्र इनकी संख्या में वृद्धि की तैयारी की जाएगी, लेकिन बोत्सवाना से लाए गए नौ चीतों के अलावा पिछले 30 दिन में ही कूनो में 13 शावकों के जन्म से यहां चीतों की संख्या अचानक बढ़ गई है। ऐसे में, कूनो और गांधी सागर के बाद देश में रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) चीतों का तीसरा घर बनेगा। इसका क्षेत्र 1,197 वर्ग किलोमीटर है। मंगलवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को दी।

चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही बताया गया था कि 750 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला कूनो नेशनल पार्क 30 चीतों को बसाने के अनुकूल है। यहां शिकार कर उनके भोजन के लिए पर्याप्त वन्य जीव मौजूद हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रत्येक चीते को लगभग 50-100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। यह आकलन चीतों के दौड़ने की क्षमता और उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप किया गया है। प्रोजेक्ट शुरू होने के छह माह बाद ही चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए न सिर्फ कूनो में श्योपुर व शिवपुरी वन मंडल का भाग भी जोड़ा गया बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों को जोड़कर कारिडोर तैयार करने की कवायद भी की गई है।

कूनो में विचरण करते चीता शावक। फाइल फोटो

ऐसे बढ़ा चीतों का कुनबा

- कूनो में मौजूद सभी छह मादा चीता मां बन चुकी हैं। इनके द्वारा जन्मे कुल 33 शावकों में से कई वयस्क हो चुके हैं। केवल मंदसौर में बसी चीता धीरा ही मां नहीं बन सकी है।
- सबसे पहले मां बनी ज्वाला चीता का तीन बार प्रसव हो चुका है। उसके द्वारा जन्मे कुल 14 शावक में से एक मुखी वयस्क होकर पांच शावकों को जन्म भी दे चुकी है। ऐसे में, इस परिवार के ही कुल 15 चीता हो चुके हैं।
- इस वर्ष 30 दिनों के भीतर ही सात फरवरी को आशा ने पांच, 18 फरवरी को गामिनी ने तीन और नौ मार्च को ज्वाला ने पांच शावकों को जन्म दिया है।

कूनो में चीतों की वंशवृद्धि तेजी से हो रही है। शावकों के अलावा बोत्सवाना से लाए गए चीते अभी बाड़े में ही हैं। इन्हें भी समय-समय पर खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। चीतों को बाहर शिफ्ट करने को लेकर निर्णय चीता स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा।
– उत्तम कुमार शर्मा, निदेशक, चीता प्रोजेक्ट

छत्तीसगढ़ में अफसर की गर्भवती पत्नी से दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: रायपुर में एक अफसर की गर्भवती पत्नी को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित गोपाल गोयल को गिरफ्तार किया है, जो पुरानी गाड़ियों का कारोबार करता है। सिविल लाइन एसीपी रमाकांत साहू ने बताया कि आरोपित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म से संबंधित धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपित ने उसे अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान आरोपित ने उसका वीडियो भी बनाया। किसी तरह आरोपित के चंगुल से निकलकर पीड़िता सिविल लाइन थाना पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। एसीपी रमाकांत साहू के अनुसार, पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है।

बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक

जागरण संवाददाता, देहरादून

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने बैठक में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय किया है। बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में धामों में यात्रा पूर्व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने, ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का शिविर कार्यालय खोलने व धामों में निर्धारित दूरी तक मोबाइल प्रतिबंधित करने समेत अन्य प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। मालूम हो कि गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति पहले ही गैर सनातियों के धाम में प्रवेश पर रोक लगा चुकी हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे।

मंगलवार को श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में दून स्थित कार्यालय में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद यह आदेश पारित किए गए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को ध्यान में रखकर अहम निर्णय लिए गए हैं। गैर सनातनियों के बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला भी इसमें शामिल है। धाम में उन सभी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा जिनकी सनातन में आस्था नहीं है। बोर्ड के बदरीनाथ व केदारनाथ में गैर सनातियों के प्रवेश पर रोक लगाने के संबंध में पारित प्रस्ताव की जानकारी राज्य सरकार को भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष का गठन को स्वीकृति दे दी गई है। कोष के लिए राज्य सरकार से भी मदद ली जाएगी। मंदिर समिति का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्था करना है।

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

बुधवार, 11 मार्च, 2026

14

www.jagran.com

सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाला पहला गणराज्य बना लिथुआनिया

1990 में आज ही लिथुआनिया सोवियत संघ से स्वतंत्र होने की घोषणा करने वाला पहला गणराज्य बना था। साजुडिस सुधार आंदोलन और बाल्टिक वे प्रदर्शन के बाद उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम ने सोवियत संघ के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया।

जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा घटी

2011 में आज ही के दिन 9.0 तीव्रता के भूकंप व सुनामी के कारण जापान में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा घटी थी। रेडियोधर्मी रिसाव के कारण एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। इसे चेर्नोबिल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु आपदा माना जाता है।

कैंसर के इलाज को किफायती व सुलभ बनाने में डा. शांता ने दिया योगदान

डा. विश्वनाथन शांता का जन्म 1927 में आज ही चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में हुआ था। 1955 में एमडी की डिग्री हासिल कर अड्यार कैंसर संस्थान से जुड़ीं और 12 बेड वाले संस्थान को विश्व स्तरीय केंद्र में परिवर्तित किया। 1960 में यहां कैंसर के लिए भारत की पहली बाल चिकित्सा कैंसर इकाई की स्थापना की। 1980 से 1997 के बीच संस्थान के निदेशक के रूप में कार्य किया। यहां उन्होंने ऐसा तंत्र विकसित किया, जहां आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों का उच्च गुणवत्ता वाला इलाज निशुल्क या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता था। 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुईं।

सड़क हादसों में सिर को अधिक सुरक्षित रखेगा यह 'ड्यूल सेफ' हेडगियर

जागरण विशेष

खोपड़ी व दिमाग के बीच मौजूद तरल की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली से प्रेरित है इस हेलमेट का डिजाइन

नंदकिशोर भारद्वाज • जागरण

सोनीपत: दोपहिया वाहन चालकों की सड़क हादसों में होने वाली मौतों में बड़ा कारण सिर में लगने वाली चोट होती है। पारंपरिक हेलमेट कई बार चोट के प्रभाव को पूरी तरह कम नहीं कर पाते। ऐसे में 'ड्यूल सेफ' हेडगियर (हेलमेट) इस समस्या का बेहतर समाधान बन सकता है। आइआइटी गांधीनगर के शोधार्थी अरविंद सेठी द्वारा विकसित यह हेलमेट खोपड़ी व दिमाग के बीच मौजूद तरल की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली से प्रेरित है।

इस हेडगियर की खास बात यह है कि इसका डिजाइन मानव सिर की प्राकृतिक संरचना को आधार बना कर किया गया है। मानव शरीर में खोपड़ी और दिमाग के बीच एक तरल पदार्थ की परत होती है, जो किसी झटके के समय दिमाग को सीधे चोट लगने से बचाती है। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हेडगियर में दोहरी सुरक्षा प्रणाली विकसित की गई है। बाहरी खोल के साथ इसके अंदर एक विशेष प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाया गया है, जिसमें कई स्ट्रिप लगी हैं। दुर्घटना के समय यदि बाहरी खोल क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो अंदर की पूरी संरचना एक साथ नहीं टूटती, बल्कि जिस दिशा से झटका आता है, उसी दिशा की स्ट्रिप प्रभावित होती हैं। इससे सिर पर पड़ने वाला प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है और दिमाग को गंभीर चोट लगने की संभावना कम हो जाती है।

जहां तक इसके सुरक्षा परीक्षण की बात है, तो मल्टी डायरेक्टशनल इंपैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम की जांच में इसको 6.5 किलो भार के साथ 80 किमी की गति से अलग-अलग पांच दिशाओं से फेंककर जांच की गई, जिसमें ये खरा उतरा है। अब आइएसआइ सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया है। इसके बाद ये चार से छह माह में भारतीय बाजार में उपलब्ध हो जाएगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

2023 में देशभर में 1,68,491 लोगों की जान गई सड़क हादसों में

2030 तक सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है

- **66%** मौतें 18–45 वर्ष आयु के युवाओं की हुई
- **45%** मौतें दोपहिया वाहन सवारों की हुई
- **20%** मौतें पैदल चलने वालों की हुई
- **71.8%** दोपहिया सवारों की मौतें बिना हेलमेट के कारण

सामान्य हेलमेट जितनी ही कीमत, गडकरी के समक्ष प्रजेंटेशन

हेडगियर की कीमत बाजार में मिलने वाले सामान्य हेलमेट के आसपास ही रखने की कोशिश की गई है, ताकि सुरक्षा केवल महंगे उत्पाद तक सीमित न रह जाए। अरविंद ने बताया कि आम हेलमेट की तरह इसकी कीमत ढाई हजार रुपये रखी गई है। हालांकि, हाईटेक फीचर वाला पांच हजार रुपये तक में उपलब्ध होगा। अरविंद ने इस हेडगियर को 12 फरवरी को सोनीपत स्टार्टअप समिट में प्रदर्शित किया था। उन्होंने इसका प्रजेंटेशन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष भी किया था। इसके बाद मंत्रालय को इसको लेकर अनुदान के लिए विचार करने को निर्देश दिए गए।

अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रिटेन में मिला पेटेंट

अरविंद को अमेरिका, इंग्लैंड और ब्रिटेन में इसको लेकर पेटेंट मिल चुके हैं, जबकि चीन में पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह पहल इस बात का संकेत देती है कि हेलमेट की तकनीक में बदलाव और नवाचार से दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में नए रास्ते खुल सकते हैं। चीन में पेटेंट मिलते ही यह हेडगियर पूरे विश्व में बिक्री के लिए तैयार होगा।

सुरक्षा के साथ ही इस हेडगियर में हाईटेक फीचर भी

अरविंद ने बताया कि हेडगियर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जीपीएस ट्रैकर, लाक होल्डिंग अलार्म, साउंड मैपिंग और मल्टी चैनल कम्युनिकेशन जैसे हाईटेक फीचर हैं। दोपहिया की सवारी के दौरान हेडगियर से फोन काल रिसीविंग, दोनों सवारों की आपस में बातें करना, लाक की स्ट्रिप ढीली या न बांधने पर अलार्म जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। दो राइडर्स के हेडगियर को एक-दूसरे के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है।

शोधार्थी अरविंद सेठी

अच्छी क्वालिटी के हेलमेट नहीं होने से इसके निमार्ण का आया विचार

चंड़ीगढ़ के रहने वाले अरविंद सेठी ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई आइआइटी गांधीनगर से की है। पढ़ाई के दौरान से ही उन्हें बाइक चलाने का शौक है। वह कई साल तक कई देशों में रहे, वहां भी उन्होंने बाइक चलाई। इस दौरान उन्होंने देखा कि बाइक सवारों की सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। इसका बड़ा कारण हेलमेट न पहनने से सिर में चोट लगना होता है। दूसरा, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट नहीं होना भी था। ऐसे में उनके मन में एक बेहतर हेलमेट के निर्माण का विचार आया।

ड्यूल सेफ हेडगियर • जागरण

इधर-उधर

यहां सोने से भी ज्यादा महंगी है गाय की पित्त पथरी

पारंपरिक चिकित्सा में होता है पथरी का प्रयोग। इंटरनेट मीडिया

बीजिंग, एजेंसी: चीन में गाय की पित्त की पथरी की भी खूब मांग है। दरअसल यहां हजारों वर्षों से इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान में, चीन में स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं जिससे पित्त पथरी की मांग में वृद्धि हुई है। 2025 में गाय की पित्त पथरी की कीमत 5,800 डालर यानी लगभग पांच लाख रुपये प्रति औंस तक पहुंच गई, जो उस समय सोने से दोगुनी महंगी थी। चीनी शोधकर्ता कृत्रिम पित्त पथरी भी विकसित कर रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक पथरी को ही सर्वोत्तम माना जाता है।

देश में साढ़े पांच करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चे 'मायोपिया' से पीड़ित

अनूप कुमार सिंह • जागरण

- डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता उपयोग और आउटडोर गतिविधियों में कमी मानी जा रही बड़ी वजह
- समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में बन सकती है चुनौती: विशेषज्ञ

समय पर जांच है जरूरी

डाक्टरों का कहना है कि यदि मायोपिया का समय पर पता चल जाए तो चश्मे, कांटेक्ट लेंस या अन्य उपचार के माध्यम से दृष्टि को नियंत्रित किया जा सकता है। देर से पहचान होने पर समस्या बढ़ सकती है और गंभीर मामलों में रेटिना से जुड़ी जटिलताएं भी हो सकती हैं।

नई दिल्ली : स्कूली बच्चों के बीच आंखों की बीमारी मायोपिया (नजदीक की नजर का कमजोर होना) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, देश में 24.8 करोड़ स्कूली छात्रों में से करीब 23 प्रतिशत यानी 5.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी स्तर पर मायोपिया से प्रभावित हैं। राजधानी में यह संख्या छह लाख है।

इंडियन जर्नल आफ आप्थैल्मोलाजी और विभिन्न भारतीय नेत्र स्वास्थ्य अध्ययनों में भी स्कूली बच्चों में मायोपिया की बढ़ती दर को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बताया गया है। लंबे समय तक मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग, आनलाइन पढ़ाई का बढ़ता चलन और बच्चों की आउटडोर गतिविधियों में कमी इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), वर्ल्ड और वैश्विक नेत्र स्वास्थ्य रिपोर्टों में भी बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम व कम शारीरिक गतिविधियों को मायोपिया बढ़ने का प्रमुख जोखिम कारक बताया गया है। एम्स आरपी सेंटर के प्रो. डा. राजपाल ने चेताया कि यदि समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में यह एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। प्रो. राजपाल का कहना है कि लगातार नजदीक की चीजों को देखने, डिजिटल स्क्रीन पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने और प्राकृतिक रोशनी में कम समय बिताने से बच्चों की आंखों पर दबाव बढ़ रहा है। दिल्ली और उत्तर भारत के स्कूली बच्चों पर किए गए 'नार्थ इंडिया मायोपिया स्टडी' (नार्थ इंडिया मायोपिया अध्ययन) जो इंडियन जर्नल आफ आप्थैल्मोलाजी में प्रकाशित हुआ, में भी अधिक पढ़ाई का दबाव, स्क्रीन उपयोग और कम आउटडोर गतिविधियों को प्रमुख जोखिम कारकों में पाया गया है।

क्या होता है मायोपिया : मायोपिया दृष्टिदोष है, जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि नजदीक की चीजें साफ दिखाई देती हैं। यह समस्या तब होती है, जब आंख का आकार सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। नेत्र विज्ञान जर्नलों में प्रकाशित शोधों के अनुसार मायोपिया प्रायः छह से 14 वर्ष की आयु के बीच विकसित होना शुरू होता है। कम रोशनी में पढ़ाई, किताब या स्क्रीन को बहुत करीब से देखना और धूप में कम समय बिताना भी मायोपिया के जोखिम को बढ़ाते हैं। 2024 में प्रकाशित अध्ययन में छह से 12 वर्ष के बच्चों पर किए गए शोध में पाया गया कि अधिक स्क्रीन टाइम और कम आउटडोर गतिविधियों वाले बच्चों में मायोपिया की दर अधिक थी।

नकारात्मक लोग बढ़ाते हैं समय से पहले बुढ़ापा

अनुसंधान

अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय तनाव, आलोचना या परेशानी पैदा करते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए। नए अध्ययन के मुताबिक, ऐसे नकारात्मक लोग व्यक्ति को समय से पहले बूढ़ा बना सकते हैं। शोध में पाया गया कि सामाजिक दायरे में मौजूद ऐसे लोगों को, जिन्हें विज्ञानियों ने 'हैसलर' यानी जीवन को मुश्किल बनाने वाला व्यक्ति कहा है, हर अतिरिक्त हैसलर के साथ बुढ़ापा आने की रफ्तार लगभग 1.5 प्रतिशत तेज हो सकती है। इससे व्यक्ति की जैविक उम्र औसतन करीब नौ महीने ज्यादा हो सकती है। अध्ययन में सामने आया कि करीब 30 प्रतिशत प्रतिभागियों ने माना कि उनके करीबी सामाजिक दायरे में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके लिए लगातार तनाव का कारण बनता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि महिलाओं, रोजाना धूमपान करने वालों व जिनका बचपन कठिन रहा है, उनके सामाजिक नेटवर्क में ऐसे लोगों की मौजूदगी ज्यादा होती है। इसके लिए अमेरिका के इंडियाना राज्य के 2,345 लोगों के लार के नमूनों का विश्लेषण किया गया। विज्ञानियों ने डीएनए मेथिलेशन नामक प्रक्रिया का अध्ययन किया। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

मधुबाला की बायोपिक नहीं कर रही हैं अनीत पड्डा

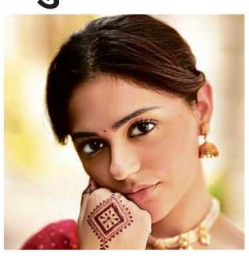

सैयारा से फिल्मों में पदार्पण किया है अनीत ने।

कई दिनों से अभिनेत्री मधुबाला पर बायोपिक बनने को लेकर खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा था कि सैयारा फिल्म की अभिनेत्री अनीत पड्डा इस फिल्म में मधुबाला की भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि, अब अनीत से जुड़े सूत्रों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है। उनके अनुसार अनीत को मधुबाला की बायोपिक में कास्ट करने की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इन खबरों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अनीत वैसे भी पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें सैयारा के लिए जो प्यार मिला था, उसे देखकर वह बेहद भावुक हैं और उसके बाद से ही वो सोच-समझकर काम कर रही हैं। आगामी दिनों में हारर कामेडी फिल्म शक्ति शालिनी में नजर आने वाली अनीत ने कहा था कि मैं अक्सर इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों का मेरे लिए प्यार देखकर हैरान रह जाती हूं। वो मेरे वीडियो को जो एडिट्स बनाते हैं, उन्हें देखकर मैं रो पड़ती हूं। उनकी मेहनत और प्यार देखकर बस यही उम्मीद करती हूं कि मैं उनके इस प्यार के साथ न्याय कर सकूं। मैं चीजों को बहुत गहराई से महसूस करती हूं, इसलिए लोगों का प्यार और उनका भरोसा, उनके लिए सही करने की जिम्मेदारी कई बार दबाव जैसा महसूस होती है। यह खूबसूरत अहसास है।

जब कपड़ों से परेशानी के बावजूद जीनत से शूट किया ओ दीवानों... गाना

कलाकारों का अपने प्रशंसकों के साथ दिलचस्प कहानियां साझा करने के लिए इंटरनेट मीडिया एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म बन चुका है। अभिनेत्री जीनत अमान भी इंटरनेट मीडिया पर खूब सक्रिय रहती हैं। हाल ही में उन्होंने 1979 में प्रदर्शित फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के गाने ओ दीवानों दिल संभालो.. से जुड़ी ऐसी ही कहानी साझा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर गाने का एक छोटा क्लिप साझा किया। इसे पसंदीदा गाना बताते हुए उन्होंने लिखा, 'इस सीक्वेंस (गाने) में तीन कपड़े बदले गए थे। जिनमें से सुनहरे ट्रैक-पैंट सेट, जिसे आप गाने में देख सकते हैं, उसने मुझे ज्यादा परेशान किया था। यह आउटफिट मेरे पूरे शरीर पर था, इसके साथ मेरी हेयर टीम ने मुझे एक छोटा पेजबाय (छोटे बालों वाली स्टाइल) विग देने का निर्णय लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं बहुत कांफिडेंट (आत्मविश्वासी) डांसर नहीं थी, क्योंकि उस समय मेरे पास कभी डांस की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी। फिर भी मैं मस्ती में झूम सकती थी। जिससे कई डायरेक्टर को लगा कि मुझसे मुश्किल कोरियोग्राफी निकलवाने में खुद को परेशान करने के बजाय मुझे मेरी मस्ती में झूमने पर छोड़ देना बेहतर है।'

इंटरनेट पर सक्रिय रहती हैं जीनत। इंस्टाग्राम - @thezeenataman

अक्षय खन्ना की सफलता पर बोले अनूप, मैंने उन्हें एक्टिंग सिखाई है

पहले फिल्म छावा और फिर धुरंधर की सफलता के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना पिछले साल खूब चर्चा में रहे। सिनेमा इंडस्ट्री से लेकर इंटरनेट मीडिया तक हर जगह उनकी चर्चा हुई। इस बीच उनके फिल्म दृश्यम 3 से अलग होने की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरी। अब 19 मार्च से प्रदर्शित होने जा रही फिल्म धुरंधर : द रिवेंज में अक्षय की फिर झलक देखने को मिलेगी। इस बीच अपहरण और सत्यमेव जयते 2 फिल्मों के अभिनेता अनूप सोनी ने दावा किया है कि उन्होंने अक्षय को अभिनय सिखाया है। अनूप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय के अभिनय सफर को लेकर कहा, 'अक्षय का सफर देखकर मुझे खुशी होती है। मैंने उन्हें एक्टिंग सिखाई है और उनके साथ कई क्लासेस की है। मैंने हमेशा उनकी स्पष्ट सोच की सराहना की है। उन्होंने पहले केंद्रीय भूमिकाओं का अनुभव लिया और अब वो जो काम कर रहे हैं, वो सच में कमाल का है। अब वह उस स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां अब वह फिल्मकारों के लिए ऐसे विश्वसनीय कलाकार बन गए हैं कि आप उन्हें किसी भी रोल में कास्ट कर सकते हैं। किसी भी कलाकार के लिए ऐसी चीजें बहुत कमाल की होती हैं।'

क्राइम पेट्रोल से अनूप ने बटोरी खूब लोकप्रियता। फाइल

...तो इन्हें काफी पिलाने की चाह है जैकी को

अपने किसी पसंदीदा को काफी पिलाने का मौका मिले, तो किसे पिलाएंगे, इस सवाल का जवाब तुरंत दे दिया अभिनेता व निर्माता जैकी भगनानी ने। दरअसल, जैकी और उनकी पत्नी व अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह साथ में अब बिजनेस की दुनिया में उतरे हैं और जिम, लान्ड्री और काफी के ब्रांड के साथ उन्होंने साझेदारी की है। मुंबई में मंगलवार को हुए इस प्रेस कान्फ्रेंस के मौके पर जब जैकी और रकुल से पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले, तो वह इंडस्ट्री से किसे काफी पिलाना चाहेंगे, इस पर जहां रकुल ने कहा वह पूरी इंडस्ट्री को काफी पिलाना चाहती हैं, वहीं जैकी ने झट से नाम लिया किंग खान शाह रुख खान का। वह कहते हैं कि सच कहूं, तो मेरा मन है कि मैं शाह रुख खान साहब को काफी पिलाऊं। मैं जानता हूं कि उन्हें काफी पीना बहुत पसंद है। आगे इस साझेदारी को लेकर जैकी ने कहा कि मैं और रकुल दोनों दी हमसफर हैं, पेशेवर जीवन हो या निजी, हम दोनों एक ही दिशा में सोचते हैं। हालांकि इस बिजनेस से जुड़ने का आइडिया इस बार मेरा था, पर बिजनेस के बजट से जुड़ी जिम्मेदारी रकुल की होगी, क्योंकि वह गणित में अच्छी हैं। जिम में निवेश करने को लेकर जैकी ने कहा कि मैंने 150 किलो का था। मैंने 75 किलो कम किए हैं। मैं उसके बाद से ही केवल फिटनेस की बात करता हूं। मुझे फिर से डेढ़ सौ किलो का नहीं होना है। मैं जानता हूं कि फिट होने का कोई शार्टकट रास्ता नहीं होता है।

जैकी और रकुल संग उतरे बिजनेस में। फाइल

चुप रहकर काम करना ही बेहतर: गोविंदा

कुछ बातें कम शब्दों में भी हो जाती हैं। अभिनेता गोविंदा ने भी कुछ ऐसा किया, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के उन पर लगाए आरोपों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है या फिर वह स्टारडम नहीं संभाल पा रहे थे। एक साक्षात्कार में गोविंदा ने कहा, 'यह सब सुनकर दुख होता है, लेकिन हर पुरुष घर में चुपचाप रहता है। मेरा मानना है कि तमीज इसी में है कि बिना किसी को दुख पहुंचाए काम करते रहिए। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन वफादारी कहीं और पड़ी होती है। उसके बारे में बात करके शर्मिंदा करूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आगे निकलिए टाप पर आइए। मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थीं कि दो-चार लोगों को दुनिया मान लोगे और वो धोखा देंगे, तो कहां जाओगे। इतने लोगों ने तुमसे प्यार किया है, क्या यह बेवकूफ हैं। यह पूरी दुनिया हमारी है, हम पूरी दुनिया के हैं। जब तक मैं किसी के लिए गलत नहीं कह देता है, या यह नहीं कह देता कि हां ऐसा है, कृपया तब तक सभी शांत रहें। यह फिल्म लाइन बुराई का शृंगार करती है। यहां बुराई पर चर्चा ज्यादा होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी की बेइज्जती से किसी की इज्जत का इजाफा हो जाए।' आगे गोविंदा ने काम को लेकर बताया कि वह तीन फिल्मों का निर्माण करने के साथ ही उसमें अभिनय भी कर रहे हैं।

@govinda_herono1

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

फिल्म दोस्ताना 2 से लक्ष्य बाहर!

साल 2008 में रिलीज हुई अभिषेक बच्चन और जान अब्राहम अभिनीत फिल्म दोस्ताना की सीक्वल पर लगता है नजर लग गई है। पहले इस फिल्म को कार्तिक आर्यन करने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से उनके फिल्म से हटने के बाद लक्ष्य फिल्म से जुड़ें। हालांकि अब खबरें हैं कि लक्ष्य भी इस फिल्म से दूरी बना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार भी दोस्ताना 2 में हो रही देरी का कारण कास्टिंग पूरा न हो पाना ही है। भले ही विक्रांत मेस्सी फिल्म में अब भी बने हुए हैं, लेकिन लक्ष्य इससे किनारा कर सकते हैं। हालांकि लक्ष्य ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि वह फिल्म छोड़ रहे हैं। वहीं विक्रांत पहले ही दोस्ताना 2 से जुड़ने को लेकर खुशी जता चुके हैं। लक्ष्य आगामी दिनों में चांद मेरा दिल फिल्म में नजर आएंगे।

@lakshya

सितारों को इंटरनेट मीडिया से बाहर आना चाहिए

पैन इंडिया स्तर पर किसी भी दक्षिण भारतीय फिल्म के अच्छी तरह से चल जाने के बाद जड़ों से जुड़े सिनेमा पर चर्चा शुरू हो जाती है। हालांकि कल हो ना हो व वेदा फिल्मों के निर्देशक निखिल आडवाणी ऐसा नहीं मानते। वह कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता है कि फिल्म का चलना या न चलना का जड़ों से जुड़े होने या ना होने पर निर्भर करता है। हम दक्षिण भारत की उन फिल्मों की बारे में तो बातें नहीं करते हैं, जो नहीं चली, हम बस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की न चलने वाली फिल्मों के बारे में बातें करते हैं। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि फ्लाप देने वाले फिल्मकार या कलाकार ने कोई नई गाड़ी या घर खरीदा है। अब तो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है। ऐसे में लोगों को गुस्सा आ जाता है कि ऐसी फिल्म देने के बाद भी हमारे ही पैसों से जाकर गाड़ी ले रहा है। मुझे लगता है कि सितारों को थोड़ा इंटरनेट मीडिया से भी बाहर आना चाहिए।'

@nikkhiladvani

आगे बढ़ी वरुण की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है'

पिछले दिनों 19 मार्च को रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर : द रिवेंज और यश अभिनीत फिल्म टाक्सिक के टकराव को लेकर काफी चर्चा रही। हालांकि, मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष की परिस्थितियों के कारण हाल ही में टाक्सिक की रिलीज तिथि बदलकर चार जून कर दी गई। उसके एक दिन बाद पांच जून को वरुण धवन अभिनीत फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज होने वाली थी। ऐसे में फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी ने उसी दिन टाक्सिक भी रिलीज किए जाने पर आश्चर्य जताया था। अब इस टकराव से बचते हुए है जवानी तो इश्क होना है को एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है। यानी अब यह फिल्म एक सप्ताह बाद 12 जून को प्रदर्शित होगी। इसकी आधिकारिक घोषणा के साथ जारी बयान में रमेश ने कहा, 'हमारी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है असल में पांच जून को रिलीज होने वाली थी, यह तारीख हमने कई महीने पहले बताई थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें लगा कि अपनी रिलीज को आगे बढ़ाना ज्यादा सही होगा। हमारा यकीन है कि फिल्म निर्माता एक ही तारीख पर बेवजह मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वह अच्छा होता है। इसी एकता की भावना से हमने है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज को 12 जून करने का निर्णय लिया है।' बता दें कि वरुण की उनके पिता और फिल्मकार डेविड धवन के साथ यह चौथी फिल्म है।

@varundvn

JOIN OUR PAID SERVICE – 2026

Daily PDF Access | Editorial Bonus | Almost All Editions

ENGLISH NEWSPAPERS

The Hindu, Indian Express, Hindustan Times, Business Line, Business standard, The Live Mint, Times of India, Telegraph, New Indian Express, Asian Age, Statesman, Tribune, Pioneer, Financial Express, The Economic Times, Mid-Day, Deccan Chronicle, Employment News, Free Press Journal, Hans India, Deccan Herald, Lokmat Times, Mirror, Telangana Today

HINDI NEWSPAPERS

दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, बिज़नेस स्टैण्डर्ड, राजस्थान पत्रिका, हरी भूमि, लोकसत्ता , पायनियर , दैनिक ट्रिब्यून , द हिन्दू, राष्ट्रीय सहारा , नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, जनसत्ता, देशबंधू, प्रभात खबर, दैनिक नवज्योति, आईनेक्स्ट लाइव, लोकमत, नव भारत, नई दुनिया

🎁 Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

🎁 Bonus Included :

- The Hindu Analysis
- Editorial Complation
- The Hundu in Hindi

All in One English. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~129~~ ₹69**
(⭐ Popular)	**6 Month = ~~449~~ ₹269**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~699~~ ₹449**

Special Offer

All in One Hindi. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~99~~ ₹59**
(⭐Popular)	**6 Month = ~~399~~ ₹259**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~599~~ ₹399**

Special Offer

All Major Hindi & English Newspapers - 2026

✍️ UPSC Essensial ePaper

The Hindu, BL, IE,NIE. Telegram

(Starter)	**1 Month = ~~99~~ ₹49**
(⭐ Popular)	**6 Month = ~~399~~ ₹249**
(👑 Best Value)	**1 Year = ~~599~~ ₹389**

Special Offer

You will Get

- The Hindu
- Business Line
- Indian Express
- New Indian Express
- Editorial Complation
- The Hindu Analysis

You Get All Editions of These Premium Newspapers

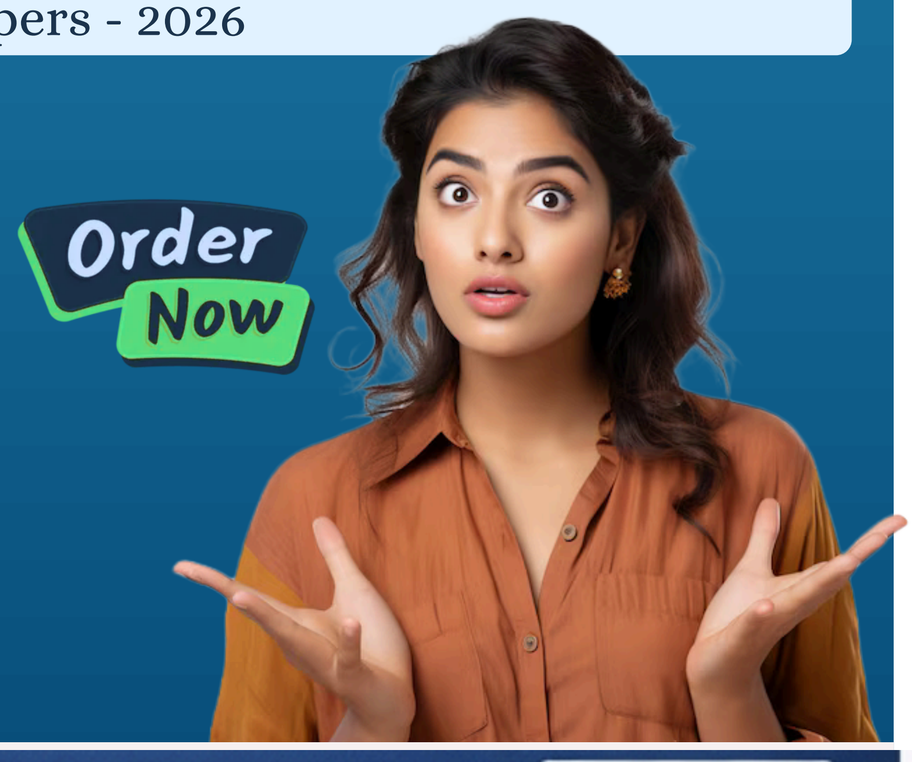

LIMITED TIME OFFER

Telegram Access Available

→ CLICK HERE & JOIN NOW